चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 14 मार्च–20 मार्च 2016 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

बाज़ीगरी या धोखाधड़ी

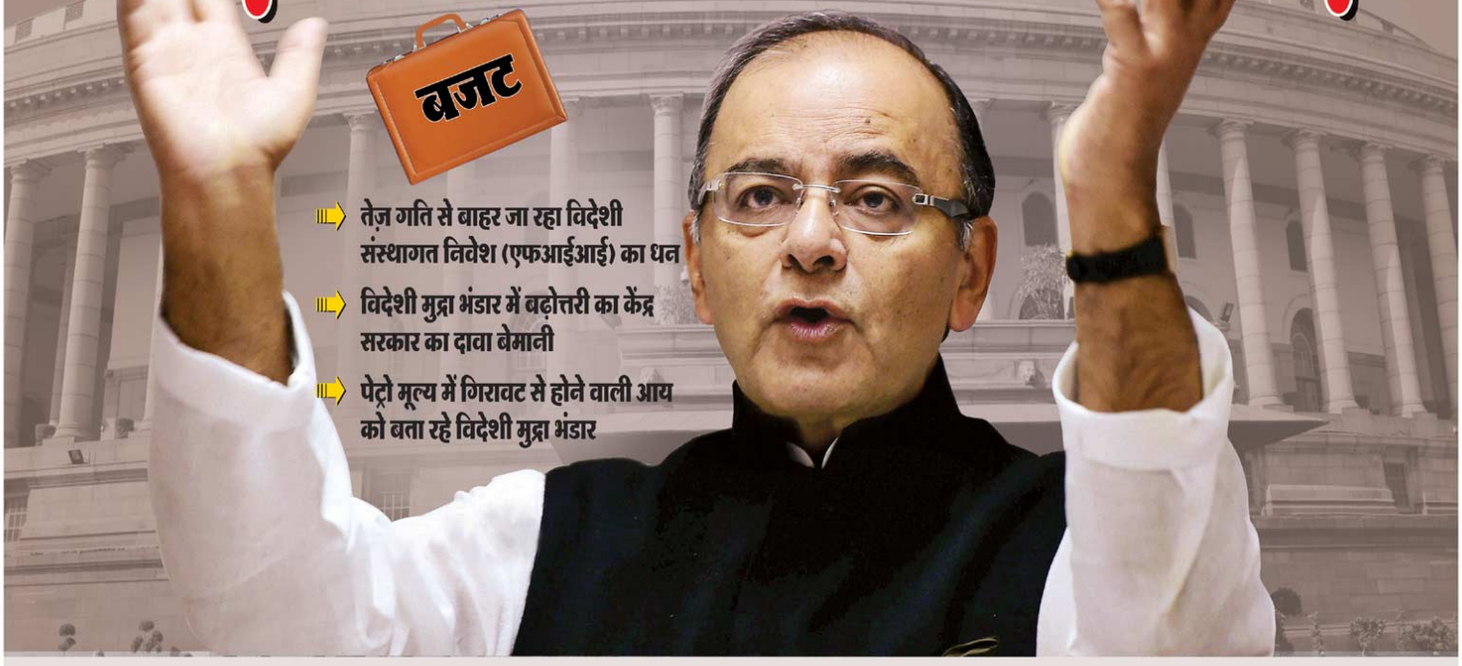

- तेज़ गति से बाहर जा रहा विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) का धन
- विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोत्तरी का केंद्र सरकार का दावा बेमानी
- पेट्रो मूल्य में गिरावट से होने वाली आय को बता रहे विदेशी मुद्रा भंडार

एस. एन. विशाल

केंद्रीय बजट आंकड़ों की बाजीगरी है या धोखाधड़ी, इसे समझने के लिए कुछ अंदरूनी जानकारियां हासिल करें और बजट की गहराई से समीक्षा करें तो इसे लेकर इस्तेमाल हो रहे दोनों जुमले सही साबित होते हैं. हम बजट के विस्तार में जाएं उसके पहले यह जान लें कि देश में जमा विदेशी पूंजी बड़ी तेज गति से बाहर जा रही है, जबकि केंद्र सरकार यह कह रही है कि विदेशी मुद्रा कोष में इजाफा हो रहा है. विदेशी मुद्रा कोष में बढ़ोत्तरी का दावा करने वाली केंद्र सरकार कहीं पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार गिर रही कीमतों को विदेशी मुद्रा कोष में बढ़ोत्तरी दिखाने का इंटरप्रेटेशन तो नहीं कर रही! क्योंकि तथ्य यह है कि भारत के कुछ बड़े राष्ट्रीयकृत बैंकों की मिलीभगत से कुछ बड़ी कंपनियां देश से विदेशी मुद्रा निकाल कर विदेशों में भेज रही हैं. लेकिन देश के आर्थिक नीति-नियंताओं को इसका तनिक भी भान नहीं है.

वैसे तो बजट हमेशा से आंकड़ों की जादूगरी ही रहा है. कम से कम आम आदमी के लिए यह एक ऐसा जटिल विषय रहा है, जिसे समझना आसान काम नहीं है. आम बजट 2016-17 के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि यह गांव-गरीबों का बजट है. खेती-किसानी का बजट है. आम आदमी का बजट है. यह भी दावा हो रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर है. लेकिन, क्या सचमुच यह सब ऐसा ही है, जैसा देखा और दिखाया जा रहा है? क्या सचमुच इस बजट से किसानों का भला होने वाला है? क्या यह बजट देश की अर्थव्यवस्था के बेहतर स्वास्थ्य को दर्शाता है? इन्हीं मुद्दों की हम आगे पड़ताल करेंगे.

हम देश में विदेशी निवेश के आंकड़ों पर नज़र डालें तो वहां कोई उत्साहजनक दृश्य नहीं दिखाई देता. सबसे पहले इस आंकड़े पर एक नजर डालिए. फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आंकड़े असलियत में क्या कहते हैं-

वर्ष	इक्विटी	ऋण	कुल
2010-11	1,10,121	36,317	1,46,438
2011-12	43,738	49,988	93,726
2012-13	1,40,033	28,334	1,68,367
2013-14	79,709	-28,060	51,649
2014-15	1,11,333	1,66,127	2,77,461
2015-16	-35,315	-2,528	-37,843

इस सूची से साफ़-साफ़ दिख रहा है कि विदेशी पूंजी के आंतरिक प्रवाह में बड़ी कमी आई है और जितनी पूंजी देश में आ नहीं रही, उससे ज्यादा देश के बाहर जा रही है. इस आंकड़े को ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) भारत में जब पैसा लगाता है तो वह दो क्षेत्रों में पैसा लगाता है. एक तो इक्विटी और दूसरा ऋण के क्षेत्र में. इक्विटी में जो पैसा लगता है, वह पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है और फिर वहां से वह पैसा विभिन्न कंपनियों में लगता है. इस सब से देश भर में एक आर्थिक वातावरण तैयार होता है. विदेशी संस्थागत निवेशक किसी भी देश में पैसा तभी लगाता है, जब उसे उम्मीद हो कि आने वाले सालों में फायदा मिलने वाला है. 2010 से ले कर 2014 तक भारत में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खूब सारा पैसा लगाया. लेकिन उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि 2015-16 में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इक्विटी समेत ऋण क्षेत्र से भरपूर पैसा निकाला और अपने देश वापस ले गए. 2015-16 के आंकड़ों के मुताबिक इक्विटी में से 35315 करोड़ रुपये और ऋण सेक्टर से 2528 करोड़ रुपये की निकासी हुई है. इस साल में कुल 37843 करोड़ रुपये विदेशी संस्थागत निवेशक भारत से निकाल कर ले गए हैं. गौरतलब है कि विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई और एफडीआई अर्थात विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दो अलग-अलग रास्ते हैं. एफडीआई के बढ़ने की बात भले ही की जा रही हो लेकिन विदेशी संस्थागत निवेश बड़ी मात्रा में कम हुआ है. सूत्रों के मुताबिक भारत की ही एक कम्पनी (कोलकाता आधारित) ने बजट आने के ठीक पहले करीब 500 करोड़ रुपये भारत से निकाल कर दुबई और सिंगापुर भेज दिए. इसमें एक बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक की संदेहास्पद भूमिका रही. जबकि उस बैंक के साथ-साथ रिजर्व बैंक और विजिलेंस को भी इस बारे में पहले ही इत्तिला कर दी गई थी. इसका सीधा अर्थ है कि विदेशी निवेशकों का भारत की अर्थव्यवस्था से भरोसा उठा है. जहां तक विदेशी मुद्रा कोष बढ़ने की बात है तो उसमें भी आंकड़ों की बाजीगरी की गई मालूम पड़ती है. ऐसा इसलिए, क्योंकि पिछले दो सालों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में भारी कमी आई है. जाहिर है, इससे हमें पेट्रोल खरीदने के लिए कम विदेशी मुद्रा देनी पड़ी है. इससे हमारा विदेशी मुद्रा का रिजर्व निश्चित तौर पर बढ़ा होगा. यदि हम समग्र रूप से विदेशी मुद्रा भंडार को देखना चाहते हैं तो हमें इसके लिए एफआईआई के निवेश की सच्चाई को भी देखना होगा.

सभी बजटों की तरह इस बजट में भी गुण-दोष की व्याख्या की जा सकती है, जो अलग-अलग सोच के अनुसार अतिवादी विरोध या समर्थन की ओर जा सकती है. इस संदर्भ में उल्लेखनीय बात यह है कि मोदी सरकार का प्रत्येक बजट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई दशकों के बाद (1984 के चुनावों के बाद) केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और अब यह कहना मुश्किल है कि दोबारा इस तरह बहुमत की सरकार फिर बन पाएगी या नहीं. पूर्ण बहुमत के कारण वित्त मंत्री अरुण जेटली के समक्ष यह विवशता नहीं थी कि वह बजट को लेकर विभिन्न सहयोगी दलों की मांगों और जरूरतों के अनुसार संतुलन बिठाते. उन्हें तो बजट को सिर्फ निचले सदन यानी लोकसभा से ही पास कराना था, जहां वर्तमान सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त है. लिहाजा, सरकार के पास इस बात का पूरा मौका था कि वह देशहित और नागरिकों के हित में सटीक और सकारात्मक कदम उठाती. परन्तु बजट में ऐसा कोई नया विज़न नहीं है जो इस बहुमत का सही इस्तेमाल करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हो. अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने के बजाय सिर्फ पुराने ढर्रों को बरकरार रख कर केंद्र सरकार ने इस सुनहरे मौके को गंवा दिया.

इस बजट को किसानों का बजट कहा जा रहा है. अब, सवाल उठता है कि यह वर्तमान सरकार की समझ का नतीजा है या मजबूरी का? सुरसा के मुंह की तरह बढ़ते एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स) पर नज़र डालते ही स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि उद्योग धंधे, निर्माण इकाइयां बंद हो रही हैं और व्यापारिक गतिविधियों के लिए निराशाजनक माहौल है. इसके साथ वर्ष 2015-16 के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों ने निवेश बढ़ाने के बजाय 37843 करोड़ रुपये निकाल लिए. किसी भी अन्य

(शेष पृष्ठ 2 पर)

बैंकों से कर्ज लेकर भाग गए उद्योगपति

BHUSHAN	भूषण स्टील 40,000 करोड़	विनसम डायमंड एंड ज्वेलरी 3,200 करोड़	
ESSAR	एस्सार स्टील 30,000 करोड़	इलेक्ट्रोथर्म इंडिया 2,600 करोड़	ELECTROTHERM
ABG SHIPYARD LIMITED	एबीजी शिपयार्ड 11,000 करोड़	ज़ूम डेवलपर 1,810 करोड़	ZOOM
BHARATI SHIPYARD LIMITED	भारती शिपयार्ड 8,000 करोड़	स्टर्लिंग बायोटेक 1,732 करोड़	STERLING BIOTECH
KINGFISHER AIRLINES	किंगफ़िशर एयरलाइन 7,000 करोड़	एस कुमार्स नेशनवाइड 1,692 करोड़	SKNL
THE LEELA	होटल लीला 4,500 करोड़	सूर्य विनायक इंडस्ट्रीज लि. 1,446 करोड़	Surya Vinayak Industries Ltd

जाट और ग़ैर-जाट में बंटा हरियाणा | P-3

जिसे अदालत ने देशद्रोह नहीं माना... | P-5

बांगाली मानुषेर विरोधी आछे एई बजट | P-6

बाज़ीगरी या धोखाधड़ी

आयकर व प्रोविडेंट फंड के प्रमुख बिंदु

- पांच लाख रुपये की आमदनी पर कर छूट 2,000 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये.
- मकान किराया भत्ता पर कर छूट 24,000 रुपये से बढ़कर 60,000 रुपये.
- 50 लाख रुपये तक का घर ख़रीदने पर 50 हज़ार रुपये तक की छूट.
- एनपीएस के तहत मिली रकम का 40 प्रतिशत हिस्सा अब टैक्स के दायरे से बाहर होगा, पहले एनपीएस की पूरी रकम टैक्स दायरे में थी.
- ईपीएफ़ निकालते समय अब यह राशि पहले की तरह टैक्स के दायरे से बाहर नहीं होगी, बल्कि सिर्फ़ 40 प्रतिशत राशि पर ही टैक्स छूट मिलेगी (15 हज़ार रुपये या उससे कम वेतन पाने वालों पर ये शर्तें लागू नहीं होंगी).
- मान्यताप्राप्त भविष्यनिधि में नियोक्ता (कंपनी) के वार्षिक अंशदान की अधिकतम सीमा डेढ़ लाख रुपये तय कर दी गई है.
- नियोक्ता द्वारा ईपीएफ में दिए जाने वाले 8.33 प्रतिशत हिस्से को सरकार देगी. सरकार यह योगदान सभी नए कर्मचारियों के पहले तीन सालों की नौकरी में देगी.

पृष्ठ 1 का शेष

क्षेत्र में सरकार द्वारा लगाया पैसा कोई परिणाम नहीं देता. इसलिए, मजबूरन आज फिर सरकार को कृषि और कृषि आधारित उद्योगों और किसानों की शरण में आना पड़ा है.

सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि चालू खाता घाटे में कमी आई है और चालू खाता घाटा 18.4 बिलियन से घट कर 16.4 बिलियन हो गया है, जो जीडीपी का 1.4 फीसदी है. गत कई महीनों से विश्व बाजारों में पेट्रोल की कीमतों में आ रही भारी कमी के कारण सरकार को मिलने वाले राजस्व में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी हुई है. खुद भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार 2.14 लाख करोड़ बचा चुकी है. जबकि चालू घाटा सिर्फ 4 बिलियन यानी 26 हज़ार करोड़ रुपये कम हुआ है, लेकिन बचा हुआ 1.88 लाख करोड़ कहीं भी बजट में प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है. इसकी वजह क्या है? इसमें मोदी सरकार की पारदर्शिता कहां गई? सिर्फ यही नहीं, बल्कि पिछले बजट में घोषित की गई अनेक योजनाओं में आवंटित धनराशि का एक बड़ा भाग खर्च नहीं हो सका और वह पूंजी भी भारत सरकार के पास ही सुरक्षित होनी चाहिए. इन योजनाओं की बड़ी राशि के बचे होने के बावजूद घाटे का बजट प्रस्तुत करना अचंभित करता है और कुछ अनुत्तरित सवाल भी खड़े करता है.

बहरहाल, ऐसी हालत में इस बजट में देश की अर्थव्यवस्था की धुरी कृषि जगत और कृषि आधारित छोटे उद्योगों की सुध ली गई है, ऐसा दर्शाया गया है. लेकिन, मजेदार बात यह है कि जिसे कृषि आधारित और किसानों का बजट कहा जा रहा उसमें 19,00,000 करोड़ में से महज 36,000 करोड़ रुपये का प्रावधान कृषि के लिए किया गया है जो दो फीसदी के आस-पास बैठता है. सरकार का दावा है कि आगे आने वाले छह सालों में किसान की आय दो गुनी कर दी जाएगी. यह दावा ही अपने आप में अस्पष्ट है, क्योंकि आठ सालों में तो बैंक की एफडी या गांव के पोस्ट ऑफिस में भी पैसा दोगुना हो जाता है तो छह सालों में किसान की आय दोगुनी करने का वायदा अपने आप में एक मजाक है.

बजट के प्रावधानों में एक भारी विरोधाभास तब साफ़-साफ़ दिखता है, जब एक तरफ कृषि क्षेत्र के विकास, कृषि आधारित उद्योगों को संबल, कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के दावे किए जा रहे हैं और दूसरी ओर मनरेगा में निवेश को 4,000 करोड़ बढ़ा कर 34,000 करोड़ किया जा रहा है. अब सवाल उठता है कि जब खेती और किसानी में इतने सुधार होने वाले हैं और किसानों की आय में वृद्धि होने वाली है तो फिर ये चालीस लाख परिवार कौन से हैं जिनको मनरेगा में शामिल किया जा रहा है? चालीस लाख परिवारों का मतलब यह हुआ कि कम से कम दो करोड़ लोग और मनरेगा में शामिल किए जाएंगे. अगर कृषि क्षेत्र में विकास होता है तो इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगार कहां से आएंगे या सरकार को अपने ही दावों पर भरोसा नहीं है?

ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर या ढांचागत सुधारों के लिए दी गई राशि सराहनीय है. परन्तु यह भी एक तथ्य है कि गांव का इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण गांव को ही ध्यान में रख कर किया जाता है. लेकिन, उसका तात्कालिक लाभ निर्माण करने वाली वाली कंपनी ही उठा लेती है. मेक इन इंडिया पर वित्त मंत्री की बातें काफी उत्साहजनक थीं और दालों की कीमत कम करने तथा उपलब्धता बढ़ने से संबंधित प्रावधानों ने भी सकारात्मकता का संचार किया. लेकिन वर्ष 2015 में जारी वैश्विक भुखमरी सूची में तीन सबसे बुरे हालत वाले देशों में से एक भारत के के बजट में कुपोषण, शिशु कुपोषण और महिला कुपोषण से निबटने के लिए कोई समुचित और प्रभावी कदम का अभाव भारी निराशा की तरफ ले जाता है.

अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और सरकार के विभिन्न जरूरी कार्यकलापों को सम्पन्न करने के लिए कर (टैक्स) ही एक महत्वपूर्ण जरिया होते हैं. इन करों का एक बड़ा भाग नागरिकों द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों से आता है. व्यापारी वर्ग का इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन वर्तमान कर-व्यवस्था ऐसी है जिसमें व्यापारी कर जमा करके राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दे कर गौरवान्वित होने के बजाय सब कुछ छोड़ कर उससे भागना ज्यादा अच्छा समझता है. जटिल कर प्रणाली और ऊपर से कर जमा करने वाली एजेंसियों का असहयोगपूर्ण रवैया, व्यापार और व्यापारी दोनों की कमर तोड़ देता है. आमूल-चूल कर सुधारों, कर वसूलने वाली एजेंसी के सहयोगपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके के बगैर हम व्यापारी वर्ग को देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते.

देश की अर्थव्यवस्था की सच्चाई जानने के लिए हमें आंकड़ों के जाल में उलझने की जरूरत नहीं है, बल्कि बंद होते उद्योग-धंधे, परेशान व्यापारी और बदहाल किसान ही अर्थव्यवस्था की सच्चाई बयां कर रहे हैं. वित्त मंत्री ने अपने बजट के माध्यम से उनको संबोधित नहीं किया. कंगाल होते व्यापारियों और बदहाली के शिकार किसानों के लिए कोई ठोस योजना नहीं है. जिंदगी का कीमती समय खपा कर, खून पसीना एक करके लगाई हुई औद्योगिक इकाइयां बंद हो चुकी हैं या बंद होने की कगार पर खड़ी हैं, लेकिन इन अनगिनत औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए बजट में कोई भी योजना नहीं है. आत्महत्या करते, कुपोषण और मुसीबतों से जूझते किसानों के लिए कोई ठोस योजना नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

क्या है बजट

सबसे पहले केंद्र सरकार के इस बहुप्रतीक्षित बजट के कुछ खास बिन्दुओं पर एक नज़र डालते हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुसार अर्थव्यवस्था में 7.6 फ़ीसदी की तेज़ी आई है और चालू खाता घाटे में भी कमी आई है. विदेशी मुद्रा भंडार 350 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और राजस्व घाटा 2.5 फ़ीसदी रहेगा. इस बजट को किसानों और ग्रामीण जन-जीवन पर आधारित बजट के रूप में पेश किया गया है.

बजट के विशेष प्रावधान आवंटन और घोषणाएं

- ग्रामीण विकास के लिए 87000 करोड़ रुपये.
- सड़कों और हाइवेज़ के लिए 97 हज़ार करोड़ रुपए (वित्त वर्ष में नेशनल हाइवेज़ को 10000 किलोमीटर और स्टेट हाइवेज़ को 50 हज़ार किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना).
- मनरेगा के लिए 38500 करोड़ रुपये.
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19,000 करोड़ रुपये.
- किसानों पर ऋण का बोझ कम करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये.
- बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 2,000 करोड़ रुपये (बीपीएल परिवारों के लिए पांच साल की योजना).
- नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा (प्रत्येक परिवार को एक लाख रुपये का हेल्थ कवर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी हुई सीमा).
- मार्च 2017 तक सस्ते राशन की तीन लाख नई दुकानें.
- स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरे से खाद बनाने की योजना.

नए सेस से जनता के पास क्या बचेगा शेष

क्लीन एनर्जी सेस – कोयला और लिग्नाइट पर अधिभार 200 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति टन.

प्रदूषण सेस – छोटी पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारों पर 1 प्रतिशत, डीज़ल कारों पर 2.5 प्रतिशत, महंगी कारों पर 4 प्रतिशत.

कृषि कल्याण सेस – सभी सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत.

विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लगाए गए 13 सेस खत्म.

आर्थिक ढांचे को खोखला कर रहा नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स

एनपीए से लड़खड़ाते हुए बैंकों के लिए जो प्रावधान किया गया है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है. एनपीए या यों ऐसे कर्ज, जिनका चुकाया जाना संभव नहीं है, एक राष्ट्रीय संकट बन चुका है. एनपीए का इतनी बड़ी तादाद में होना न सिर्फ अर्थव्यवस्था के संकट की ओर इशारा करता है बल्कि व्यापार में आ गए भारी गतिरोध को भी उजागर करता है.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल 4,50,000 लाख करोड़ रुपया कर्जे के रूप में फंसा है. कुछ प्रमुख बैंकों के एनपीए का जायजा लेते चलें :

बैंक	एनपीए
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	72791
बैंक ऑफ़ बड़ौदा	38934
बैंक ऑफ़ इंडिया	36519
केनरा बैंक	19813
यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया	18495

कीमतों में बढ़ोत्तरी व कमी

- बीड़ी को छोड़कर तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद कर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत.
- सोने और हीरे के जवाहरातों पर उत्पाद कर में 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी.
- सॉफ्ट ड्रिंक और मिनरल वाटर भी 3 प्रतिशत तक महंगे.
- 10 लाख रुपये से अधिक कीमत की कारों पर अब एक प्रतिशत अधिक कर लगेगा. हालांकि छोटी कारों को भी नहीं बख्शा गया है और इन्हें सेस के दायरे में लाया गया है.
- 1,000 रुपये से अधिक मूल्य के ब्रांडेड कपड़े और रेडिमेड गारमेंट्स, एल्यूमीनियम फॉइल, एयर टिकट, प्लास्टिक बैग, रोपवे, आयातित कृत्रिम ज्वैलरी, औद्योगिक सोलर वाटर हीटर, कानूनी सेवाएं, आयातित गोल्फ कार भी महंगी.
- लॉटरी टिकट, पैकर्स एंड मूवर्स और सोने की छड़ भी महंगी.
- सर्विस टैक्स 14.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत.
- चप्पलें, सोलर लैंप, राउटर, ब्रॉडबैंड मॉडेम, सेट टॉप बॉक्स, डिज़िटल वीडियो रिकॉर्डर, सीसीटीवी कैमरा, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, डायलसिस के उपकरण, 60 वर्गमीटर तक के सस्ते मकान, पेंशन प्लान, माइक्रोवेव ओवन, सैनेटरी पैड वगैरह सस्ते होंगे.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 08 अंक 02
दिल्ली, 14 मार्च-20 मार्च 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

जाट आरक्षण आंदोलन

जाट और ग़ैर-जाट में बंटा हरियाणा

हरियाणा में स्थिति अब सामान्य हो रही है. सड़कों पर और बाज़ारों में लोग दिखने लगे हैं. हाईवे पर गाड़ियां और रेल पटरियों पर रेल गाड़ियां दौड़ने लगी हैं. लेकिन, सड़कों के किनारे जली हुई गाड़ियों, बाज़ारों में जली हुई दुकानों और रिहाइशी इलाकों में हुए तोड़-फोड़ के निशान पिछले दिनों राज्य में जाट आरक्षण के नाम पर हुए उपद्रव की कहानी अब भी चीख़-चीख़ कर सुना रहे हैं. हालांकि उपद्रव से प्रभावित लोग अभी भी सहमे हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग अब उपद्रवियों के ख़िलाफ़ सरकार से कार्रवाई की मांग करने लगे हैं. हरियाणा जातिगत तौर पर जाट और ग़ैर-जाट में साफ तौर पर बंटा हुआ दिख रहा है और दोनों पक्ष हिंसा के लिए एक-दूसरे को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं. राज्य में पहले भी जाटों के आरक्षण के सवाल पर आंदोलन हो चुके हैं, जिनमें से कुछ हिंसक भी थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हिंसा कभी नहीं हुई थी. तो अब यह सवाल उठाना लाज़िमी है कि आख़िर यह हिंसा भड़की क्यों? अगर हिंसा भड़की तो इसको फैलने का मौक़ा क्यों दिया गया? क्या इस हिंसा का कोई राजनीतिक महत्व भी है? इन सवालों के जवाब आसान हैं और मुश्किल भी, क्योंकि इनमें भी कई सवाल छिपे हुए हैं ...

शफीक आलम

ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वावधान में जाटों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर 12 फरवरी से हवा सिंह सांगवान के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू हुआ. आंदोलन की शुरुआत हिसार जिले में दिल्ली–हिसार रेल लाइन को ब्लॉक कर दिया गया. गौरतलब है कि वर्ष 2012 में जाटों के आरक्षण के लिए यहां पहले भी आंदोलन हो चुका है. इस बार सांगवान जाटों के लिए आरक्षण के साथ–साथ कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद राज कुमार सैनी पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे थे. राज कुमार सैनी जाटों के आरक्षण का विरोध करते रहे हैं. सैनी का मानना है कि जाटों को आरक्षण देने से दूसरी पिछड़ी जातियों को नुकसान उठाना पड़ेगा. बहरहाल, जाट समुदाय से संबंध रखने वाले हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनकड़ के आश्वासन पर (कि जाट आरक्षण पर 31 मार्च तक कोई न कोई फैसला हो जाएगा) 13 फ़रवरी की रात को सांगवान ने अपना ब्लॉकेड हटा लिया. लेकिन उसके दूसरे दिन हालात उस समय तनावपूर्ण हो गए जब रोहतक जिले के सांपला में जाट स्वाभिमान रैली निकाली गई. इस रैली में रोहतक, झज्जर और सोनीपत के खाप प्रमुखों ने यह फ़ैसला किया कि यदि सरकार निर्धारित समय अवधि में उनकी मांगे नहीं मानती है, तो छह अप्रैल को राज्य स्तरीय बैठक बुलाकर आगे की रणनीति पर फैसला किया जाएगा. लेकिन रैली में मौजूद नौजवान आरक्षण के मसले पर जल्द कार्रवाई चाह रहे थे. उन्होंने अपने नेताओं के आदेश को न मानते हुए पंजाब–दिल्ली हाईवे जाम कर दिया. अगले दो दिनों तक यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन 18 फरवरी के बाद हालत बेक़ाबू हो गए.

हिंसा की शुरुआत उस समय हुई जब रोहतक के कुछ वकील जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित राष्ट्रद्रोह के मामले में छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक जुलूस निकाल रहे थे. उसी समय 35 बिरादरी संघर्ष समिति के बैनर तले 200 के करीब व्यापारियों का एक जुलूस भी निकल रहा था. इस जुलूस ने वकीलों को जाट आरक्षण का समर्थक समझ कर उनपर हमला कर दिया. जबकि व्यापारियों का कहना था कि वे जाट आंदोलन की वजह से ठप हो रहे व्यापार के संबंध में कलेक्टर को एक ज्ञापन देने जा रहे थे कि वकीलों ने उन्हें घेर लिया. एक दूसरी घटना जिसे हिंसा भड़काने का कारण बताया जा रहा है, वह है पंडित नेकी राम शर्मा गवर्मेंट कॉलेज, रोहतक में 18 फरवरी की रात ब्लॉकेड हटाने गई पुलिस पर पथराव और पुलिस द्वारा लाठी चार्ज. कॉलेज के छात्रों का आरोप है कि पुलिस हॉस्टल में घुस गई और उन्हें बुरी तरह से पीटा. इस घटना के बाद दूसरे दिन आसपास के गांव से तकरीबन 5000 जाट, जिनमें अधिकतर छात्र थे, हिंसक प्रदर्शन करने लगे. भीड़ ने न सिर्फ यातायात बाधित करना शुरू किया बल्कि वाहनों और दुकानों को आग के हवाले करना भी शुरू कर दिया. रोहतक जिले के कलानौर में दुकानों के साथ–साथ एक पेट्रोल पंप जला दिया गया. रोहतक से यह आग झज्जर जिले में भी पहुंच गई जहां उपद्रवियों ने पंजाबियों (भारत विभाजन के समय पाकिस्तान से आये लोग) और सैनियों की दुकानों और सम्पतियों को जलाना शुरू कर दिया. इसमें सबसे भयावह स्थिति झज्जर के छावनी मोहल्ले की हुई जहां 21 फरवरी को उपद्रवियों ने हमला किया और सैनियों, नाइयों और दूसरी पिछड़ी जातियों की दुकानों, गाड़ियों और घरों को निशाना बनाना शुरू किया. यहां हुई हिंसा में तीन जाट, दो सैनी और एक–एक हलवाई और कुम्हार जाति के लोग मारे गए.

धीरे–धीरे यह आग राज्य के दूसरे क्षेत्रों में भी फैलने लगी पानीपत और सोनीपत में रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं. जींद जिले के बुढ़ा–खेड़ा रेलवे स्टेशन के साथ–साथ राज्य के सात रेलवे स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया गया. सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिनमें हरियाणा रोडवेज़ की बसें भी शामिल थीं. राज्य के 10 ज़िले जाटों के आरक्षण के नाम पर हुए उपद्रव के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए. तक़रीबन नौ दिनों तक चले इस हिंसात्मक जाट आरक्षण आंदोलन में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लोग मारे गए और 200 से अधिक ज़ख्मी हुए. पुलिस के मुताबिक झज्जर में सबसे अधिक 13 लोग मारे गए, जबकि सोनीपत में आठ, रोहतक में पांच, जींद में दो और कैथल और हिसार में एक–एक लोगों की जानें गईं. लेकिन सबसे भयानक और शर्मसार करने वाली घटना सोनीपत के मुरथल में घटी, जिसमें एक चश्मदीद के मुताबिक घटना की रात तकरीबन 200 गाड़ियों का क़ाफिला एक साथ निकल रहा था, तभी मुरथल के सुखदेव ढाबा के पास उन गाड़ियों को रोक कर उनमें आग लगा दी गई और महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया. हालांकि हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद इस घटना की जांच चल रही है और अभी तक एक महिला को छोड़ कर कोई दूसरी पीड़ित इस मामले को लेकर सामने नहीं आई है. इस सिलसिले में पुलिस की भूमिका भी शक के दायरे में आ गई है. कई लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने पहले मामले को रफ़ा–दफ़ा करने की कोशिश की, लेकिन हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद उसे कार्रवाई करनी पड़ी. अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन पूरे आंदोलन से उपजी हिंसा को रोकने में इसलिए नाकाम रहा, क्योंकि इसके पीछे गंदी राजनीति का खेल खेला जा रहा था? पुलिस ने कार्रवाई भी की. पुलिस फायरिंग में प्रदर्शनकारी भी मारे गए. लेकिन यह हक़ीक़त है कि जब हिंसा पूरी तरह से भड़क गई तो पुलिस की नाकामी हर जगह देखने को मिली और बाद में सेना को बुलाना पड़ा. फ़िलहाल दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है. अब तक सात सौ से अधिक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और सौ से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है.

दरअसल, शांति के बाद अब जाट और ग़ैर–जाट हिंसा के लिए एक–दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप लगा रहे हैं. लेकिन जाट समुदाय फ़िलहाल बैकफुट पर नज़र आ रहा है. चुंकि हिंसा जाट समुदाय की तरफ से हुई थी, इसलिए वे अधिक रक्षात्मक हो गए हैं और इसके लिए सफाई दे रहे हैं. दूसरी तरफ ग़ैर–जाट जातियां महापंचायत बुला कर जाटों के सामाजिक बहिष्कार की बातें कर रही हैं. पिछले दिनों गुड़गांव में 35 ग़ैर–जाट जातियों के 100 गांवों की महापंचायत हुई जिसमें जाटों के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय लिया गया. इसमें महत्वपूर्ण बात यह रही कि पंचायत ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया. गुड़गांव के एक ग़ैर–जाट नेता ओमप्रकाश ने चौथी दुनिया को बताया कि पंचायत यह मानती है कि जाट आंदोलन आरक्षण के लिए कम और राजनीति से अधिक प्रेरित था. उनके मुताबिक यह आंदोलन एक ग़ैर–जाट मुख्यमंत्री को कमज़ोर करने की साज़िश के तौर पर शुरू हुआ था.

जाट आंदोलन का एक दूसरा पक्ष भी है. कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण की मांग के पीछे कुछ वास्तविक सामाजिक और आर्थिक कारण भी हैं. आम तौर यह पर माना जाता है कि हरियाणा में जाट एक समृद्ध जाति है और राज्य की सत्ता पर आम तौर पर उसी का वर्चस्व रहा है. सरकारी नौकरियों में भी उसकी हिस्सेदारी कम नहीं है. लेकिन कुछ लोग जाटों की बेचैनी का कारण मौजूदा सरकार और पूर्व की सरकारों की दीर्घकालिक नीतियों की नाकामी बता रहे हैं. उनका कहना है कि हरियाणा में कृषि अब लाभदायक नहीं रही. इसके सामाजिक दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं. दरअसल कृषि पैदावार में कमी और मुनाफ़े की कमी ने नौजवानों को शहर की तरफ पलायन को मजबूर किया है. ज़ाहिर है कि हरियाणा में उद्योग धंधे भी लगे हैं, लेकिन यहां उद्यमी राज्य के लोगों को नौकरी देने के बजाय दूसरे राज्यों से आये सस्ते मजदूरों को प्राथमिकता देते हैं. राज्य के युवाओं के पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन रोज़गार नहीं है. ऐसे में वे सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग करने लगे हैं. जाटों के आरक्षण आंदोलन का कारण रोहतक यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के प्रोफेसर देशराज भी कृषि की असफलता को ही मानते हैं. उनका कहना है कि कृषि पैदावार कम होने और कृषि में कम मुनाफ़ा कम होने के कारण लोगों का शहरों की तरफ पलायन हो रहा है जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है. वह यह भी मानते हैं कि हिंसा जातीय आधार पर हुई है, जिसकी वजह से जातियों के बीच दूरी बढ़ी है. राज्य जातीय स्तर पर इतना विभाजित कभी नहीं हुआ था. कुछ लोगों, जिनमें राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, को आरक्षण आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा ने देश विभाजन के समय हुए दंगों की याद दिला दी. अब राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक–दूसरे पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा रहे हैं. भजपा–कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि उसने भीड़ को उकसा कर हिंसा पर आमादा किया. उनकी तरफ से यह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह के कथित ऑडियो क्लिप का हवाला दिया जा रहा है जिसमें वह किसी से आंदोलन को तेज़ करने की बात करते सुने जा रहे हैं. हिंसा के लिए एक दलील यह भी दी जा रही है कि मौजूदा भाजपा सरकार में राज्य की सबसे बड़ी जाति जाटों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है. कांग्रेस और जाट समर्थक भाजपा नेता कुरुक्षेत्र से सांसद राज कुमार सैनी पर जाटों को उकसाने का आरोप लगा रहे हैं. इस पूरे आंदोलन पर सरकार और विपक्ष की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आईं, वे साफ तौर पर राजनीतिक नफ़ा–नुक़सान से प्रेरित थीं. जहां सरकार ने हिंसा को कुचलने के लिए ठोस क़दम नहीं उठाए वहीं विपक्ष, जिसकी नज़र जाट वोटरों पर है, ने भी सख्त निंदा नहीं की. कानून व्यवस्था की स्थिति सियासी नफ़ा–नुक़सान का खेल बन गया. रोहतक यूनिवर्सिटी में राजनीतिशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉ. रणबीर गुलीया का कहना है कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित था. उन्होंने भी भाजपा सांसद राज कुमार सैनी पर जाटों को उकसाने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि भाजपा को इसका राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाएगा और राज्य में अलग–अलग जातियों के बीच फिर से भाईचारा क़ायम हो जाएगा. लेकिन हरियाणा की सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार ने इस संवाददाता को बताया कि कांग्रेस ने यह खेल शुरू किया था जिसमें बाद में भाजपा भी शामिल हो गई. दोनों पार्टियों ने मिलकर जाट आंदोलन को हवा देने और इसे उकसाने का काम किया. उनका मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अधिक लाभ भाजपा को हुआ है, क्योंकि भले ही राज्य में चुनाव जीत गई हो, लेकिन यह जीत मोदी लहर की वजह से हासिल हुई थी. राज्य में पार्टी का कोई बड़ा जनाधार नहीं था. लेकिन इस जातीय हिंसा ने ग़ैर–जाट जातियों को भाजपा के पीछे खड़ा कर दिया है. ■

आर्थिक नुक़सान बेमिसाल

जाट आरक्षण आंदोलन और उससे भड़की हिंसा के कारण राज्य और देश को ज़बरदस्त आर्थिक नुकसान सहना पड़ा है. औद्योगिक संगठन पीएचडी चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स के एक सर्वे के मुताबिक राज्य में भड़की हिंसा की वजह से हरियाणा के साथ–साथ उत्तर भारत को 34,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. मारुति सहित कई कंपनियों को इस आंदोलन के दौरान अपना प्रोडक्शन स्थगित रखना पड़ा. कच्चे माल की सप्लाई नहीं मिलने और तैयार माल बाहर भेजने में शामिल खतरे की वजह से राज्य के कपड़ा उद्योग को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा. हिंसा की मार भुगत रहे व्यापारी राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जाने की बात कर रहे हैं. यह अफवाह उड़ रही थी कि एक कंपनी हिंदुस्तान विद्युत लिमिटेड हरियाणा से अपना प्रोडक्शन समेट कर किसी और राज्य में जा रही है. लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि कंपनी किसी और वजह से दूसरे राज्य में जा रही है. व्यापारी पंकज गुप्ता ने कहा कि राज्य में व्यापारियों में ख़ौफ़ ज़रूर है, लेकिन वे अभी राज्य छोड़ कर जाने की नहीं सोच रहे हैं. उन्होंने यह ज़रूर माना कि जाट आंदोलन से भड़की हिंसा के कारण व्यापारी वर्ग बेचैन है. राज्य में 7–8 मार्च से हैप्पेनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट होने वाला है. इसमें देश और विदेश के उद्यमियों को शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है. जिस तरह विदेशी अख़बारों ने हरियाणा के जाट आंदोलन से उपजे दंगों को कवर किया. उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस सम्मिट के प्रति विदेशियों में उतना उत्साह देखने को नहीं मिलेगा. अब तक सम्मेलन में भाग लेने के लिए हुए रजिस्ट्रेशन में विदेशी उद्यमियों की तादाद भारतीय उद्यमियों के मुक़ाबले बहुत कम है. आंदोलन की वजह से राज्य सरकार ने 9 मार्च से शुरू होने वाले प्रवासी सम्मेलन को भी रद्द कर दिया है. प्रवासी सम्मेलन में मुख्यमंत्री हरियाणा से संबंध रखने वाले प्रवासी भारतीयों से एक–एक गांव गोद लेने का आह्वान करने वाले थे. ज़ाहिर है कि इस वजह से भी राज्य को आर्थिक नुक़सान उठाना पड़ेगा. बहरहाल, आर्थिक मामलों के कुछ जानकारों का कहना है कि हरियाणा आर्थिक तौर पर पांच वर्ष पीछे चला गया है. ■

हरियाणा के जाटों को आरक्षण मिलने और राजस्थान में भी भरतपुर-धौलपुर को छोड़ कर बाकी जगह जाटों को आरक्षण हासिल हो जाने का असर दूसरी जातियों खासकर ब्राह्मण-राजपूतों पर भी देखा गया. खासतौर पर राजपूतों ने इस दिशा में पहल की. राजपूतों के कद्दावर कहे जाने वाले नेता देवी सिंह भाटी और लोकेंद्र सिंह कालवी ने सामाजिक न्याय मंच का गठन किया, जिसके जरिए उन्होंने राजपूतों समेत दूसरी सवर्ण जातियों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग रखी है.

हरियाणा के बाद राजस्थान में भी सुलगने लगी आरक्षण की चिंगारी

अब सब चाहें आरक्षण

> हरियाणा के जाटों को आरक्षण मिलने और राज्य में भी भरतपुर-धौलपुर को छोड़ कर बाकी जगह जाटों को आरक्षण हासिल हो जाने का असर दूसरी जातियों खासकर ब्राह्मण-राजपूतों पर भी देखा गया. खासतौर पर राजपूतों ने इस दिशा में पहल की. राजपूतों के कद्दावर कहे जाने वाले नेता देवी सिंह भाटी और लोकेंद्र सिंह कालवी ने सामाजिक न्याय मंच का गठन किया, जिसके जरिए उन्होंने राजपूतों समेत दूसरी सवर्ण जातियों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग रखी...

सुनीता सिंह

हरियाणा में भारी तबाही को अंजाम देने के बाद जाट आंदोलन अब थम चुका है. पीछे रह गए हैं, तो कुछ दिन पहले तक समृद्ध कहे जाने वाले हरियाणा की बरबादी के निशान. हरियाणा की मेहनती जमात जल्दी ही इस दंश को मिटाते हुए विकास के पथ पर फिर से आगे बढ़ जाएगी, इसकी उम्मीद सभी को है. लेकिन हरियाणा से शुरू हुई कहानी क्या यहीं पर रुक जाएगी? इस सवाल का जवाब टेढ़ा ही नहीं है, बल्कि एक तरह से यह हुक्मरानों के सामने और आम जनता के जेहन में बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह बनाए खड़ा है. जाट आंदोलन के पीछे सियासी कारण और कुचक्र होंगे, इसकी आशंका से किसी को इन्कार नहीं है, लेकिन हालिया आंदोलन ने राजस्थान जैसे आरक्षण को लेकर सुलगते धोरों के नीचे दबी आग को जैसे कुरेदने का ही काम किया है. यह आशंका अब प्रबल हो गई है कि जल्द ही यहां की कुछ और कौमें भी अपनी जमात को आरक्षण दिलाने की मुहिम के तहत नई मांगों के साथ सामने आ सकती हैं. दरअसल, राजस्थान में आरक्षण को लेकर चर्चा से पहले यहां आरक्षण की चाह रखने वाली जमात की स्थिति और समीकरणों के बारे में भी जानना जरूरी है.

सरसरी तौर पर देखा जाए, तो भले ही जाट समुदाय की आरक्षण की मांग और गुर्जरों की मांग के बीच कोई लिंक दिखाई न देता हो, लेकिन यह कटु और प्रमाणित तथ्य है कि राजस्थान के सर्वाधिक हिंसक आंदोलनों के इतिहास में अंकित हो चुके गुर्जर आंदोलन की वजह दरअसल जाट आंदोलन की कोख से ही निकली है. राजस्थान में गुर्जरों की आबादी करीब 11-12 फीसदी के आसपास है. कारण समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा और राजस्थान में हुए आरक्षण आंदोलनों के इतिहास में भी झांकना होगा. बात 1993 की है, जब नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था. आयोग को मुख्य काम यह सौंपा गया था कि वह राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी समेत उन सभी राज्यों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की जरूरत को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करे, जहां से ऐसी मांगें उठ रही हैं. तब कमीशन को कहा गया था कि वह पिछड़ा वर्ग में आरक्षण के योग्य और आरक्षण की सुविधा ले रही जातियों को लेकर एक समीक्षात्मक रिपोर्ट तैयार करे, जिसके अनुसार यह तय किया जा सके कि किन-किन नई जातियों को इस वर्ग में शामिल किया जा सकता है और किन को बाहर किया जा सकता है. सन 1997 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी. सरकार वह रिपोर्ट दबाए बैठी रही. केंद्र में 13 महीने की सरकार चलाने के बाद संख्या अभाव में इस्तीफा देकर फिर से चुनाव मैदान में उतरने वाले भाजपा के सर्वमान्य नेता अटल विहारी वाजपेयी की उन दिनों एक रैली सीकर में हुई थी. वाजपेयी ने वहां वादा किया था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में वापसी आई तो जाटों को केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण दिलवा कर रहेंगे. भीड़ ने उन्हें हाथों-हाथ लिया. संयोग से वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए की सरकार सत्तारूढ़ हुई. सत्ता में आने के कुछ ही दिन बाद 1999 में वाजपेयी सरकार ने जाटों को ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया.

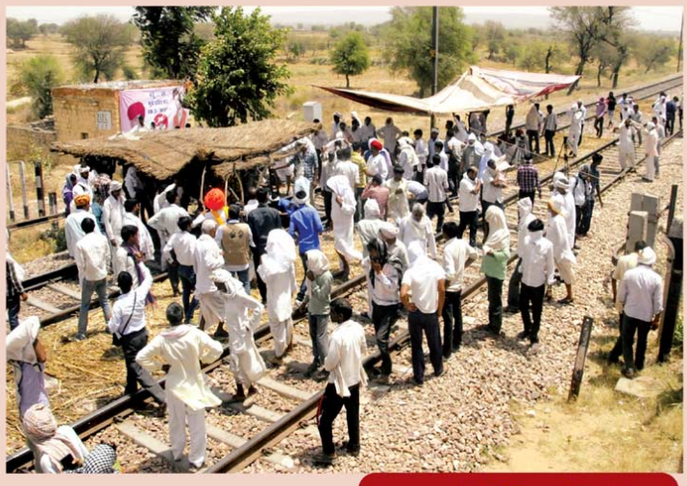

दरअसल, 1993 में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ने 1997 में जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, उसमें एक अहम बात यह थी कि उसने पूरे राजस्थान के जाटों को तो आरक्षण के योग्य माना था और उन्हें आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराने की पैरवी की थी, लेकिन भरतपुर और धौलपुर के जाटों को सूची से बाहर रखा था. आयोग का कहना था कि भरतपुर और धौलपुर के शासक ही जाट समुदाय से आते हैं, लिहाजा साधन-सम्पन्न होने के कारण वहां के जाट आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते. जनवरी 2000 में राज्य सरकार ने भी राज्य में जाटों को इसी तर्ज पर (भरतपुर और धौलपुर के जाटों को छोड़ कर) आरक्षण दे दिया. माना जाता है कि गुर्जर आंदोलन की नींव भी साल 2000 में ठीक उस वक्त ही पड़ गई, जब सरकार ने राज्य में जाटों को ओबीसी में शामिल कर लिया. गुर्जर समुदाय को लगा कि उनके हक में सेंध लग चुकी है. अगर जाट समुदाय को ओबीसी में आरक्षण दिया गया, तो पहले से ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण का थोड़ा-बहुत लाभ ले पा रहे उनके समुदाय का हक मारा जाएगा, लिहाजा गुर्जर समुदाय के बीच इस बात को लेकर गहन चर्चा और मनन का दौर शुरू हो गया कि ओबीसी से निकल कर एसटी यानी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का दबाव बनाया जाए. इस बीच 2003 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने गुर्जरों को एसटी स्टेटस देने का वादा किया, तो गुर्जरों को लगा कि वे सही ट्रैक पर हैं और अगर उन्होंने दबाव बनाया, तो उनके समुदाय को एसटी में आरक्षण मिल सकता है. इसी दौर और जद्दोजहद में गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का नाम सामने आया. साल 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व उनके सिपहसालारों के साथ बैंसला और उनके साथियों का एक ग्रुप मंत्रणाएं करने लगा, लेकिन कोई हल नहीं निकला. राज्य सरकार ने भी तब तक गुर्जर समुदाय की मांगों को एक गंभीर आंदोलन जैसा नहीं माना था. वर्ष 2007 के अप्रैल महीने के अंतिम दिनों से गुर्जर आंदोलन की सुगबुगाहटें सामने आने लगीं. चेतावनी और अल्टीमेटम का भी दौर चला. राज्य सरकार ने गुर्जरों को प्रस्तावित आंदोलन वापस लेने के लिए कहा, लेकिन कोई ठोस वादा नहीं किया. इस पर कर्नल बैंसला ने आंदोलन का आह्वान किया वार्ता के लिए सरकार के तैयार होने तक 23 लोगों की जानें चली गईं. इस दौरान कई जगह गुर्जर और मीणा समुदाय के बीच टकराव भी हुआ. मीणा समुदाय ने साफ तौर पर घोषणा कर दी कि वे किसी भी हाल में गुर्जरों को एसटी में शामिल नहीं होने देंगे. राजस्थान में एसटी आरक्षण की सुविधा का सर्वाधिक और प्रभावी लाभ मीणा समुदाय ही उठाता रहा है.

आरक्षण की मौजूदा स्थिति

एससी- 16 फ़ीसद
एसटी- 12 फ़ीसद
ओबीसी-21 फ़ीसद
एसबीसी- 05 फ़ीसद
(एसबीसी - स्पेशल बैकवर्ड क्लास)

बहरहाल, राज्य सरकार ने रास्ता निकालते हुए, गुर्जरों को आरक्षण देने के लिए एक स्पेशल श्रेणी एसबीसी (स्पेशल बैकवर्ड क्लास) बना कर उन्हें 5 फीसदी आरक्षण दिए जाने की बात कही. साथ ही सवर्णों और अन्य जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़ों को भी ईबीसी (इकोनामिकल बैकवर्ड क्लास) के नाम से 14 फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई. राज्यपाल ने इस प्रस्ताव पर सहमति देने से मना कर दिया. इसके बाद सरकार ने इसे विधानसभा से पास कराया, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी. इसी बीच 2008 में कांग्रेस सत्ता में आ गई. गुर्जर फिर सड़क पर उतर आए. 23 मई 2008 को शुरू हुआ आंदोलन 17 जून तक चला. इस दरम्यान खूब हिंसा हुई. पीलूकापुरा में फायरिंग हुई. 14 लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए. बाद में सिकंदरा में भी हिंसा भड़कने से कुल 17 लोगों की मौत हो गई. सवाई माधोपुर में भी दो लोग मारे गए. कांग्रेस सरकार के मुखिया अशोक गहलोत ने गुर्जर आरक्षण के मुद्दे को लेकर पिछली भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उसने गुर्जरों को धोखा दिया, क्योंकि ईबीसी आधार पर आरक्षण संविधान के अनुसार तो दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित सीमा यानी 50 फीसदी से ऊपर जा रहा है. गहलोत सरकार ने गुर्जरों के लिए दो अलग-अलग बिलों का प्रस्ताव किया. जिसमें से एसबीसी के लिए 5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था थी और ओबीसी के लिए 14 फीसदी, लेकिन यह मामला भी कोर्ट में अटक गया. कोर्ट ने क्वान्टिफिएबल डाटा लाने की बात कही. जिसके बाद चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष लाई गई, जिसका गठन वसुंधरा सरकार के समय हुआ था. चोपड़ा आयोग ने गुर्जरों को पिछड़ा मानते हुए उन्हें आरक्षण दिए जाने की वकालत की थी. कुल मिला कर साल 2006 से लेकर 2015 तक गुर्जरों के विभिन्न आंदोलन हुए, लेकिन एसटी में शामिल होने की जिस मूल मांग को आंदोलन की शुरुआत की थी, वह मसला पीछे छूट गया और एसबीसी में आरक्षण को लेकर भी स्थिति साफ नहीं हो पाई, जिसका नतीजा यह है कि आज भी रह-रह कर यह समुदाय आरक्षण की हुंकार भरता रहता है.

और जाट आंदोलन का क्या हुआ

इस बीच राज्य के भरतपुर और धौलपुर इलाकों के जाट समय-समय पर अपने समुदाय को आरक्षण दिए जाने की मांग उठाते रहे, लेकिन उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया गया. हालांकि, इस दौरान एक बड़ा बदलाव यह हुआ कि धौलपुर-भरतपुर के जाटों की मांगों के साथ हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत आठ अन्य राज्यों के जाट भी जुड़ गए. हरियाणा के जाटों के आंदोलन के साथ ही अंतिम के दो-तीन दिनों में भरतपुर और धौलपुर के जाट भी जुड़ गए. उन्होंने खासतौर से भरतपुर-मथुरा रेलखंड और आगरा-जयपुर रोड को निशाने पर लिया. हरियाणा के आंदोलनकारियों की ही तर्ज पर उन्होंने आंदोलन को हिंसक बनाने की भी कोशिश की, नतीजे में हेलक स्टेशन के पास खड़ी एक मालगाड़ी के इंजन में आग लगा दी गई, जबकि एक अन्य स्टेशन को तो उन्होंने तहस-नहस ही कर डाला. हरियाणा में जाट आंदोलन के थमते ही राजस्थान सरकार ने भी बातचीत की पहल कर दी. जाट आंदोलनकारियों ने मांग रखी कि ओबीसी कमीशन को विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले ही भरतपुर भेजा जाए. साथ ही ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए. सरकार ने उनकी मांगें मान लीं और फिलहाल भरतपुर-धौलपुर के जाटों ने आंदोलन वापस ले लिया.

सुगबुगाहट नए आंदोलन की

हरियाणा के जाटों को आरक्षण मिलने और राज्य में भी भरतपुर-धौलपुर को छोड़ कर बाकी जगह जाटों को आरक्षण हासिल हो जाने का असर दूसरी जातियों खासकर ब्राह्मण-राजपूतों पर भी देखा गया. खासतौर पर राजपूतों ने इस दिशा में पहल की. राजपूतों के कद्दावर कहे जाने वाले नेता देवी सिंह भाटी और लोकेंद्र सिंह कालवी ने सामाजिक न्याय मंच का गठन किया, जिसके जरिए उन्होंने राजपूतों समेत दूसरी सवर्ण जातियों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग रखी. अब यूं तो सामाजिक न्याय मंच भंग हो चुका है. देवी सिंह भाटी भाजपा में शामिल हो चुके हैं और विधायक भी हैं, लेकिन इसके बावजूद ताजा घटनाक्रम से एक बार फिर खासतौर से राजपूत समुदाय में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग फिर से जोर पकड़ती दिखाई दे रही है. फरवरी का अंतिम सप्ताह मानों राजस्थान में आरक्षण की कशमकश को लेकर भविष्य में होने वाली खींचतान का संकेत ही दे गया, जब बाड़मेर-बीकानेर इलाके में करणी सेना और कुछ राजपूत संगठनों के माध्यम से राजस्थान के राजपूतों ने भी अपने लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करके हजारों की तादाद में रैली निकाली. ■

feedback@chauthiduniya.com

जिसे अदालत ने देशद्रोह नहीं माना...

शशि शेखर
feedback@chauthiduniya.com

जेएनयू और कन्हैया कुमार प्रकरण के बाद देश में देशद्रोह बनाम देशभक्ति एक राष्ट्रीय मुद्दा बनकर सामने है. हालत यह है कि विभिन्न राजनेता एवं संगठन देशद्रोही और देशभक्त का प्रमाण-पत्र बांटने का काम कर रहे हैं. ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि आख़िर देशद्रोह होता क्या है, इस बारे में संविधान क्या कहता है, क़ानून क्या कहता है? सबसे अहम बात यह कि देश की अदालतों ने इसे कैसे पारिभाषित किया है? यह सब इसलिए भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश अपने संविधान एवं क़ानूनों के हिसाब से चलता है और चलना भी चाहिए, न कि कुछ लोगों या समूहों की भावनाओं के मुताबिक. वैसे देशद्रोह को लेकर एक दिलचस्प तथ्य भी है. अगर हम पूरे देश में देशद्रोह के मामलों की बात करें, तो सबसे आगे बिहार और झारखंड का नंबर आता है. सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, 2014 में देशद्रोह के मामले में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां झारखंड में हुईं. उसके बाद केरल में देशद्रोह के सबसे अधिक मुक़दमे दर्ज किए गए.

आइए, पिछले कुछ वर्षों के दौरान देशद्रोह के आरोपों पर विभिन्न अदालतों ने क्या कहा, यह जानते हैं. लेकिन, उससे पहले यह जानते हैं कि देशद्रोह की परिभाषा क्या है और इसे सुप्रीम कोर्ट ने कैसे पारिभाषित किया है? भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की एक धारा है 124-ए. इसी धारा के तहत किसी पर देशद्रोह या राजद्रोह का मुक़दमा दर्ज किया जाता है. 124-ए के तहत अगर कोई व्यक्ति सरकार के ख़िलाफ़ लिखकर, बोलकर, संकेत देकर या फिर अभिव्यक्ति के किसी अन्य माध्यम के ज़रिये विद्रोह करता है या नफरत फैलाता है, तो ऐसा कृत्य देशद्रोह है. इस क़ानून के तहत अधिकतम सजा उम्रक़ैद है. लेकिन, पुलिस द्वारा देशद्रोह के आरोप लगाने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124-ए का दायरा फिर से पारिभाषित करते हुए उसे सीमित करने का काम किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करे, जिससे अव्यवस्था फैलती है, क़ानून व्यवस्था खराब होती है और हिंसा को बढ़ावा मिलता है, तभी उसके ख़िलाफ़ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जा सकता है. अदालतों ने अपने फ़ैसले में कई बार कहा है कि महज नारेबाजी के आधार पर किसी के ख़िलाफ़ देशद्रोह का मुक़दमा नहीं बनता. ■

आलोचना देशद्रोह नहीं

1962 में इस मामले में फ़ैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सरकार की आलोचना कर देने से किसी के ख़िलाफ़ देशद्रोह का मामला नहीं बन जाता. 1953 में केदार नाथ सिंह ने बरौनी-बिहार की एक सभा में तत्कालीन बिहार सरकार के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था.

बलवंत सिंह-बलविंदर सिंह

नारे से ख़तरे में नहीं पड़ता देश

1995 में पंजाब के बलवंत सिंह एवं बलविंदर सिंह पर देशद्रोह के आरोप लगे. दोनों ने 31 अक्टूबर, 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद खालिस्तान के समर्थन में राज करेगा खालसा और हिंदुओं को पंजाब से बाहर निकालेंगे जैसे नारे लगाए थे. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि स्थापित क़ानून के मुताबिक, कुछ लोगों द्वारा अकेले नारेबाजी भर कर लेने से भारत सरकार को कोई ख़तरा पैदा नहीं होता. इसके अलावा ऐसा करने से विभिन्न समुदायों या धर्मों के बीच आपसी दुश्मनी या नफरत की भावना नहीं पैदा होती.

बिनायक सेन

किताब पढ़ना देशद्रोह नहीं

छत्तीसगढ़ सरकार ने डॉ. बिनायक सेन पर देशद्रोह का आरोप लगाया, जिसका आधार था नक्सलियों के प्रति सहानुभूति. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिनायक सेन को न सिर्फ़ जमानत दी, बल्कि यह भी कहा कि सेन पर देशद्रोह का मामला नहीं बनता है. अदालत ने कहा कि नक्सलियों को समर्थन का मतलब देशद्रोह नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई जेल में जाकर नक्सली नेताओं से मिलता है और घर में नक्सलियों से संबंधित किताबें रखता है, तो उसे देशद्रोही नहीं मान सकते. ठीक उसी तरह, जैसे कोई गांधी जी से जुड़ी किताबें अपने यहां रखता है, तो वह गांधीवादी नहीं हो जाता.

नारों का असर जांचिए

1982 में पी अलावी पर अदालत और सरकार के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक नारे लगाने का आरोप लगा था. 2010 में केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि मौजूदा न्यायिक कार्य प्रणाली या विधायिका की आलोचना या महज नारेबाजी से सरकार के ख़िलाफ़ नफरत नहीं फैलती. अदालत ने कहा कि ऐसे नारों के वास्तविक असर को देखा जाना चाहिए.

नारे से हिंसा न फैले

2009 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ता गुरजंतिंदर पाल सिंह के ख़िलाफ़ देशद्रोह क़ानून के तहत दर्ज एफआईआर ही खारिज कर दी थी. अदालत ने कहा कि नारेबाजी से देशद्रोह नहीं होता है. गुरजंतिंदर पाल ने 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए आतंकियों की याद में आयोजित एक समारोह में खालिस्तान की मांग संबंधी नारे लगाए थे. उनके साथ अन्य लोगों ने भी नारेबाजी की थी. लेकिन, हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का उदाहरण देते हुए कहा कि महज नारेबाजी करने, जिससे हिंसा न फैलती हो, से देशद्रोह का आरोप नहीं बनता. अदालत ने उनके ख़िलाफ़ देशद्रोह का मामला निरस्त कर दिया था.

कार्टून देशद्रोह नहीं

असीम त्रिवेदी

विवादास्पद कार्टून बनाने की वजह से कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को गिरफ्तार किया गया था. उन पर देशद्रोह का आरोप था. हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद असीम जेल से रिहा हुए थे. उन पर लगा देशद्रोह का आरोप सरकार को वापस लेना पड़ा था. इस मामले में बांबे हाईकोर्ट ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को स्टेट मशीनरी की कड़े शब्दों में आलोचना करने का अधिकार है. देशद्रोह का आरोप तभी लगेगा, जब ऐसे कृत्य से हिंसा भड़के. अदालत ने यह भी माना कि असीम के कार्टून देशद्रोह जैसे कृत्य नहीं हैं.

सरकार के ख़िलाफ़ लिखना देशद्रोह नहीं

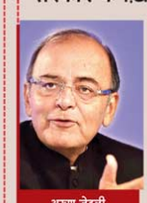
अरुण जेटली

अक्टूबर, 2015 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नेशनल ज्यूडिशियल अप्वायंटमेंट कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की आलोचना करते हुए एक आर्टिकल लिखा था. इस आर्टिकल में उन्होंने कहा था कि यह लोकतंत्र कुछ गैर निर्वाचित लोगों की निरंकुशता से नहीं चल सकता. इस आर्टिकल को लेकर एक मजिस्ट्रेट ने जेटली पर देशद्रोह का आरोप लगाकर समन भेज दिया. इस मामले में जब जेटली इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे, तब न सिर्फ़ अदालत ने यह आरोप खारिज किया, बल्कि उक्त मजिस्ट्रेट को भी निलंबित कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि एक नागरिक को सरकार के ख़िलाफ़ लिखने का अधिकार है. वह सरकार के ख़िलाफ़ टिप्पणी कर सकता है, आलोचना कर सकता है और तब तक, जब तक कि इस सबसे वह नागरिकों को हिंसा के लिए नहीं उकसाता, देशद्रोह का मामला नहीं बनता है.

पाताल कोट के नन्हे जुगनू

जावेद अनीस

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले के तामिया ब्लॉक का पाताल कोट मानो धरती के गर्भ में समाया है. यह घाटी सदियों तक बाहरी दुनिया के लिए अनजान और अछूती बनी रही. पाताल कोट में 12 गांव हैं, गैलुडब्बा, कारेआम, रातेड़, घटलिंगा-गुढ़ीछत्री, घाना कोड़िया, चिमटीपुर, जड़-मांदल, घर्राकछार, खमारपुर, शेरपंचगेल, सुखाभंड-हरमुहुभंजलाम और मालती-डोमिनी. बाहरी दुनिया का यहां के लोगों से संपर्क हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है. इनमें से कई गांव ऐसे हैं, जहां आज भी पहुंचना बहुत मुश्किल है. ज़मीन से काफी नीचे और विशाल पहाड़ियों से घिरे होने के चलते इसके कई हिस्सों में सूरज की रोशनी भी देर से और कम पहुंचती है. मानसून में बादल पूरी घाटी को ढंक लेते हैं और तैरते हुए नज़र आते हैं. सतपुड़ा की पहाड़ियों में क़रीब 1,700 फुट नीचे बसे ये गांव भले ही तिलिस्म का एहसास कराते हों, लेकिन यहां बसने वाले लोग हमारी और आपकी तरह ही हाड़-मांस के इंसान हैं. ये लोग भारिया एवं गौंड आदिवासी समुदाय के हैं, जो अभी भी हमारे पूर्वजों की तरह अपने आपको पूरी तरह प्रकृति से जोड़े हुए हैं. इन लोगों की ज़रूरतें सीमित हैं, प्राकृतिक संसाधनों के साथ इनका रिश्ता सह-अस्तित्व का है और अपनी संस्कृति, परंपरा, ज़िंदगी जीने एवं आपसी व्यवहार का तरीका भी पुरातन है, बिल्कुल सहज, सरल और निश्छल. बाहरी दुनिया से संपर्क और सदियों से संजोकर रखी गई प्रकृति से छेड़छाड़ के चलते अब ये संकट में दिखाई दे रहे हैं.

पाताल कोट को लेकर भले ही कई मिथक हों, लेकिन यहां की समस्याएं यथार्थ हैं. यहां भी विकास की कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनका लाभ ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच सका है. 2007 में यहां पहला आंगनबाड़ी केंद्र खुला था. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित पाताल कोट विकास प्राधिकरण की वजह से यहां स्कूली शिक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा जैसी सेवाएं पहुंच गई हैं, लेकिन बाकी सुविधाओं से यहां के लोग वंचित हैं. गैलुडब्बा तक पक्की सड़क होने से आना-जाना आसान हो गया है, लेकिन बाकी क्षेत्र अभी भी कटे हुए हैं. खेती भी परंपरागत और नए तरीकों के बीच उलझ कर रह गई है. लोग अपनी पुरानी फसलों से तक़रीबन हाथ धो चुके हैं, नई नगदी फसलों से भी कोई खास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है. पुराना खाद्य सुरक्षा तंत्र बिखरने का नतीजा यह है कि जानलेवा कुपोषण ने यहां अपने पैर पसार लिए हैं. क्षेत्र में पानी की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है.

यहां पानी का एकमात्र स्रोत पहाड़ों से निकलने वाली जलधाराएं रही हैं. पहले उक्त जलधाराओं में वर्ष पर्यंत पानी रहता था, लेकिन अब वे ठंड में भी सूख जाती हैं. ऐसा जलवायु परिवर्तन और बाहरी हस्तक्षेप के चलते हुआ है. पाताल कोट की जैविक विविधता, प्राकृतिक संसाधन एवं वन संपदा ख़तरे में हैं. यहां की दुर्लभ जड़ी-बूटियों का बड़ी बेरहमी से दोहन हो रहा है. अगर रोक नहीं लगी, तो पाताल कोट का उक्त बहुमूल्य खजाना खत्म हो जाएगा.

स्वैच्छिक संस्था विज्ञान सभा 1997 से पाताल कोट में वैज्ञानिक चेतना, स्वास्थ्य, आजीविका एवं खेती आदि बिंदुओं पर काम कर रही है. संस्था के तामिया स्थित सेंटर के समन्वयक आरिफ खान के मुताबिक, विज्ञान सभा ने यहां आजीविका एवं स्वास्थ्य को लेकर काफी काम किया. लोगों को वैज्ञानिक तरीके से शहद निकालने का प्रशिक्षण दिया गया और आवश्यक पोशाक उपलब्ध कराई गई. गैलुडब्बा सेंटर में शहद की हार्वेस्टिंग के लिए मशीन लगाई गई है. वनोपज को लेकर भी लोगों को जानकारी दी गई कि उन्हें किस समय तोड़ना चाहिए, जिससे उनकी मेडिसिन वैल्यू ख़त्म न होने पाए. वनोपज बेचने में भी संस्था द्वारा सहयोग किया जाता है. पिछले कुछ वर्षों से विज्ञान सभा द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से बाल अभिव्यक्ति एवं सहभागिता को लेकर भी काम किया जा रहा है, जिसका मकसद बच्चों में आत्मविश्वास, कौशल, अभिव्यक्ति एवं शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें एक मंच उपलब्ध कराना है, जहां वे अपने अनुभव-विचार सबके सामने रख सकें. इसके तहत चित्रकला, फोटोग्राफी, लेखन एवं विज्ञान से संबंधित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं. बच्चों की अभिव्यक्तियां बाल पत्रिका गुड़िया में प्रकाशित भी की जाती हैं. कुछ समय पहले यहां ज्ञान-विज्ञान पोटली (पुस्तकालय) की शुरुआत की गई, जिससे बच्चों को किताबों एवं शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ा जा सके. पाताल कोट में इन सबका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है. बकौल आरिफ, बच्चे पहले कुछ बोलने में झिझकते थे, लेकिन अब वे खुलकर बातचीत करने लगे हैं और अपने आसपास की समस्याएं पेंटिंग, फोटोग्राफी एवं लेखन के माध्यम से सामने लाने लगे हैं.

बच्चों की रचनात्मकता बड़ी है, उनकी हिचक टूटी है और वे अपने अधिकारों के बारे में भी जान-समझ रहे हैं. पिछले दिनों विज्ञान सभा की एक फोटोग्राफी कार्यशाला के सिलसिले में पाताल कोट स्थित गैलुडब्बा गांव जाने का मौक़ा मिला. उस दौरान 26 जनवरी भी थी. बच्चों के साथ बड़े-बुजुर्गों ने भी गणतंत्र दिवस बहुत उत्साह के साथ मनाया. बाद में पता चला कि क्षेत्र में 1997 से पहले स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस को लेकर कोई जागरूकता नहीं थी. जानकारी के अभाव में लोग इन राष्ट्रीय पर्वों से विमुख थे. गैलुडब्बा की फोटोग्राफी कार्यशाला का आयोजन पांच विद्यालयों ने संयुक्त रूप से किया था, जहां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पाताल कोट के विभिन्न गांवों के पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे एकत्र हुए थे. इस दो दिवसीय आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, खेल प्रतियोगिताएं हुईं. सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों-बड़ों की समान रूप से भागीदारी देखी गई. परंपरागत सामूहिक नृत्य के अलावा देश रंगीला एवं जलवा तेरा जलवा जैसे गीतों पर दी गई प्रस्तुतियों ने आयोजन में चार चांद लगा दिए. प्रत्येक प्रस्तुति के बाद मंच संचालक की ओर से पुरस्कार का ऐलान भी किया जा रहा था. गणतंत्र दिवस का यह अनोखा उत्सव देखना एक सुखद एहसास था. बच्चे घर, पहाड़, नदियों, पेड़-पौधों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करके बहुत खुश नज़र आ रहे थे. पाताल कोट के बच्चे भी जीवन के सपने देख रहे हैं. वे डॉक्टर, नर्स, फोटोग्राफर, वैज्ञानिक, टीचर, इंजीनियर, चित्रकार वगैरह बनना चाहते हैं. ज़ाहिर है, ये सपने बड़े हैं, लेकिन बच्चे बाहरी दुनिया की भाषा और तौर-तरीकों से स्वयं को अभिव्यक्त करना सीख रहे हैं. वे चाहते हैं कि यहां के लोगों को जीवनयापन के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं. उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति में कहीं अवचेतन से यह भी निकल कर आ रहा है कि उनके पहाड़, जंगल, पेड़-पौधे एवं वनोपज सलामत रहें, जो उनकी धरोहर हैं. उम्मीद कर सकते हैं कि पाताल कोट के उक्त जुगनू आने वाले समय में घाटी समेत देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी चमक ज़रूर बिखेरेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

केंद्रीय बजट

मोदी के वादे पर उठे सवाल

सरोज सिंह

बिहार को विशेष दर्जा मिले या फिर विशेष पैकेज इसे लेकर लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव में लंबी बहस चली. आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरा के कार्यक्रम में बिहार के लिए विशेष पैकेज का ऐलान कर इस तरह की तमाम बहसबाजी का पटाक्षेप कर दिया. ठीक उसी दिन से यह उम्मीद की जा रही थी कि अगामी बजट में केंद्र सरकार बिहार के लिए पैकेज के अनुरूप पैसे का आवंटन करना शुरू कर देगी. लेकिन जेटली साहब ने जो बजट पेश किया उससे बिहार के लोगों को खासकर 1.25 लाख करोड़ के पैकेज के संदर्भ में निराशा ही हाथ लगी है. हालांकि एनडीए से जुड़े लोग कहते हैं कि बजट में बिहार का पूरा ध्यान रखा गया है, पर जब बिंदुवार बहस होती है तो उनकी आवाज धीमी पड़ती जाती है. बात यहीं खत्म नहीं हुई है. चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में बिहार को केंद्रीय करों से मिलने वाली राशि में 1339 करोड़ रुपये की कटौती होगी यानी 31 मार्च 2016 तक कम राशि मिलेगी. चालू वित्त वर्ष में केंद्र ने केंद्रीय करों से राज्यों को 5.20 लाख करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया था, लेकिन बजट के संशोधित अनुमानों से इसे घटाकर 5.06 लाख करोड़ कर दिया गया. यह 14 हजार करोड़ रुपये कम है. बिहार को केंद्रीय करों से 50 हजार करोड़ मिलने का अनुमान था जबकि संशोधित बजट के बाद यह राशि कम होकर 48661 करोड़ रुपये रह गई है. इस तरह राज्य को 1339 करोड़ रुपये कम मिलेंगे. सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बजट से बेहद निराश हैं. नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री ने एक चुनावी सभा में बोली लगाई थी. पचास हजार करोड़ दें या साठ हजार करोड़ या सत्तर हजार करोड़ दें, लो एक लाख 25 हजार करोड़ दिया. इसका क्या हुआ कहीं बजट में जिक्र नहीं है. बीआरजीएफ के रास्ते से बिहार को विशेष सहायता का जिक्र था की 8300 करोड़ रुपये बिहार को मिलेगा इसका भी बजट में उल्लेख नहीं है. बीआरजीएफ एनेक्सचर से गायब है. इनको बात करने की आदत है, जैसे रेल बजट में कुछ नहीं वैसे ही आम बजट में भी कुछ नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा की बजट में बार–बार किसानों की बात की गई है. वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात की गई है. इकोनॉमिक सर्वे में किसानों की आमदनी बहुत कम दिखी है. अगर यह आमदनी पांच साल के अंदर दोगुनी भी हो जाती है, तब भी कोई फर्क नही पड़ने वाला है. मुद्रा स्फीति के कारण रुपये की कीमत गिरने से किसानों की माली हालत खराब ही होगी. दो साल पहले केंद्र सरकार ने किसानों की लागत में 50 प्रतिशत जोड़ कर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात की थी वह वादा आज तक अधूरा है. नीतीश कहते हैं कि बजट में बिहार के साथ केंद्र का भेदभाव साफ दिख रहा है. पीएमजीएसवाई में सर्वाधिक आवंटन का दावा किया गया, लेकिन अब इसमें केंद्र 60 प्रतिशत राशि देगा और 40 प्रतिशत राशि राज्य लगाएंगे. इससे राज्यों का कौन सा कल्याण होगा?

मुख्यमंत्री का आरोप है कि इस बजट से आम लोगों को नहीं सिर्फ कालाधन रखने वालों को फायदा होगा. लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि कालाधन लाएंगे गरीबों के खाते में पंद्रह से बीस लाख रुपये मिल जाएंगे. बजट में कालाधन वाले लोगों के लिए एमनेस्टी स्कीम चला दी गई है. कालाधन को वैध बनाने के लिए मात्र 45 प्रतिशत राशि जमा करना होगा बची हुई 55 प्रतिशत राशि लेकर वे मौज करेंगे. दूसरी तरफ लालू प्रसाद भी बजट को लेकर बेहद गरम हैं. लालू प्रसाद कहते हैं कि अरुण जेटली ने वित्तीय वर्ष 2016–17 की जगह 2022 का बजट पेश कर दिया. वह कह रहे हैं की 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे. अभी किसानों की आय कितनी है इसका कोई सर्वे कराए हैं क्या? किसानों को उपज का सही मूल्य देंगे. अभी तो फसल खरीद समय पर करते ही नहीं है. आम बजट चलाकी से बनाया गया दस्तावेज है यह हाथी के दांत के समान है. उन्होंने मान लिया है कि 2019 के आम चुनाव में जीतेंगे तभी रेल बजट में 2020 तक सबको कंफर्म टिकट और 2022 में किसानों की आय दोगुना करने की घोषणा कर रहे हैं.

लालू प्रसाद ने जनधन का खाता खुलवाने वाले लोगों से कहा कि ऊपर से सेटिंग हो गया अब कुच्छो नहीं मिलने वाला है.

इकोनॉमिक सर्वे में किसानों की आमदनी बहुत कम दिखी है. अगर यह आमदनी पांच साल के अंदर दोगुनी हो जाती है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुद्रा स्फीति के कारण रुपये की कीमत गिरने से किसानों की माली हालत खराब ही होगी. दो साल पहले केंद्र सरकार ने किसानों की लागत में 50 प्रतिशत जोड़ कर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात कही थी, वह वादा आज तक अधूरा है.

हालांकि सुशील मोदी केंद्रीय बजट का जमकर बचाव कर रहे हैं. सुशील मोदी कहते हैं कि वित्त मंत्री ने हर परिवार को 1 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, डेढ़ करोड़ बीपीएल परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन और तीन साल में 6 करोड़ परिवारों को कम्प्यूटर साक्षर बनाने की घोषणा की है. देशभर में 1500 बहु कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जिससे पटना साहिब का विकास होगा. प्रत्येक स्थानीय निकाय के लिए औसतन 21 करोड़ व पंचायतों को 80 करोड़ देने की घोषणा कर गांवों के विकास पर अधिक जोर दिया गया है. राष्ट्रीय उच्चपथों के लिए 55 हजार करोड़ दिए गए हैं, मुद्रा बैंक के लिए 1 लाख 80 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है. इन सबका सबसे ज्यादा लाभ बिहार के युवाओं को मिलेगा. लेकिन बजट प्रावधानों पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि बजट में किस तरह बिहार के हितों की अनदेखी की गई है. सड़क और परिवहन के मामले में केंद्र सरकार ने बजट में बिहार की उपेक्षा की है. बजट में राज्य के लिए इस क्षेत्र में कोई नई योजना मंजूर नहीं की गई है. यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित सवा लाख करोड़ के पैकेज में पहले से चल रही जिन योजनाओं की चर्चा थी उनकी भी गति तेज करने का कोई प्रयास नहीं दिखा. नरेन्द्र मोदी ने पटना–आरा–बक्सर फोरलेन का शिलान्यास किया था, लेकिन अब तक एक किलोमीटर सड़क का भी निर्माण नहीं हो सका. पैकेज की घोषणा के बाद बिहार के लिए एनएचआई को कोई पैसा नहीं मिला है. राज्य को उम्मीद थी बजट में पटना में गंगा पर गांधी सेतु के समानांतर चार लेन का पुल बनाने की घोषणा की जाएगी. यह पीएम के पैकेज में भी शामिल था, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं है. इतना ही नहीं गांधी सेतु का सुपर स्ट्रक्चर बदलने के लिए भी राशि नहीं दी गई है.

केंद्र सरकार इसके लिए पैसा देने की घोषणा पहले ही कर चुकी थी. केंद्र को 2800 करोड़ देने थे और इसी पैसे से गांधी सेतु का कंपोजिट सुपर स्ट्रक्चर तैयार करना था. लेकिन बजट के बाद उम्मीद पर पानी फिर गया. हालांकि यह योजना अभी पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड में है, वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही कोई कार्यवाही होगी. इसी तरह बिरपुर–बिहपुर के एनएच 106 पर फुलौत के पास कोसी पर महासेतु बनाने की योजना केंद्र के पास लंबित है. इस योजना की भी बजट में कोइ चर्चा नहीं की गई है. बजट में कोई नई सड़क नहीं दी गई है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा पटना की सड़कों पर बैट्री वाली बस चलने और गंगा सहित सभी नदियों में जल परिवहन शुरू करने की योजना खटाई में पड़ गई है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार कहते हैं कि आम बजट में इंदिरा आवास और जीविका जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है. बिहार जैसे राज्य में 75 से 90 लाख लोग बिना घर के हैं, इसके लिए बिहार को फोकस कर विशेष योजना बनाई जानी चाहिए थी. मगर बजट में इसका कोई जिक्र नहीं है. जीविका के मद का हमारा 40 करोड़ अब भी केंद्र के पास बकाया है इससे महिलाओं और गरीबों से जुड़ी जीविका योजना प्रभावित हो रही है. उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास के लिए इस बार 19 हजार करोड़ का प्रावधान है. मगर इसमें 9 हजार करोड़ तो बिहार का ही केंद्र सरकार पर बकाया है. श्री कुमार ने कहा कि केंद्र से राशि नहीं मिलने से डीआरडीए का कार्य भी प्रभावित हो रहा है. मजदूरों को भुगतान करने में दिक्कत आ रही है. इसी तरह आम बजट में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को न के बराबर मिला है. राज्य सरकार के शिक्षा महकमे में बजट के विश्लेषण के बाद जानकारों ने बताया की बहुत उम्मीद थी लेकिन निराशा ही मिली. उच्च शिक्षा में 20 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव है, लेकिन इनमें बिहार को एक भी नहीं मिलेगा. अलबत्ता चंद नवोदय स्कूल और कुछ कौशल विकास केंद्र ही मिलेंगे. इस तरह देखा जाए, तो केंद्र का आम बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के साथ किए गए वादे पर ही सवाल उठा रहा है. बजट के बाद बिहार के कई मंत्री और सांसदों ने रेल मंत्री से मुलकात कर बिहार की हुई उपेक्षा पर उनका ध्यान दिलाया है. देखना है केंद्र सरकार खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को किए अपने वादे पर कितना खरा उतरते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

केंद्रीय बजट

पश्चिम बंगाल और असम के लोग नाखुश, सरकार और पार्टियों ने भी निंदा की

बांगाली मानुषेर विरोधी आछे एई बजट

कृष्ण कुमार शाह

पश्चिम बंगाल के लोगों का मानना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साल 2016–17 का जो बजट पेश किया है उसने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. जेटली के इस बजट की पश्चिम बंगाल की जनता और राजनीतिक दलों ने तीखी निंदा की है. केंद्र सरकार ने पांच राज्यों में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया है, लेकिन लोग कहते हैं कि इस बजट में पश्चिम बंगाल और असम के लिए कुछ भी खास नहीं है, जिसका चुनाव पर कोई असर पड़ेगा.

उत्तर भारत में असम और बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन राज्यों में भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है. बंगाल में वाम दलों के बाद तृणमूल जैसी क्षेत्रीय पार्टी और असम में अधिकतर कांग्रेस का ही बोलबाला रहा है. बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा कि इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है. गोगोई टैक्स देने वालों पर और बोझ लादे जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि केंद्रीय बजट में विजन का अभाव साफ दिख रहा है. यह आम लोगों के हित में नहीं है. पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए तो ये किसी काम का नहीं है. केंद्रीय बजट को पश्चिम बंगाल सरकार दिशाहीन और निराशाजनक बता रही है. राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने बजट के बहाने नरेंद्र मोदी सरकार की एफडीआई (विदेशी पूंजी निवेश) नीति की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाया और कहा कि यह पूरी तरह लक्ष्यहीन है. प्रदेश के पंचायत मंत्री सुव्रत मुखर्जी ने कहा कि केंद्रीय बजट में दृष्टि का अभाव है. इसमें आम लोगों और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए कुछ भी नहीं है. इस बजट से पश्चिम बंगाल को कुछ भी नहीं मिला है. जानबूझ कर राज्य को वंचित रखा गया है. बजट में कोयले की कीमत में वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है. कोयले की कीमत बढ़ने से बिजली एवं अन्य जरूरी सामग्रियों की कीमत भी बढ़ेगी.

पश्चिम बंगाल सरकार के कुछ अन्य मंत्रियों का भी कहना था कि केंद्र सरकार ने राज्यों के ही कुछ फार्मूलों की नकल की है. केंद्रीय बजट में इस साल घर खरीदने के बारे में सोचने वालों के लिए विशेष सुविधा का ऐलान किया गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम कहते हैं कि यह सुविधा पश्चिम बंगाल के लोगों को देने के बारे में राज्य सरकार पहले ही फैसला कर चुकी है. इसके अलावा, राज्य सरकार केंद्र से पहले ही चिटफंड के खिलाफ बिल लेकर आई है. केंद्र में यह बिल लंबे वक्त से लटका था जिसे अब स्वीकृति मिली है. लेकिन हमारा बिल पहले पूरा हुआ. यह ममता बनर्जी की योजना थी. इसलिए हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार हमारी ही राह पर चल रही है. यह हमारे लिए गर्व की बात है कि केंद्र हमारी दिखाई राह पर चल रहा है.

कोलकाता की सड़कों पर आम लोगों से बातें करते हुए जो राय सामने आई उससे भी साफ प्रतीत हुआ कि केंद्रीय बजट आम लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. बेहला के रहने वाले आशुतोष रॉयचौधुरी बांग्ला में कहते हैं –बांगाली मानुषेर विरोधी आछे एई बजट, आमरा तो किच्छु पाए नी– यानी केंद्रीय बजट आम बंगाली नागरिकों के खिलाफ है. हम बंगालियों को तो इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ. इसी तरह की मिली जुली राय अन्य बंगाली मध्यवर्गीय लोगों की भी थी. चाहे वे उल्टाडांगा के जीवानंद भट्टाचार्य रहे हों, या टॉलीगंज के बुजुर्ग फणीभूषण मजूमदार. इक्का–दुक्का ऐसे लोग भी मिले जो केंद्रीय बजट की प्रशंसा कर रहे थे. गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के महासचिव रोशन गिरी ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि बजट से साफ जाहिर है कि भाजपा सरकार ग्रामीण अर्थ (रूरल इकोनॉमी) को प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अगले एक साल में एक करोड़ युवाओं में इंटरप्रेन्योर स्किल्स डेवलप करने के मोदी सरकार के कदम की सराहना की. गिरी कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट सेंटरों के जरिए युवाओं के कौशल में सुधार होगा जिससे देश की बेरोजगारी की समस्या दूर करने में काफी मदद मिलेगी.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पॉलित ब्यूरो ने बजट पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में न तो विकास की दृष्टि है और न ही इसमें लोगों के हित को ध्यान में रखा गया है. इस बजट से असमानता, बेरोजगारी व कंट्रैक्ट निर्यात बढ़ेगा. इससे कृषि के क्षेत्र में तकलीफ बढ़ेगी. बजट में पब्लिक सेक्टर के विनिवेश के जरिये 56500 करोड़ रुपये उगाहने की बात कही गई है. पर, बीमा व खाद्य क्षेत्र में विनिवेशीकरण का बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा इससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी अस्थिर होगी. दूसरी तरफ प्रदेश भाजपा ने स्वाभाविक तौर पर केंद्रीय बजट की प्रशंसा की और इसे विकासोन्मुखी बताया. पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा के आर्थिक सेल के संयोजक डॉ. धनपत राम अग्रवाल ने कहा है कि यह बजट अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा जो कि विश्व में सबसे तेज गति यानी 7.6 फीसदी की दर से विकास कर रही है. भारत को स्थिरता के लिए विश्व भर में जाना जा रहा है. बजट प्रस्ताव से नए रोजगार का सृजन होगा और मझोले व छोटे उद्यम को और ऋण मिल सकेगा. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि और आधारभूत ढांचे के लिए अतिरिक्त आवंटन मंजूर किया है. इससे सामग्रिक विकास हो सकेगा. वित्तीय घाटा भी नियंत्रण में है. काले धन की रोकथाम के लिए उपाय अपनाए गए हैं. जबकि पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने केंद्रीय बजट को देश के संघीय ढांचे का विरोधी बजट बताया है. प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक डॉ. मानस रंजन भुईंया ने केंद्रीय बजट को संविधान का संघीय ढांचा विरोधी करार दिया और कहा कि इसके पहले वर्ष के बजट में जेटली ने कहा था कि वह कॉऑपरेटिव फेडरलिज्म के पक्षपाती हैं, लेकिन बजट में साफ है कि यह पूरी तरह से केंद्रीय बजट है. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र की भागीदारी 100 फीसदी होती थी, लेकिन बजट में इसे घटा कर 60 फीसदी कर दिया गया है. अब राज्य में 40 फीसदी अधिक भार पड़ेगा. इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री ने मनरेगा के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की है, लेकिन यह राशि तो वेतन मद में ही खर्च हो जाएगी. केंद्र सरकार ने राज्यों की 25 योजनाओं को बंद कर दिया है, जिसका भार अब राज्यों को ही वहन करना पड़ रहा है. मानस भुईंया ने कहा कि केंद्रीय बजट किसान व गरीब विरोधी और उद्योगपतियों के हित का बजट है. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 15 हजार करोड़ रुपये किसानों के ऋण को माफ कर दिया है, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने बजट में 72 हजार करोड़ रुपये किसानों के कर्ज माफ किए थे. असम के सांसद और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता बदरुद्दीन अजमल ने बजट को निराशाजनक बताया और कहा कि इसमें खेती और किसानों के लिए बड़े–बड़े आइडिया तो हैं लेकिन सवाल यह है कि सरकार उन पर अमल कैसे करेगी. वित्त मंत्री ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात तो कह दी लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि 2019 के बाद वो अपने लंबे–लंबे वादों को कैसे पूरा करते हैं. मनरेगा और आधार जैसी यूपीए की तमाम योजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी अक्सर मजाक उड़ाते रहे हैं, लेकिन बजट में उन्हीं योजनाओं पर खासा ध्यान दिया गया है. भाजपा ने यूपीए की बहुत सी योजनाओं को अपनाया है. साफ है कि यूपीए की योजनाओं को अपनी प्लेट में परोसना मोदी सरकार के काम करने का तरीका बनता जा रहा है. इस बजट में सबसे अफसोसजनक है कि इसमें डिफेंस और एजुकेशन को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है. इस बजट से साफ होता है कि संप्रदाय के आधार पर समाज को बांटने वाली केंद्र सरकार आम आदमी से अपनी पकड़ खोती जा रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

यूपी के मध्य वर्ग और किसानों पर आई केंद्रीय बजट की आपदा

बल्ले-बल्ले की जगह छल्ले-छल्ले

प्रभात रंजन दीन

केंद्रीय बजट के संसद में पेश होने के कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश के बरेली में रैली थी. रैली का नाम दिया गया था किसान कल्याण रैली. यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव होने वाला है. लिहाजा, प्रधानमंत्री की बड़ी-बड़ी बातें सुन कर किसानों को लगा कि इस बार के बजट में तो यूपी की बल्ले-बल्ले जरूर होगी. रैली में किसान सबसे अधिक संख्या में मौजूद थे. मोदी ने किसानों के हित की बातें भी खूब कीं, लेकिन बजट के बाद किसानों को समझ में आया कि वो सारी बातें बेमानी थीं, जमीनी सच्चाई कुछ और ही निकली. यूपी की बल्ले-बल्ले के बजाय छल्ले-छल्ले हो गई. बरेली के किसान कहते हैं कि मोदी सबके चेहरे पर सूरमा पोत गए और बाजार में जो झुमका गिरा था उसे भी झपट कर दिल्ली ले गए. लोग कहते हैं कि इस बजट से किसान और मध्य वर्ग का कलेजा छलनी हो गया है.

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपया चीनी मिलों के पास बकाया है, लेकिन बजट में उसकी भरपाई का कोई प्रावधान नहीं रखा गया. चीनी मिल मालिकों को केंद्र और राज्य सरकार दोनों तरफ से राहत और रियायतें मिलती जा रही हैं, लेकिन गन्ना किसानों को उनके बकाये का भुगतान हो उसके लिए कोई ठोस बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है. दोनों सरकारें आंकड़ों में सफेद झूठ परोस रही हैं. मोदी ने बरेली की रैली में किसानों को श्रम का देवता बताया और कहा कि उनकी चिंता किसानों को पैसा पहुंचाना ही नहीं है बल्कि उन्हें हर तरह से सशक्त करना है. प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य पर एक बुजुर्ग किसान ने पूछा कि किसान श्रम के देवता हैं तो सरकार राक्षस पूंजीपतियों की ही पूजा क्यों करती है? किसानों का बकाया दिलवाने के लिए मिल मालिकों पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करती? किसान अगर श्रम देवता हैं तो प्राकृतिक आपदा से मरने वाले श्रम देवताओं को 60-70 रुपये का चेक देकर किस तरह की राहत दी जाती है और श्रम देवताओं का किस तरह ख्याल रखा जाता है? श्रम देवताओं के लिए यह सम्मान है या अपमान? क्या इसी तरह किसानों की आय दोगुनी की जाएगी? किसानों के इन सवालों का जवाब न केंद्र सरकार के पास है और न राज्य सरकार के पास. केंद्रीय बजट में फसल बीमा का प्रावधान किए जाने पर तकरीबन सारे किसानों का कहना था कि यह प्रावधान बीमा कंपनियों के फायदे के लिए किया गया है न कि किसानों के लिए.

उन्हें पसंद है भारत के विद्रूप का गीत

केंद्र सरकार का बजट देख कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मशहूर पॉप गायिका बेयोंसे नोल्स का गाना हिम फॉर द वीकेंड' सुनना अधिक पसंद आ रहा था. बेयोंसे नोल्स के इस गाने में भारत के विद्रूप को परोसा गया है. बजट पर चहकते (ट्वीट करते) हुए अखिलेश ने यह बात लिखी. लेकिन भारत को विद्रूप बनाने में उनकी और अन्य राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, इसकी ईमानदार स्वीकृति देने से परहेज कर गए. अखिलेश ने अपने ट्वीट में कहा था कि केंद्रीय बजट में वही पुराना गाना बज रहा है, इससे बेहतर है हिम फॉर द वीकेंड' सुनना.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान कल्याण रैली के बाद आए केंद्रीय बजट को ध्यान से देखें तो केंद्र का बजट राज्य को नुकसान पहुंचाने वाला बजट दिखाई पड़ेगा. आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय बजट से यूपी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा. 2016-17 के बजट में 2015-16 का बजट पुनरीक्षित किया गया है, जिससे चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय करों में प्रदेश की हिस्सेदारी 3340 करोड़ रुपये कम हो गई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों जो प्रदेश का बजट पेश किया था, केंद्रीय बजट उस पर भी असर डालेगा. विशेषज्ञ कहते हैं कि केंद्र ने 2015-16 के बजट में केंद्रीय करों से प्रदेश की हिस्सेदारी 94,313 करोड़ रुपये तय की थी, लेकिन 2016-17 के बजट के साथ केंद्र ने 2015-16 का बजट पुनरीक्षित कर दिया है. इससे यूपी की हिस्सेदारी 94,313 करोड़ रुपये से घटकर 90,973 करोड़ रुपये रह गई है. इसके अलावा केंद्र ने 2016-17 में यूपी का आवंटन 1,02,650 करोड़ करने की बात कही है जो 2015-16 के मूल बजट से मात्र 1.84 फीसदी ज्यादा है. राज्य सरकार केंद्र के मूल आवंटन से 10-11 प्रतिशत की वृद्धि मान कर ही अपना अगला बजट बनाती है. लिहाजा, अब केंद्र से आवंटन में कमी हो जाने से प्रदेश के बजट अनुमानों पर असर पड़ना तय है. ऐसे में केंद्र द्वारा पुनरीक्षित बजट के आधार पर राज्य सरकार को भी अपने वर्ष 2016-17 के बजट में अपेक्षित फेरबदल करना पड़ सकता है.

बजटीय प्रावधानों के मुताबिक दलहनी फसलों के बीजों पर ज्यादा अनुदान मिलने से इसका रकबा बढ़ाने में मदद मिल सकती है. अभी इन बीजों पर केंद्र सरकार 2500 रुपये प्रति क्विंटल और राज्य सरकार 800 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देती है. लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत यह है कि गन्ना की तरह दलहनी फसलों का भी रकबा लगातार कम होता जा रहा है. सबसे ज्यादा दलहनी फसलें बुंदेलखंड में बोई जाती हैं. लेकिन सूखे के कारण वहां के 50 फीसदी रकबे में बोआई ही नहीं हुई. मौसम और बीमारी की मार के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र में भी किसान दलहनी फसलों की खेती में रुचि नहीं ले रहे हैं. किसानों का कहना है कि फसलें खराब हो जाने पर सरकार से उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता. मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ मजाक किया जाता है. जिन किसानों की फसलें बीमाकृत हैं, उन्हें भी फसल बर्बाद होने पर कोई भुगतान नहीं मिलता. सब बीमा कंपनियों की चोंचलेबाजी है और उनमें सरकार की मिलीभगत है. 2014 में 2.33 करोड़ किसानों में से 7.36 लाख का ही खरीफ फसल का बीमा हुआ था, लेकिन उसका लाभ केवल 3.23 लाख किसानों को ही मिला. बीमा होने के बावजूद सवा चार लाख किसानों को फसलों की बर्बादी का मुआवजा बीमा कंपनियों से नहीं मिला. इसके लिए न सरकार ने कोई कार्रवाई की और न प्रशासन तंत्र ने किसानों की कोई सुध ली.

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बजट से किसानों को घोर निराशा हाथ लगी है. पूर्व के वर्षों की तरह इस बार भी आंकड़ों की बाजीगरी की गई. इस बजट में किसान के नाम पर बीमा कम्पनियों और दूसरे उद्योगों को लाभ देने का प्रयास किया गया है. इससे किसानों की आत्महत्याएं रुकने के बजाय इसमें इजाफा होने का ही अंदेशा है. टिकैत ने कहा कि 2014-15 में कृषि क्षेत्र को 32 हजार करोड़ का आवंटन किया गया था. भाजपा सरकार ने 2015-16 में इसे घटाकर 25 हजार करोड़ कर दिया. फिर 2016-17 में इसे 36 हजार करोड़ रुपये कर दिया और उसका ढिंढोरा पीट रही है. लेकिन असलियत में चार हजार करोड़ रुपये ही तो बढ़ाए. कृषि क्षेत्र को महज चार हजार करोड़ दिए जाने से क्या अच्छे दिन आ सकते हैं? किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने भी कहा कि बजट आंकड़ों की बाजीगरी के अलावा कुछ भी नहीं है. यह बजट कॉरपोरेट हाउसों को ध्यान में रख कर बनाया गया है. बजट में महंगाई रोकने का कोई उपाय नहीं किया गया है. पिछले तीन वर्षों में किसानों की फसलें दैवीय आपदा के कारण तबाह हो रही हैं. लेकिन उन्हें राहत देने का कोई प्रावधान बजट में नहीं है. बजट में मनरेगा के तहत सिंचाई के लिए पांच लाख कुओं का निर्माण कराने का प्रावधान किया गया है, जबकि कुओं से सिंचाई की पद्धति 18वीं सदी की है जिसे वर्तमान सरकार 21वीं सदी में लागू कराना चाहती है. भूजल लगातार नीचे जा रहा है, ऐसे में कुओं में पानी कहां से आएगा, इसकी किसी को चिंता नहीं. यह धन के अपव्यय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है. दीक्षित ने कहा कि प्रदेश के किसानों को नए बजट से बहुत उम्मीदें थी लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी. राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान और रालोद के वरिष्ठ नेता अनिल दुबे ने कहा कि केंद्रीय बजट का बोझ किसानों और मध्य वर्ग की कमर तोड़ कर रख देगा. महंगाई में बेतहाशा वृद्धि होगी. फसलों की लागत वापस होने तक पर आफत रहेगी. किसान मरेगा और नए-नए करों का भार सर्विस क्लास और मध्यम श्रेणी के लोगों का जीवन दुभर कर देगा. रालोद नेताओं ने कहा कि केंद्रीय बजट केवल पूंजीपतियों के फायदे के लिए है. ■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड : भाजपा के सांगठनिक चुनाव में जूतम-पैजार

सवा साल में हाल बेहाल

मीरा पटेल

नरेंद्र मोदी की लहर के सहारे झारखंड में भी भाजपा की सरकार जरूर बन गई, लेकिन सवा वर्ष में ही इसकी इतनी फजीहत होगी, कोई नहीं जानता था. सरकार को फेल होने का प्रमाण पत्र लोहरदगा में हुए उपचुनाव में जनता ने दे ही दिया था, अब सांगठनिक चुनाव में लाठी-डंडे चल रहे हैं.

खोजे नहीं मिल रहे सक्रिय कार्यकर्ता

भारतीय जनता पार्टी ने मोबाइल पर मिस्ड कॉल के माध्यम से लाखों कार्यकर्ता झारखंड में बनाने का दावा जरूर किया, लेकिन इनको सक्रिय कार्यकर्ता में तब्दील नहीं किया जा सका. लक्ष्य रखा गया कि हर मंडल में कम से कम सौ सक्रिय कार्यकर्ता हों. जब संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो पता चला कि बमुश्किल 10 मंडल में ही इतने सक्रिय कार्यकर्ता होंगे. संथाल परगना के जिलों में तो इसी कारण चुनाव की प्रक्रिया ही रुक गई है. रांची के पास सिकिदरी मंडल की बात करें तो यहां पांच सक्रिय कार्यकर्ता हैं. नरकोपी में 11 हैं. चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधितकर मंडलों में कोरम ही पूरा नहीं हो पा रहा है. पहले प्रदेश भर में 344 मंडल थे. इसे बढ़ाकर 514 कर दिया गया. जिन मंडलों में चुनाव हो भी गया है, वहां कार्यसमिति का विस्तार रुका पड़ा है. क्योंकि सक्रिय सदस्य ही नहीं रहेंगे तो कार्यसमिति में कैसे शामिल किए जाएंगे.

जिलाध्यक्ष के चुनाव में चल रहे लाठी-डंडे

झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के 26 सांगठनिक जिले थे. इन्हें बढ़ाकर अब 29 कर दिया गया है. जिलाध्यक्ष के चुनाव में तू-तू-मैं-मैं इतनी है कि अभी तक 20 जिलों में भी अध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया जा सका है. जहां हुआ है, वहां विवाद हावी रहा. जमशेदपुर में लाठी-डंडे चले. धनबाद में भी यही स्थिति रही. राजधानी रांची में महानगर व ग्रामीण दोनों जिलाध्यक्षों के चुनाव में भारी विरोध हुआ. प्रदेश मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन तक हुआ. झामुमो का गढ़ तोड़ने के लिए संथाल परगना पर भाजपा का ज्यादा फोकस है. इसके मुख्यालय दुमका में कैबिनेट की बैठक भी

हो चुकी है, लेकिन इस प्रमंडल के किसी जिले में संगठन का चुनाव नहीं हो सका है.

प्रदेश अध्यक्ष का भी कार्यकाल पूरा

अब तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए था. फरवरी में ही मौजूदा अध्यक्ष डॉ. रवींद्र राय का तीन साल पूरा हो गया था, लेकिन जिलों का चुनाव हुए बिना यह कैसे हो सकता है. चर्चा है कि शायद मनोनयन की तैयारी है. चुनाव में ज्यादा संभावना है कि केंद्रीय नेतृत्व के मन का अध्यक्ष न बन सके. हालांकि यह भी संकेत मिला कि भाजपा आलाकमान ने झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख गणेश मिश्र पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष होने पर अपनी सहमति दे दी है. 29 फरवरी को इसकी आधिकारिक घोषणा किए जाने की संभावित तारीख भी चर्चा में थी. लेकिन घोषणा नहीं हुई. पहले कहा जा रहा था कि चूंकी गैर आदिवासी रघुवर दास झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं तो संगठन की जिम्मेवारी किसी आदिवासी को सौंपी जाए. इस पर केंद्रीय नेतृत्व में काफी गहन मंथन भी हुआ, लेकिन इस मंथन का कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया. इस कवायद में आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों समुदायों के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत भी की गई. लेकिन आखिरकार प्रदेश संगठन की कमान गणेश मिश्र को सौंपने का ही मन बना लिया गया. अमित शाह के दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह तय हुआ था कि उनकी सहमति से प्रदेश अध्यक्ष का मनोनयन किया जाएगा. इस पद के लिए गणेश मिश्र व सांसद लक्ष्मण गिलुआ का नाम सबसे ऊपर था. वहीं मनोज कुमार मिश्र को रांची महानगर अध्यक्ष चुना गया है.

सरकार व संगठन में मनभेद

अभी तक निगम व खाली पड़े आयोगों के पदों पर मनोनयन नहीं हो सका है. सरकार में एक जाति विशेष के वर्चस्व से भी समर्पित व पुराने कार्यकर्ता विदक रहे हैं. पूर्व लोकसभा अध्यक्ष व खूंटी के सांसद कड़िया मुंडा तो कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि झारखंड सरकार का कामकाज ठीक नहीं है.

गोड्डा में होगी अग्निपरीक्षा

गोड्डा में विधायक रघुनंदन मंडल के निधन के बाद वहां उपचुनाव शीघ्र ही होना है. मंडल नरेंद्र मोदी लहर के सहारे विधानसभा तक पहुंच गए थे. गोड्डा संथाल परगना प्रमंडल में ही आता है. अभी जो स्थिति है, इस सीट को बचा पाना भाजपा के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी. क्योंकि इस समय कोई लहर नहीं है, जिसके सहारे नैया किनारे तक लगे. संगठन भी नहीं है, जिसकी बदौलत चुनाव में सफलता हासिल हो सके. सरकार के कामकाज को यदि मानक माना जाए तो राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ऐसा कोई काम इस सवा साल में नहीं हुआ, जिससे सरकार की लोकप्रियता जनता में बढ़ी हो. अन्य पार्टियां भी भाजपा से इस सीट को छीनने के लिए तलवार पर धार दे रही हैं. एक बात यह भी सच है कि भाजपा को दूसरों से कम, अपनों से ही ज्यादा खतरा है, क्योंकि निहायत अनुशासित कही जाने वाली इस पार्टी में सांगठनिक चुनाव में ही सिरफुटौव्वल हो रहा है. प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ धरना-प्रदर्शन हो रहा हो और सबसे बड़ी बात यह है कि वरीय नेता सरकार के खिलाफ बोलने लगे हों तो स्थिति क्या होगी, अंदाज लगाया जा सकता है. चुनाव में सबक सिखाने के लिए असंतुष्ट कार्यकर्ता तैयार हैं.

सवा साल में स्थानीय नीति तक नहीं बन सकी

रघुवर सरकार बनी थी, तो सीएम ने कहा था कि राज्य की स्थानीय नीति तीन माह में बन जाएगी, लेकिन सवा साल होने वाले हैं, यह नहीं हो सका. इसके चलते पार्टी में ही आदिवासी विधायकों व मंत्रियों का मूक विरोध सरकार को झेलना पड़ रहा है. अन्य मुद्दों पर भी भाजपा की यह सरकार पुरानी सरकारों से अलग नहीं दिखाई दे रही है. राजधानी में ही प्रतिदिन हत्या, लूट, अपहरण, चोरी की घटनाएं हो रही हैं. महिला हिंसा पर भी कोई रोक नहीं लग सकी है. सिंचित जमीन का रकबा एक इंच भी नहीं बढ़ सका है. सड़कें जस की तस हैं. सिर्फ एनएच 33 को छोड़कर आज भी कोई एनएच 24 घंटे नहीं चलता.

अन्य पार्टियों के मृतप्राय होने का फायदा भाजपा को

कांग्रेस भले ही लोहरदगा उपचुनाव में जीत गई, लेकिन विधानसभा का आम चुनाव हुए सवा साल हो गया, अभी तक यह पार्टी जनमुद्दों को लेकर इस तरह से आगे नहीं आई है, जिससे जनता को इसमें विकल्प नजर आए. आजसू सरकार में ही शामिल है. बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा (प्र) के छह विधायकों को चुनाव के तुरंत बाद तोड़कर अपने पाले में शामिल कराने में भाजपा को सफलता मिल गई थी. एकमात्र प्रदीप यादव की आवाज नक्कारखाने में तूती की आवाज ही साबित होती है. बाबूलाल खुद विधानसभा चुनाव हार गए थे, सो उनकी बातों में वह आत्मविश्वास नहीं झलकता. वामपंथी पार्टियों में इतना दम नहीं है कि वह भाजपा को चुनौती दे सकें. लिहाजा भाजपा ही अजगर बनी हुई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

पद की मर्यादा समझें मोदी

न्याय पालिका ने जिस तरीके से नेशनल ज्यूडिशियल अप्वायंटमेंट कमीशन को लेकर टिप्पणी की, वह लोकतंत्र के लिए ग़लत है. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट नेताओं को आपस में जिस तरीके से लड़ते हुए देखता है, उसके मद्देनज़र ऐसी टिप्पणी स्वाभाविक है. संसद में सबको अपने बीच एक सहमति, एक समझ बनानी चाहिए. संसद को ही सर्वोच्च होना चाहिए. दुनिया में कहीं भी जज खुद जज को नियुक्त नहीं करता. इसके लिए संसद से बना एक क़ानून होना ही चाहिए. मैं न्याय पालिका से जुड़े किसी अन्य मसले पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर विधायिका स्पष्ट रूप से अपनी और न्याय पालिका की ताकत के बीच एक लाइन नहीं खींचती है, तो यह देश के भविष्य के लिए सही नहीं होगा.

बीते 29 फरवरी को बहुप्रतीक्षित केंद्रीय बजट पेश कर दिया गया, जिसमें ध्यान देने वाली तीन बातें हैं. पहला बजट भाषण एवं उसके अंतर्निहित मायने. दूसरा, विभिन्न मदों के लिए आवंटित धनराशि. तीसरा, आंकड़े पुनर्व्यवस्थित करना, ताकि एक ही तरह के आवंटन को दूसरा स्वरूप दिया जा सके. पहले बजट भाषण पर एक नज़र डालते हैं, जो यह जताने की आक्रामक कोशिश कर रहा है कि सरकार अब गांवों-ग़रीबों के लिए काम करने जा रही है. 1991 के बाद के सारे बजट कॉरपोरेट सेक्टर को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए, जिनमें से कुछ बजट पूरी तरह कॉरपोरेट केंद्रित थे, कुछ संतुलन बनाने की कोशिश करते दिख रहे थे, लेकिन ज़ोर हमेशा कॉरपोरेट सेक्टर पर रहा. कृषि क्षेत्र की शिकायत रही है कि यूपीए के दस वर्षों और मौजूदा सरकार के दो वर्षों में उस पर ध्यान नहीं दिया गया. इस क्षेत्र में प्रभावी निवेश नहीं हो सका. यह बजट भाषण इस भाव को मिटाने की कोशिश करता नज़र आया. और, इसने यह ज़ाहिर करने की कोशिश की कि कृषि क्षेत्र में बड़ा निवेश होने जा रहा है. यह बात पूरी तरह सत्य नहीं है. वास्तविक आवंटन ज़रूर बढ़ गया है, लेकिन यह वृद्धि उतनी नहीं है, जितने की ज़रूरत है. इसमें कुछ ऐसी बातों एवं योजनाओं का भी जिक्र है, जो पहले से चलती आ रही हैं यानी इस भाषण में पुरानी बातें भी दोहराई गई हैं. खास तौर पर फसल बीमा वगैरह. आंकड़ों की पुनर्व्यवस्था, जिसमें 15,000 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता शामिल है, जो पहले बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र के लिए थी, अब कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित कर दी गई है. यह एक छलावा भर है. इससे कोई प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि कृषि क्षेत्र को कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जा रही है. इस पूरे मामले में दिलचस्प मोड़ यह है कि सरकार इस तरह की चर्चा को जन्म देने की कोशिश क्यों कर रही है? बिहार चुनाव के बाद उसे लगा कि केवल विदेशी निवेश, मेक इन इंडिया आदि की बात करने से काम नहीं चलने वाला, बल्कि इसके साथ-साथ कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान देना होगा. इस सीमा तक तो यह बात ठीक है.

अगर पुरानी परंपराओं को देखा जाए, तो ऐसे बजट, जिन्हें वित्त मंत्री लोक लुभावन नहीं मानते, लेकिन वे होते लोक लुभावन हैं, आम तौर पर चुनावी वर्ष में पेश किए जाते हैं. चुनाव से तीन वर्ष पहले ऐसा बजट पेश करना ज़ाहिर करता है कि कहीं न कहीं पार्टी में यह डर पैदा हुआ है कि जिस तरीके से दो वर्षों तक काम हुआ, अगर आगे भी उसी तरह होता रहा, तो 2019 उसके लिए अच्छा साबित नहीं होगा. राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री काफी नरम दिखे, लेकिन विपक्षियों को आड़े हाथों लेने के लिए उन्होंने बचकाना हास्य का सहारा लिया. ऐसी बातें करने के लिए भाजपा में किसी अन्य को आगे करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को खुद आगे नहीं आना चाहिए था. प्रधानमंत्री के भाषण का स्तर ऊंचा होना चाहिए. आपने मनमोहन सिंह को देखा, राजीव गांधी को देखा, इंदिरा गांधी को देखा, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा हमेशा बनाए रखी, चाहे उन्हें जितना भी उत्तेजित क्यों न किया गया हो.

मौजूदा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में खुद यह स्वीकार किया कि वह इस पद पर नए हैं. अब जबकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं, उन्हें समझना चाहिए कि लोग एक विनम्र, ज़िम्मेदार एवं सौम्य प्रधानमंत्री का आदर करते हैं. उन्हें राहुल गांधी से व्यंग्य का आदान-प्रदान नहीं करना चाहिए. राहुल अभी नौजवान हैं, वह प्रधानमंत्री भी बनना चाह रहे होंगे. लेकिन, आपको उन्हीं की शैली में जवाब नहीं देना चाहिए. बेशक, प्रधानमंत्री ने अपनी बात बड़े असरदार तरीके से रखी और धार्मिक किताबों का हवाला देते हुए कहा कि छोटी उम्र के लोगों को अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए. ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन इन्हें भाजपा के किसी प्रवक्ता द्वारा कहा जाना चाहिए था. प्रधानमंत्री के भाषण से यह भी समझा जा सकता है कि आपको सरकार चलाने के लिए भले ही लोगों ने चुना हो, लेकिन संसद चलाने के लिए आपको सभी दलों, विपक्षी सदस्यों को साथ लेकर चलना होगा. अंतिम 15 मिनटों के भाषण में उन्होंने यह कहने की कोशिश की कि हम सबको एक साथ मिलकर काम करने और एक आम सहमति बनाने की ज़रूरत है. नौकरशाही के पास खोने के लिए कुछ नहीं है. नेता तो लड़ते ही रहेंगे. कोई आएगा, कोई जाएगा. नौकरशाह बिना किसी जवाबदेही के अपनी जगह बने रहेंगे. यही पर प्रधानमंत्री के साथियों को चाहिए कि वे अन्य दलों के लोगों से मिलें और उनसे बातचीत करें.

न्याय पालिका ने जिस तरीके से नेशनल ज्यूडिशियल अप्वायंटमेंट कमीशन को लेकर टिप्पणी की, वह लोकतंत्र के लिए ग़लत है. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट नेताओं को आपस में जिस तरीके से लड़ते हुए देखता है, उसके मद्देनज़र ऐसी टिप्पणी स्वाभाविक है. संसद में सबको अपने बीच एक सहमति, एक समझ बनानी चाहिए. संसद को ही सर्वोच्च होना चाहिए. दुनिया में कहीं भी जज खुद जज को नियुक्त नहीं करता. इसके लिए संसद से बना एक क़ानून होना ही चाहिए. मैं न्याय पालिका से जुड़े किसी अन्य मसले पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर विधायिका स्पष्ट रूप से अपनी और न्याय पालिका की ताकत के बीच एक लाइन नहीं खींचती है, तो यह देश के भविष्य के लिए सही नहीं होगा.

प्रधानमंत्री ने एक बहुत हास्यास्पद बात कही है कि कांग्रेस के समय में चीजें दूसरी तरह से थीं. भाजपा अपने कार्यकाल में छात्रों द्वारा नारेबाजी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती. यह तो वही बात हुई कि चींटे को स्टेनगन से मारना. छात्र इस उम्र में रास्ता भटक जाते हैं, उन्हें समझाने की ज़रूरत है, न कि उनके ख़िलाफ़ पुलिसिया कार्रवाई की. किसी भी देश में छात्र आंदोलन पुलिसिया कार्रवाई से नहीं दबाए गए. जितनी जल्दी आप इन सब चीजों को ठीक कर लेंगे, उतना ही इस देश के लोकतंत्र के लिए ठीक होगा. यदि आप कांग्रेस का विकल्प बनना चाहते हैं, तो आपके पास दीर्घकालिक विचार होने चाहिए. उदाहरण के तौर पर कश्मीर. वहां एक त्रिशंकु विधानसभा बनी, तो आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था, जिससे पता चल सके कि मतदाता आख़िर चाहता क्या है? जिस दिन भाजपा ने पीडीपी से हाथ मिलाया था, उसी दिन इस कॉलम में मैंने लिखा था कि यह दोनों पार्टियों के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों दो ध्रुवों पर रहने वाली पार्टियां हैं. बिना किसी सिद्धांत के आप हाथ मिला रहे हैं. मुफ्ती मोहम्मद सईद के जनाजे में कम लोगों का आना महबूबा मुफ्ती के लिए एक बहुत बड़ा झटका था. उनकी नज़र में मुफ्ती शेख अब्दुल्ला के कद के नेता थे. मुफ्ती साहब के गढ़ बिजबेहारा में दुकानदारों ने अपनी दुकानें तक नहीं बंद कीं. महबूबा पांच वर्षों तक कश्मीर में सत्ता में रह सकती हैं, लेकिन घाटी में उनकी साख ख़त्म हो जाएगी. उनके सामने दूसरा रास्ता यह है कि वह सत्ता को फिलहाल छोड़ दें और भविष्य के लिए पार्टी को तैयार करें, ताकि अगले चुनाव में वह प्रासंगिक रहें. ज़ाहिर है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन रहेगा और विपक्ष चुनाव के लिए दबाव डालेगा. यह उनके लिए बहुत ही मुश्किल निर्णय होगा. मुझे उनकी परेशानी समझ में आती है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने वरिष्ठ पार्टी सहयोगियों से विमर्श करना चाहिए. उन्हें एक सही निर्णय लेना चाहिए और सत्ता हासिल करने के लिए मुफ्ती साहब द्वारा हासिल की गई प्रतिष्ठा गंवानी नहीं चाहिए. मुफ्ती साहब ने भी भाजपा से हाथ मिलाकर ग़लती की थी. मुफ्ती साहब बहुत कद्दावर नेता थे. वह किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकते थे, लेकिन अभी हालात वैसे नहीं हैं. अब महबूबा मुफ्ती को सावधान रहना चाहिए. बेशक, लोकतंत्र में राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन कोई विकल्प नहीं है. कश्मीर का मामला विशेष है और महबूबा मुफ्ती इसमें बेहतर कर सकती हैं. ■

बेशक, प्रधानमंत्री ने अपनी बात बड़े असरदार तरीके से रखी और धार्मिक किताबों का हवाला देते हुए कहा कि छोटी उम्र के लोगों को अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए. ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन इन्हें भाजपा के किसी प्रवक्ता द्वारा कहा जाना चाहिए था. प्रधानमंत्री के भाषण से यह भी समझा जा सकता है कि आपको सरकार चलाने के लिए भले ही लोगों ने चुना हो, लेकिन संसद चलाने के लिए आपको सभी दलों, विपक्षी सदस्यों को साथ लेकर चलना होगा.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

आंगनबाड़ी केंद्रों में भ्रष्टाचार

बिहार के विभिन्न इलाकों में स्थित आंगनबाड़ियां भ्रष्टाचार का केंद्र बन गई हैं. बच्चों की हाज़िरी (उपस्थिति) में गोलमाल करके सेविकाएं-सहायिकाएं एवं अन्य पदाधिकारी मिड डे मील की बंदरबांट में जुटे हुए हैं. वहीं जनता सोचती है कि सौ बच्चों के नाम इस्तेमाल हो रहे तो क्या हुआ, दस बच्चों को सुविधाएं तो मिल रही हैं. जिन क्षेत्रों में सेविकाओं-सहायिकाओं की बहाली रोक दी गई है, वहां मुखिया एवं पंचायत के अन्य पदाधिकारी अस्थायी व्यवस्था के नाम पर केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों का हक़ मार रहे हैं. क्या ऐसे तत्वों के ख़िलाफ़ राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्रवाई करेंगे? मुख्यमंत्री जी, जनता आपसे बहुत उम्मीद रखती है. राशन एवं ईंधन की कमी दिखाकर बच्चों का भोजन हजम करना अपराध है. सरकार को अविलंब इस ओर ध्यान देना चाहिए.

– परमानंद मिश्र, *चंपारण, बिहार.*

किसानों की दयनीय हालत

कवर स्टोरी-मोदी का किसान (29 फरवरी-06 मार्च, 2016) ने बेहद प्रभावित किया. मनीष कुमार ने देश के किसानों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान बखूबी आकर्षित किया है. स्टोरी बताती है कि आज देश के किसानों की क्या हालत है. सच है कि किसान कभी सरकार की प्राथमिकता में नहीं रहा, उसकी प्राथमिकता में केवल कॉरपोरेट्स रहे. किसानों की बदहाली के लिए आज तक आईं सभी सरकारें ज़िम्मेदार हैं.

–राकेश कुमार, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

सपा को झटका

आलेख-यूपी के उपचुनावों ने बिगाड़े समीकरण, सपा की सीटों पर कांग्रेस और भाजपा का कब्जा (29 फरवरी-06 मार्च, 2016) पढ़ा. प्रभात रंजन दीन का आलेख विश्लेषणात्मक एवं जानकारीपरक है. आलेख से पता चलता है कि राज्य में सपा के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है. भाजपा के लिए भी अधिक खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि माहौल फिलहाल उसके पक्ष में नहीं है. अगर कहीं बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी महा-गठबंधन बन जाता है, तो विधानसभा चुनाव में जीत की आस लगाए बैठी भाजपा को करारा झटका लग सकता है. इस बार सबकी निगाह खासकर दलित-मुस्लिम मतदाताओं पर है. यही वजह है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियां दलित-मुस्लिम गठजोड़ बनाने के लिए जी-तोड़ प्रयास कर रही हैं.

–कृष्णकांत ओझा, *बक्सर, बिहार.*

देशद्रोह की परिभाषा

जब तोप मुकाबिल हो-आइए, देशद्रोह की परिभाषा तय करें (29 फरवरी-06 मार्च, 2016) बहुत सटीक है. संतोष भारतीय ने उन लोगों पर जबरदस्त प्रहार किया है, जो स्वयं को राष्ट्रवादी और असहमति रखने वालों को देशद्रोही साबित कर रहे हैं. आख़िर यह कहां तक उचित है? क्या भाजपा और मोदी सरकार बताएगी कि राष्ट्रभक्ति और देशद्रोह की परिभाषा क्या है? संतोष भारतीय ने बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ़ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ़ एक सांसद किसानों की आत्महत्या को फैशन करार दे रहा है. ऐसा कहना सरासर देशद्रोह है.

–अभिनव कुमार, *बेरसराय, दिल्ली.*

बस्सी के बोल

आलेख-क्या यह दिल्ली पुलिस का अपना फ़ैसला था? (29 फरवरी-06 मार्च, 2016) पढ़ा. कमल मोरारका ने जेएनयू प्रकरण और दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर बीएस बस्सी को लेकर जो विचार व्यक्त किए हैं, उनसे मैं सहमत हूं. बस्सी की बातों में विरोधाभास साफ़-साफ़ दिखा. पुलिस पहले देशद्रोह का आरोप लगाकर कन्हैया कुमार को गिरफ्तार करती है और बाद में बस्सी कहते हैं कि वह कन्हैया कुमार की जमानत का विरोध नहीं करेंगे. उसके बाद दिल्ली पुलिस अपनी कही बात से एक बार फिर पलट जाती है और कहती है कि वह कन्हैया कुमार की जमानत का विरोध करेगी. यह किसके इशारे पर हो रहा है? संसद में भी जेएनयू और रोहित वेमुला प्रकरण पर खासी नोंकझोंक हुई. सरकार को इस मुद्दे का सर्वमान्य हल निकालना चाहिए.

–आशीष राय, *छपरा, बिहार.*

अपनी फसल कैसे बचाएं

किसान बहुत दुःखी हैं, क्योंकि नील गायों के झुंड रात में खेतों पर हमला करके खड़ी फसल तबाह कर देते हैं. मेरा नुस्खा है कि पीड़ित किसान दो किलो भटकटैया के पत्ते, दो मदार (आक), पांच किलो नीम की पत्ती, 250 ग्राम लहसुन, 50 ग्राम खैनी (तंबाकू) एवं 150 ग्राम लाल मिर्च पाउडर को किसी बर्तन में 10 लीटर गौमूत्र में डेढ़ माह तक सड़ाकर उससे निर्मित एक लीटर मिश्रण को 80 लीटर पानी में मिलाकर एक एकड़ खेत में छिड़काव करें. नील गायें (बनरोज) 15 दिनों तक खेत के पास नहीं आएंगी.

–राज किशोर पांडेय, *लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

संसद की गरिमा से खिलवाड़ बंद कीजिए

देश में महंगाई है, बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, पिछड़ेपन की समस्या है. और भी तमाम समस्याएं हैं, जिनकी जानकारी सांसदों को नहीं है. हालांकि, हर सांसद अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से परिचित है. जैसे पानी का स्तर तीन, चार, छह सौ फीट तक नीचे चला गया है. किसान खेतों की सिंचाई के लिए कर्ज लेकर बोरिंग कराता है, पर पानी नहीं मिलता, क्योंकि पहले ही इतना पानी निकाला जा चुका है कि अब धरती के भीतर पानी बचा ही नहीं है और दूसरी तरफ़ हमारी नदियों का पानी व्यर्थ में बहकर समुद्र में चला जाता है. किसानों द्वारा आत्महत्या की एक वजह यह भी है.

बजट सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ता नज़र आ रहा है. दरअसल, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि लोकसभा या राज्यसभा का चरित्र धूमिल करने में सरकारी पक्ष की रुचि है या विपक्ष की? यह सवाल इसलिए मन में उठता है, क्योंकि अब देश के लोगों को भी महसूस होने लगा है कि संसद देश की समस्याएं हल करने में असफल है. लोकतंत्र में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था संसद है. हालांकि, निर्णयों में राजनीतिक दलों या फिर जिस राजनीतिक दल की सत्ता होती है, की प्रभावशाली भूमिका होती है. लेकिन, क़ानूनी तौर पर संसद ही निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है. हमारी संसद पिछले कुछ वर्षों में किसी भी समस्या का हल निकालने में असफल साबित हुई है.

संसद समस्याओं का हल निकालने में असफल साबित हो रही है, यह एक पहलू है. लेकिन, इससे भी बड़ा पहलू यह है कि संसद में समस्याओं के ऊपर बात ही नहीं हो रही है. न कोई सांसद देश की बुनियादी समस्याओं के ऊपर बहस करने में रुचि रखता है और न संयुक्त रूप से सरकारी पक्ष और विपक्ष समस्याओं के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं. अख़बार में छपी किसी भी ख़बर को लेकर संसद में हंगामा होना आम बात हो गई है. राजनीतिज्ञों के दिमाग़ में यह सवाल नहीं उठता कि अगर इसी तरह संसद का इस्तेमाल, उन सवालों को उठाने या उन्हें लेकर हल्ला मचाने में होता रहा, जिनका संबंध समस्याओं से तो है, लेकिन चुनिंदा समस्याओं से नहीं. तो, इसका एकमात्र परिणाम यह होगा कि लोकतंत्र और लोकतंत्र को चलाने वाले चेहरे यानी संसद से लोगों का विश्वास उठना शुरू हो जाएगा.

देश में महंगाई है, बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, पिछड़ेपन की समस्या है. और भी तमाम समस्याएं हैं, जिनकी जानकारी सांसदों को नहीं है. हालांकि, हर सांसद अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से परिचित है. जैसे पानी का स्तर तीन, चार, छह सौ फीट तक नीचे चला गया है. किसान खेतों की सिंचाई के लिए कर्ज लेकर बोरिंग कराता है, पर पानी नहीं मिलता, क्योंकि पहले ही इतना पानी निकाला जा चुका है कि अब धरती के भीतर पानी बचा ही नहीं है और दूसरी तरफ़ हमारी नदियों का पानी व्यर्थ में बहकर समुद्र में चला जाता है. किसानों द्वारा आत्महत्या की एक वजह यह भी है.

जहां संसद जल संकट के निदान के बारे में बात नहीं करती, फसल के ऊपर बात नहीं करती, वहीं वह किसानों की आत्महत्या पर भी बात नहीं करती. शायद संसद किसानों की आत्महत्या और उसके कारणों के ऊपर बात करना ही नहीं चाहती. उसे लगता है कि अगर वह बातचीत करेगी, तो कहीं न कहीं उसका किसान विरोधी चेहरा भी सामने आएगा. सांसदों को थोड़ी तो लज्जा आनी चाहिए. जिस देश की 60 प्रतिशत आबादी का जीवन सिर्फ़ खेती-किसानी पर निर्भर हो और किसान आत्महत्या करें, लेकिन राजनेता उसे गंभीरता से न लें, तो मानना चाहिए कि संसद में बैठे या राजनीति कर रहे लोगों की असंवेदनशीलता आपराधिक मोड़ पर पहुंच गई है.

संसद को इस बात की फ़िक्र नहीं है कि लोग धीरे-धीरे खेती छोड़ रहे हैं, खेत बेच रहे हैं. संसद को इस बात की भी फ़िक्र नहीं है कि लोग शहरों की तरफ़ भागकर मज़दूर बन रहे हैं. मज़दूरी से उन्हें निम्नतम आय होती है, लेकिन उस निम्नतम आय में भी वे जीवन जीना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय खेती से उपजी फसल के सहारे जीवन जीने के. क्योंकि, किसान अपनी सारी जमा पूंजी और बैंकों-सूदखोर साहूकारों से कर्ज लेकर सारा पैसा खेती में लगा तो देता है, लेकिन उसे भरोसा नहीं होता कि जो फसल आएगी, वह उस कर्ज का ब्याज भी चुका पाएगी अथवा नहीं. ब्याज न चुका पाना, जवान होती बेटी का चेहरा देखना, बेटे का बेरोज़गार होना किसान को मौत की तरफ़ ले जाता है. इसी वजह से हर प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. मध्य प्रदेश इसका ताजा उदाहरण है. प्रधानमंत्री ने जिस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को महान किसान की महान पैदावार के आधार पर पुरस्कृत किया, उसी मध्य प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या की अनगिनत घटनाएं हो चुकी हैं, जिन्हें सरकार ने अपने खाते में लिखा ही नहीं.

जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है, वहां के किस्से हमारे सांसदों को नहीं मालूम. लोकतंत्र को बनाए रखना और जनता की समस्याओं का हल निकालना कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, इस एहसास से भी हमारे सांसद अछूते हैं. हम संसद और सांसदों से एक साधारण अनुरोध करते हैं कि जिन्होंने आपको चुना है, उनके चेहरे याद रखिए.

लेकिन अफ़सोस, हमारी संसद के पास ऐसे सवालों पर बातचीत करने के लिए वक्त नहीं है. शोर मचाकर संसद स्थगित कराकर सेंट्रल हॉल में बैठना या घर जाकर वे काम करना, जिनका जनता से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं होता, सांसदों के बीच यह आम चलन हो गया है. अगर हम सांसदों से पूछें कि आपने आज तक देश की किन समस्याओं पर बातचीत या सार्थक बहस की और किन समस्याओं का हल निकाला, ताकि लोग समझ सकें कि यह समस्या है क्या और हम इसके निदान का कोई रास्ता तलाश सकते हैं या नहीं? तो किसी को इसका जवाब नहीं सूझेगा. सिर्फ़ और सिर्फ़ आरोप-प्रत्यारोप, हंगामा और फिर संसद का स्थगन! अब हम सवाल उठाएं, तो देशद्रोही माने जा सकते हैं, अलोकतांत्रिक माने जा सकते हैं और सरकार, विपक्ष एवं राजनीतिक दलों के विरोधी माने जा सकते हैं. हमें कोई डर नहीं. जिसे जो मानना हो माने, लेकिन हम एक छोटी-सी विनम्र चेतावनी देते हैं. आज संसद में बैठकर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के जो सांसद मस्ती करते हैं, मौज लेते हैं, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि जिस दिन कोई पागल आकर यह संसदीय व्यवस्था समाप्त करेगा, उस दिन उनका और देश का क्या हाल होगा.

जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है, वहां के किस्से हमारे सांसदों को नहीं मालूम. लोकतंत्र को बनाए रखना और जनता की समस्याओं का हल निकालना कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, इस एहसास से भी हमारे सांसद अछूते हैं. हम संसद और सांसदों से एक साधारण अनुरोध करते हैं कि जिन्होंने आपको चुना है, उनके चेहरे याद रखिए. आप और कुछ न कर सकें, तो कम से कम सार्थक बहस तो कीजिए, संसद में बैठे दिखाई दीजिए. हम लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जब टेलीविजन के ऊपर देखते हैं, तो हमें शर्म आती है यह कहते हुए कि हमारे सदनों में सदस्यों की उपस्थिति सिर्फ़ कोरम लायक रहती है. दोपहर का शून्यकाल छोड़कर नगण्य रहती है. लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सांसदों को इसकी इज्जत करनी चाहिए और समस्याओं का हल निकालने के लिए दलीय सीमा से ऊपर जाकर या दलीय सीमा की बकवास छोड़कर अपना दिमाग़ लगाना चाहिए.

कहीं हालात ऐसे न हो जाएं कि संसद में लात-घूंसे चलें, गाली-गलौच या मारपीट हो. कई बार स्थितियां बिगड़ चुकी हैं. अगर ऐसा हुआ, तो विश्व में लोकतंत्र का सम्मान ख़त्म हो जाएगा. यह ज़िम्मेदारी संसदीय कार्यमंत्री की है. श्री वेंकैया नायडू को कोई और ज़िम्मेदारी देनी चाहिए. संसदीय कार्यमंत्री अगर स्वयं विपक्ष पर हमला करने लगे, तो यह दुर्भाग्य की बात है. सांसदों और दलों के बीच सौहार्द्र बना रहे, इसके लिए किसी मुस्कराते चेहरे को संसदीय कार्यमंत्री बनाना चाहिए. संसद लोकतंत्र का आईना है और चेहरा भी. ■

editor@chauthiduniya.com

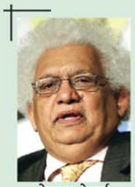

मेघनाद देसाई

नई बहस का नया दौर

पिछले कई वर्षों के बाद पहली बार भारतीय संसद गंभीर बहसों का प्लेटफॉर्म बनी है. ऐसे कई मुद्दे हैं, जिन पर इन दिनों बहस हो रही है. मसलन अभिव्यक्ति की आज़ादी और उस पर लगने वाली रोक पर बात हो रही है. सहिष्णुता के साथ ही राष्ट्र और राष्ट्रवाद के कई विचार सामने आ रहे हैं. आधुनिक भारत में दलित एवं निम्न जातियों के समक्ष आने वाली समस्याओं से जुड़ी बातें मुद्दा बन रही हैं. धर्म को लेकर आलोचना और प्रेम जैसी बातें भी सामने हैं, जिन पर संसद के भीतर और बाहर खूब बहस हो रही है. संसद की यह स्थिति उन बातों की तुलना में अच्छी है, जब सदस्य वेल में चले जाते थे, लगातार व्यवधान पैदा करते थे, जिसके चलते बार-बार संसद की कार्यवाही स्थगित हो जाती थी. अच्छी बात है कि अब उक्त मुद्दों पर कम से कम बातें तो हो रही हैं और इस बहाने संसद की कार्यवाही चल रही है. यह भी एक परिवर्तन है.

इन बहसों का कभी कोई निश्चित अंत नहीं होता और न कभी कोई अंतिम जवाब हो सकता है. लेकिन, आश्चर्य की बात यह है कि भाजपा के सत्ता में आने के साथ ही वे विचार एवं दृष्टिकोण, जिन्हें पहले बहुत कम लोग जानते थे या जो पहले बहुत कम सुने जाते थे, अब केंद्र में हैं, जैसे क्या दलित मुख्य धारा के धर्म को खारिज कर रहे हैं? काली द्वारा महिषासुर की हत्या की कथित आलोचना किताबों एवं लेखों में की गई है, लेकिन इस पर संसद में कभी बात नहीं हुई थी. हिंदू धर्म की एक दलित आलोचना की गई है, क्योंकि यह भारत के आदिवासी लोगों की अधीनता के प्रतीकों से संबंधित है. दलित अपनी पहचान राजा बलि के साथ जोड़ते हैं. राजा बलि ने एक छोटे कद के ब्राह्मण वामन को साढ़े तीन पग ज़मीन दान में दी थी (बलि को यह नहीं पता था कि वामन विष्णु के अवतार हैं). छोटे कद के ब्राह्मण वामन ने इतने दान में ही बलि का साम्राज्य अपने अधीन कर लिया था. यह शक्तिशाली बनने की चाहत रखने वाले किसी भी दलित के लिए अधीनता वाली बात है. ये सब बातें संसद में कहना कुछ लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकता है, लेकिन यह सिर्फ़ एक प्रतिद्वंद्वी विचार है. द्रोणाचार्य अनेक लोगों के लिए एक आदर्श गुरु हैं, लेकिन दलित उन्हें एक ऐसे शख्स के रूप में जानते हैं, जिसने गुरु दक्षिणा के तौर पर अपने शिष्य एकलव्य से अंगूठे की मांग कर डाली. एक व्यक्ति का नायक दूसरे के लिए खलनायक हो सकता है. एक व्यक्ति का धर्म दूसरे व्यक्ति के लिए उत्पीड़न का कारण हो सकता है.

राष्ट्र के प्रति प्रेम को लेकर भी कई विचार हैं. वामपंथी दलों का अपना एक विचार है. कांग्रेस का भी अपना एक विचार है, जो ठीक वामपंथी दलों की तरह नहीं है. लेकिन, भाजपा की अपनी एक अलग दृष्टि है. संसद में कभी भी इन विभिन्न विचारों को अभिव्यक्त नहीं किया गया. दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद बहुत लंबे समय तक पार्श्व में रहा है. उसके नायकों में वे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए हिंसा का रास्ता चुना, लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिला.

राष्ट्र के प्रति प्रेम को लेकर भी कई विचार हैं. वामपंथी दलों का अपना एक विचार है, जो ठीक वामपंथी दलों की तरह नहीं है. लेकिन, भाजपा की अपनी एक अलग दृष्टि है. संसद में कभी भी इन विभिन्न विचारों को अभिव्यक्त नहीं किया गया. दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद बहुत लंबे समय तक पार्श्व में रहा है. उसके नायकों में वे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए हिंसा का रास्ता चुना, लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिला. श्यामजी कृष्ण वर्मा, गदर आंदोलन के नायक रास बिहारी बोस जिन्होंने जापान में निर्वासन का जीवन बिताया, सावरकर जिन्होंने ब्रिटिश जेल में किसी भी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के मुक़ाबले सर्वाधिक समय तक एकांत कारावास भोगा, ये सब भारतीय इतिहास के कांग्रेसी संस्करण में हाशिये पर रहे. यहां तक कि एमएन रॉय जैसे कम्युनिस्ट नायकों को भी नज़रअंदाज़ कर दिया गया. नक्सलियों के अपने नायक हैं, जिनसे कम्युनिस्ट भी असहमत हो सकते हैं. कांग्रेस के लिए नायक सिर्फ़ गांधी एवं नेहरू हैं, दूसरा कोई नहीं है.

आने वाले वर्षों में भारत में इन मतभेदों पर कई बहसें होंगी, जिन्हें देखना और सहना होगा. आप सहमत हों अथवा नहीं, लेकिन कश्मीर भारत का एक परेशान हिस्सा है. जैसे नगालैंड, जहां 1947 के बाद से ही गृहयुद्ध हो रहे हैं. देश में ऐसे भी लोग हैं, जो इंदिरा गांधी के हत्यारों को अगर संत नहीं, तो नायक ज़रूर मानते हैं. जो लोग गोडसे का मंदिर बनाना चाहते हैं, वे भी उतने ही भारतीय हैं, जितने इस विचार से घृणा करने वाले. इस देश में हमेशा ऐसे लोग रहेंगे, जिन्हें अफजल गुरु को मिली सजा या बाटला हाउस के अभियुक्तों को लेकर शक है या जो नक्सलियों को वास्तविक देशभक्त मानते हैं. यह विभिन्न रायों की चरम विविधता है, जो परिभाषित करती है कि भारत क्या है और क्या होगा? ■

feedback@chauthiduniya.com

वास्तु विहार®
एक विश्वस्तरीय टाउनशिप
AN ISO : 9001 : 2008 : 14001 : 18001 : 2007 COMPANY
The Most Cost Effective Builder in India
4 से 50 लाख तक में घर
Customer Care : 080 10 222222
www.vastuvihar.org

मगध विश्वविद्यालय में करोड़ों का घोटाला

विजिलेंस ने खुद संज्ञान लेकर शुरू की जांच

मगध विश्वविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अमितेश प्रकाश ने विश्वविद्यालय में पदाधिकारियों की ओर से किये जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने निगरानी विभाग तथा राज्य के कुलाधिपति को करोड़ों की वित्तीय गड़बड़ी से संबंधित कागजात सौंपा है. अमितेश प्रकाश ने बताया कि नैक की टीम जब मगध विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग का निरीक्षण करने लिए आने वाले थी, तब तक मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मोहम्मद इश्तियाक ने बिना राजभवन की अनुमति लिए आंतरिक स्त्रोत के पांच करोड़ रुपये खर्च कर दिए. वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट इंफार्मेशन सेंटर के निर्माण के लिए एक करोड़ आठ लाख रुपये का ठेका बिना टेंडर के ही अपने चहते ठेकेदार को दे दिया.

सुबील सौरभ

तथागत की तपोभूमि बोधगया स्थित अपने दामन में गरिमामय अतीत को लपटे मगध विश्वविद्यालय वर्तमान में वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार, फर्जी डिग्री तथा अनेक तरह की गड़बड़ी के आगोश में पल रहा है. बिहार के सबसे बड़े विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय में पढ़ना कभी गर्व की बात माना जाता था. देश ही नहीं विदेशी छात्र-छात्राएं भी मगध विश्वविद्यालय में पढ़ना गौरव की बात मानते थे. लेकिन बीसवीं सदी के अंतिम दशक में मगध विश्वविद्यालय अपनी गरिमा को खोकर फर्जी डिग्री के लिए पूरे देश में चर्चित हो गया. मामला यहां तक पहुंच गया कि मगध विश्वविद्यालय के कई कर्मचारियों व पदाधिकारियों को जेल की हवा खानी पड़ी. इसी तरह मगध विश्वविद्यालय में वित्तीय गड़बड़ी के कई मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं.

ताजा मामला बिहार सरकार द्वारा मगध विश्वविद्यालय को दिये गए 120 करोड़ रुपये के आंवटन का है. वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 में मगध विश्वविद्यालय को कई मदों में आवंटित राशि में भी गड़बड़ी का मामला सामने आया है. बिहार सरकार के निगरानी विभाग को जब मगध विश्वविद्यालय में करोड़ो रुपये की वित्तीय गड़बड़ी के मामले का पता चला तो स्वत: संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी संख्या 8/16 दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी. जांच से पूर्व विजिलेंस ने मगध विश्वविद्यालय को एक प्रश्नावली भेजते हुए संबंधित कागजातों की मांग की. लेकिन विश्वविद्यालय ने जो कागजात विजिलेंस को सौंपे इससे जांच कर रहे पदाधिकारी संतुष्ट नहीं थे. जिसके कारण बीते 19 फरवरी 2016 को विजिलेंस की चार सदस्यीय टीम ने मगध विश्वविद्यालय पहुंचकर विभिन्न मदों में आवंटित की गई राशि और खर्च का पूर्ण ब्यौरा मगध विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी से मांगा. कागजात उपलब्ध कराने में वित्त पदाधिकारी ने सहयोग नहीं किया, जिससे निगरानी टीम में शामिल डीएसपी और इंस्पेक्टर ने कुलसचिव डा. सीताराम सिंह से इस बात की शिकायत की. वहीं दूसरी ओर मगध विश्वविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अमितेश प्रकाश ने विश्वविद्यालय में पदाधिकारियों की ओर से किये जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने निगरानी विभाग तथा राज्य के कुलाधिपति को करोड़ों की वित्तीय गड़बड़ी से संबंधित कागजात सौंपा है. अमितेश प्रकाश ने बताया कि नैक की टीम जब मगध विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग का निरीक्षण करने लिए आने वाले थी, तब तक मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मोहम्मद इश्तियाक ने बिना राजभवन की अनुमति लिए आंतरिक स्त्रोत के पांच करोड़ रुपये खर्च कर दिए. वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट इंफार्मेशन सेंटर के निर्माण के लिए एक करोड़ आठ लाख रुपये का ठेका बिना टेंडर के ही अपने चहते ठेकेदार को दे दिया. इन सब के अलावा कई वित्तीय गड़बड़ियों के मामले भी सामने आ रहे हैं. विजिलेंस की टीम जब 19 फरवरी 2016 को मगध विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंची तो वहां हड़कम्प मच गया. टीम का नेतृत्व डीएसपी आर.के पौदार कर रहे थे. टीम में इंस्पेक्टर मुरारी प्रसाद, एसआई रामहरि यादव शामिल थे. टीम ने मगध विश्वविद्यालय के आय-व्यय, अनुदान संबंधित 2014-15 तथा 2015-16 के वित्तीय कागजात मांगे. इसके अलावा साथ ही इन वर्षों में कार्यरत कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियत्रंक, वित्त पदाधिकारी, वित्त परामर्शी तथा कॉलेज इंस्पेक्टर के नाम, पते तथा मोबाइल नंबर भी मांगें.

मगध विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. सीताराम सिंह से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने मगध विश्वविद्यालय में नैक आगमन के पूर्व 120 करोड़ रुपये के आवंटन की सहमति दी थी. सरकार के वित्त विभाग ने बिना आवंटित किए उक्त राशि को आवंटित दिखा दिया था. इसी को लेकर विजिलेंस की टीम ने जांच की. कुलसचिव ने बताया कि सरकार द्वारा आंवटित राशि की जो जानकारी विजिलेंस की टीम ने मांगी, उन्हें वह जानकारी उपलब्ध करा दी गई है.

निगरानी टीम द्वारा इस अवधि में मगध विश्वविद्यालय को सरकार से अलग-अलग मदों में आवंटन की विवरणी, विश्वविद्यालय व अंगिभूत कॉलेजों द्वारा खर्च की गई विवरणी की मांग की गई. बताया जाता है कि विजिलेंस की जांच का मुख्य मुद्दा मगध विश्वविद्यालय को सरकार द्वारा 120 करोड़ रुपये का आवंटन है.

मगध विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. सीताराम सिंह से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने मगध विश्वविद्यालय में नैक आगमन के पूर्व 120 करोड़ रुपये के आवंटन की सहमति दी थी. सरकार के वित्त विभाग ने बिना आवंटित किए उक्त राशि को आवंटित दिखा दिया था. इसी को लेकर विजिलेंस की टीम ने जांच की. कुलसचिव ने बताया कि सरकार द्वारा आंवटित राशि की जो जानकारी विजिलेंस की टीम ने मांगी, उन्हें वह जानकारी उपलब्ध करा दी गई है. इस संबंध में मगध विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी देवेश कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा योजना मद में वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में उपलब्ध कराये गए बीस करोड़ रुपये के हिसाब-किताब से जुड़े मामले की जांच के लिए विजिलेंस की टीम आई थी. उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा योजना मद में मगध विश्वविद्यालय को करीब पांच करोड़ रुपये मिले हैं. इसकी रिपोर्ट विजिलेंस की टीम को सौंप दी गई है. विजिलेंस के डीएसपी आर.के पौदार ने बताया कि मगध विश्वविद्यालय में वित्तीय गड़बड़ी से संबंधित कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. लेकिन हाल के दिनों में हुई कुछ घटनाओं को देखते हुए विजिलेंस के वरीय अधिकारियों ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की है. नियम है कि जब भी किसी विभाग को विकास कार्यों के लिए राशि दी जाती है तो उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र की जांच होती है. फिलहाल इन्हीं मामले की जांच की जा रही है. सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार से आवंटित 120 करोड़ रुपये कहां गए? इस बात को बताने के लिए कोई तैयार नहीं है.

मगध विश्वविद्यालय के कुलसचिव का कहना है कि इस राशि को वित्त विभाग ने बिना आवंटन के ही मगध विश्वविद्यालय को आवंटित दिखा दिया है. जबकि यह राशि मगध विश्वविद्यालय को मिली ही नहीं. मगध विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितता चरम पर है और इस मामले में मगध विश्वविद्यालय के पूर्व तथा वर्तमान के कई पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना है. मगध विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अमितेश प्रकाश ने बताया कि मगध विश्वविद्यालय में वित्तीय गड़बड़ी तथा नियम के विपरित करोड़ो रुपये खर्च करने के सैकड़ों दस्तावेज उन्होंने राजभवन को सौंपे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

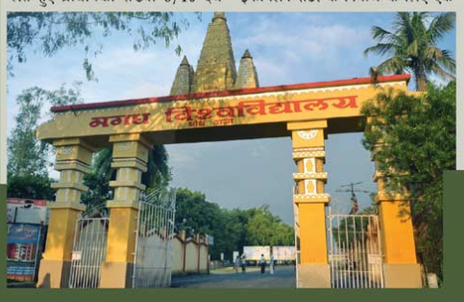

चंपारण पंचायत चुनाव में छाया चीनी मिल का मुद्दा

राकेश कुमार
feedback@chauthiduniya.com

पंचायत चुनाव की वजह से नेताओं को किसानों का दर्द समझ में आने लगा है. चाहे भाजपा हो या महागठबंधन पूर्वी चम्पारण और पश्चिमी चम्पारण में सभी दलों की राजनीति गांव-गवंई और किसान-मजदूरों के इर्द-गिर्द सिमट गई है. सभी अपने दल की मजबूती के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीताना चाहते हैं. इसी वजह से विधानसभा सत्र में किसानों और गांव से जुड़े मुद्दे सभी दल उठाने लगे हैं.

उद्योग के क्षेत्र में चम्पारण में कुछ भी नहीं है. कृषि प्रधान इस क्षेत्र में एक मात्र उद्योग चीनी मिल थी जो विभिन्न कारणों से लगभग बंदी के कगार पर है. मोतिहारी का श्री हनुमान चीनी मिल, चकिया चीनी मिल पूरी तरह बन्द हो चुके हैं. सुगौली चीनी मिल भी बन्द हो गई थी, लेकिन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की संस्था हिन्दुस्तान बायोफिल्स ने इसका अधिग्रहण कर नए सिरे से चीनी मिल का निर्माण किया जो जिले में एकमात्र संचालित होने वाली चीनी मिल है. यहां किसानों का गन्ना ही एक मात्र कैश क्रॉप था. पूर्वी चम्पारण के मोतिहारी और चकिया चीनी मिल को चालू कराने में सरकार विफल रही है. भाजपा ने इसे मुद्दा बना कर सरकार को घेरने का प्रयास किया है. ताकि पंचायत चुनाव में इसे राज्य सरकार और जदयू-राजद की विफलता के रूप में भुनाया जा सके. लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी चीनी मिल एक बड़ा मुद्दा था. स्थानीय सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा था कि चीनी मिल राज्य सरकार के अधीन का विषय है. राज्य सरकार के पूर्व गन्ना विकास मंत्री अवधेश कुशवाहा की भी चीनी मिल को खोलने को लेकर काफी किरकिरी हुई. लेकिन किसी ने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

कल्याणपुर के भाजपा विधायक सचिन्द्र प्रसाद सिंह ने चीनी मिल के मामले को उठाया है. इसके मद्देनजर श्री सिंह ने विधानसभा में एक प्रश्न भी पटल पर रखा है. उन्होंने कहा कि जिले की चीनी मिलों के दम तोड़ने के

कारण किसानों की हालत खराब हो चुकी है. 2007 में किसानों के बीच उम्मीद की किरण जगी थी जब तत्कालीन स्थानीय सांसद सह केंद्रीय कृषि, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह ने सरियतपुर में नई चीनी मिल के स्थापना की घोषणा की थी. क्षेत्र के किसानों ने इसका स्वागत किया और आगे बढ़कर मिल निर्माण के लिए अपनी भूमि दी. 105 एकड़ जमीन खरीदी गई. उक्त चीनी मिल उद्योगपति पवन रूईया की योजना थी. भूमि अधिग्रहण के बाद चीनी मिल का भव्य शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया. समारोह में तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार, केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह सहित बड़ी संख्या में नेता व गणमान्य उपस्थित थे. लेकिन मिल निर्माण की दिशा में उसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ. हालांकि अगर सरियतपुर में चीनी मिल बन जाती तो करीब 10 प्रखंडों के हजारों किसान परिवार को लाभ होता. क्षेत्रीय विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह ने इस मामले की जांच करवाने की मांग की है कि उद्योगपति रूइया को जिस शर्त पर जमीन दी गई और राजस्व में सरकार द्वारा छूट दिया गया इसका लाभ जनता को क्या मिला? जानकारी के अनुसार उद्योगपति द्वारा तत्कालीन बिहार सरकार को तीन वर्ष में चीनी मिल के स्थापना की बात कही गई थी. वर्ष 2007 में मेसर्स कयालपुर सुगर रिफाइनरी लिमिटेड कोलकाता ने इंवेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड पटना को चीनी मिल लगाने का प्रस्ताव दिया था. 26 अक्टूबर 2007 को सरियतपुर में चीनी मिल लगाने की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी थी. वहीं 21 मार्च 2008 को मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया था. प्रस्तावित मिल का नाम ग्लोब सुगर रिफाइनरी लिमिटेड रखा गया. 2011 तक मिल को स्थापित कर गन्ना की पेराई शुरू कर देनी थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ. अब मांग उठने लगी है कि भूमिदाता किसानों की जमीन का दोबारा मूल्यांकन कराकर भूमि अधिग्रहण नियमावली के अनुरूप किसानों को लाभ दिया जाए. भाजपा ने इस मामले को उठा कर जिले भर के किसानों का समर्थन लेने का प्रयास किया है. हालांकि इस मामले में आम जनता और किसानों ने सभी दलों को कठघरे में खड़ा कर रखा है, क्योंकि किसी ने भी इस मामले में कभी सार्थक प्रयास नहीं किया. आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसका सार्थक परिणाम निकलता है या यह भी महज राजनीतिक स्टंट ही है.■

CRM
TMT BAR
ISO 9001 - 2000 Certified Co.
IS:1786:2008
CM/L-5746178
भूकम्प रोधी
जंग रोधी
Fe-500
मुख्य खूबियाँ
• बचत
• मजबूती
• शानदार फिनीश
Mfg. : CITY ROLLING MILLS PVT. LTD., PATNA
HELPLINE : 0612-2216770

नीतीश बजट पर नीतीश निश्चय

बजट के ज़रिये जनता पर किसी नए टैक्स का बोझ नहीं डाला गया और न कोई राहत दी गई है. राज्य सरकार ने क़रीब डेढ़ महीने पहले कई वस्तुओं पर वैट की दरें बढ़ाने और कुछ नई वस्तुओं को टैक्स के दायरे में लाने का फ़ैसला लागू कर दिया था. शराबबंदी लागू होने से वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार की आमदनी कम हो जाएगी. वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपने बजट भाषण में 21 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक की भरपाई ऋण से करने का वादा किया है, पर आर्थिक मामलों के जानकारों को ऋण के बजाय टैक्स की आशंका अधिक दिखती है.

सरोज सिंह

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चयों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बिहार की महा-गठबंधन सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया, जो लगभग 1.45 लाख करोड़ रुपये का है. बजट में पंद्रह हज़ार करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा दर्शाया गया है, जो निर्धारित सीमा के दायरे में है. सूबे को खर्च और आमदनी की खाई पाटने के लिए 21 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण भी लेना होगा. महा-गठबंधन सरकार के इस पहले बजट में राज्य का योजना आकार साढ़े 71 हज़ार करोड़ रुपये से कुछ अधिक का है, जबकि ग़ैर योजना खर्च का आकार 72 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक का. बजट के ज़रिये जनता पर किसी नए टैक्स का बोझ नहीं डाला गया और न कोई राहत दी गई है. राज्य सरकार ने क़रीब डेढ़ महीने पहले कई वस्तुओं पर वैट की दरें बढ़ाने और कुछ नई वस्तुओं को टैक्स के दायरे में लाने का फ़ैसला लागू कर दिया था. शराबबंदी लागू होने से वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार की आमदनी कम हो जाएगी. वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपने बजट भाषण में 21 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक की भरपाई ऋण से करने का वादा किया है, पर आर्थिक मामलों के जानकारों को ऋण के बजाय टैक्स की आशंका अधिक दिखती है. ग़ौरतलब है कि सूबे के हर शख्स पर फिलहाल क़रीब तीन हज़ार रुपये का ऋण है.

बजट में सबसे अधिक धन शिक्षा के लिए आवंटित किया गया. इस मद में सरकार 21,897 करोड़ रुपये खर्च करेगी, लेकिन यह धनराशि पिछली बार की तुलना में 3,231 करोड़ रुपये कम है. संसदीय कार्य विभाग

को सबसे कम यानी एक करोड़ रुपये मिले. बजट के ज़रिये सरकार ने लोक-लुभावन घोषणाएं भी कीं. नीतीश निश्चय के तहत छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अलावा विश्वविद्यालय परिसरों में मुफ्त इंटरनेट सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी. सूबे में पांच मेडिकल एवं पांच इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ-साथ जीएमएन कॉलेज, पॉलिटेक्निक, एएनएम स्कूल और हर ज़िले में महिला आईटीआई स्थापित करने की घोषणा की गई है. रोज़गार की तलाश में बिहार से बाहर जाने वाले 20 से 25 वर्ष तक की आयु के युवाओं को दो वर्षों तक एक हज़ार रुपये मासिक सहायता भत्ता दिया जाएगा. सरकार ने बतौर मौसमी मज़दूर राज्य से रोज़गार के लिए पलायन करने वाले बुनकरों को स्लीपर क्लास का रेल किराया देने का भी फ़ैसला किया है. भागलपुर में टेक्सटाइल पार्क के साथ-साथ राज्य के विभिन्न हिस्सों में बुनकर प्रशिक्षण केंद्र, रोज़गार परामर्श केंद्र एवं फिश फीड उद्योग लगाने की घोषणा बजट में की गई है.

नीतीश निश्चय को खास तवज्जो देने के बावजूद शिक्षा, बिजली, सड़क एवं स्वास्थ्य आदि पर सरकार का ज़ोर बना हुआ है. सात निश्चयों में ग्रामीण बिहार पर भी फोकस किया गया है. कस्बों एवं ग्रामीण बिहार में बिजली आपूर्ति, सड़क निर्माण, स्वच्छता अभियान और नल से पेयजल आदि कार्यक्रमों पर खासा ज़ोर दिया गया है. वर्ष 2016-17 का बिहार बजट महा-गठबंधन सरकार की विकास दृष्टि को रेखांकित करता है. यह सूबे में नीतीश के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों से जारी विकास रणनीति में कई बदलावों का संकेत देता है. कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लेकर इस बजट में वैसी गंभीरता नहीं दिखी, जैसी पूर्ववर्ती बजटों में दिखती थी. कृषि या उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन को लेकर बजट पर्याप्त गंभीर नहीं दिखता. बजट में कृषि को योजना मद का मात्र 3.28 प्रतिशत धन आवंटित किया गया है. इससे सूबे की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की तस्वीर किस हद तक बदली जा सकेगी, यह सहज समझा जा सकता है.

बिहार में पिछले कई वर्षों से आधारभूत संरचना विकसित करने पर निरंतर ज़ोर दिया जाता रहा है. इस ख्याल से यह बजट भी उम्मीदों को नए पंख देता है. राज्य का बजटीय आवंटन पथ निर्माण (ग्रामीण कार्य विभाग सहित) एवं ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लेकर सत्तारूढ़ महा-गठबंधन की प्रतिबद्धता नए सिरे से अभिव्यक्त करता है. हालांकि, नीतीश के सात निश्चयों में इन विभागों का हिस्सा काफी महत्वपूर्ण है. इसी तरह शौचालय निर्माण, स्वच्छता अभियान एवं नल से पेयजल आदि योजनाएं भी नीतीश निश्चय से संबद्ध हैं. मानव विकास के संदर्भ में शिक्षा सहित इन सभी कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका है. ये कार्यक्रम लोक-लुभावन तो हैं, लेकिन सत्ता की विकास रणनीति में जन सरोकारों का खुलासा भी करते हैं. मानव विकास कार्यक्रम, कृषि विकास एवं उद्योग-धंधों की स्थिति में सुधार के उपाय जनता के जीवन स्तर में तात्विक बदलाव के वाहक माने जाते हैं. इन मापदंडों को सामने रखकर सत्ता की विकास रणनीति के आकलन से हालात ज़्यादा साफ़ होते हैं.

बिहार में पिछले कुछ महीनों में ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ी है. कांटी एवं बरौनी से बिजली मिलने से हालात बेहतर होने की उम्मीद है. इससे उद्योगों और इस क्षेत्र में पूंजी निवेश को गति मिलने की आशा है. बजट में शिक्षा के बाद ऊर्जा क्षेत्र को सबसे अधिक धन दिया गया है. यह नीतीश निश्चय का हिस्सा है. बिजली की स्थिति में सुधार से छोटे उद्योगों एवं कोल्ड स्टोरेज से जुड़े कार्यक्रम ज़मीन पर उतारने की उम्मीद पैदा होगी, गांवों के कच्चे माल को संरक्षण एवं स्थानीय स्तर पर बाज़ार मिलेगा और वहां आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी. लेकिन, इसकी पूरी तैयारी है क्या? सूबे में कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की व्यापक संभावना है, जिसमें रोज़गार सृजन की बड़ी क्षमता है. फल-सब्जी की खेती के विस्तार और उसकी उपज बढ़ाने के लिए कई योजनाएं यहां चल रही हैं. कुछ की घोषणा इस बजट में भी की गई है. लेकिन, उनके औद्योगिक इस्तेमाल की किसी ठोस रणनीति का अभाव रहा है. इसी वजह से रोज़गार के अवसर विकसित नहीं हो पा रहे हैं. मौजूदा बजट भी इस संदर्भ में कोई उम्मीद नहीं जगाता.

बिहार की एक पहचान श्रम आपूर्तिकर्ता की भी हो गई है. इस बजट से लगता है कि बिहार से पलायन की प्रक्रिया को गति देने की कोशिश की जा रही है. काम की तलाश में बिहार से बाहर जाने वाले बेरोज़गार युवाओं को दो वर्षों तक प्रतिमाह एक हज़ार रुपये भत्ता देने की योजना कई हलकों में इसी नज़रिये से देखी जा रही है. क़रीब डेढ़ करोड़ युवकों को भाषा एवं लोक संवाद का प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करके उन्हें रोज़गार के लायक बनाने की भी योजना है. कोई भी मान सकता है कि बिहार जब इतने बड़े पैमाने पर युवाओं को प्रशिक्षित कर रहा है, तो उनके रोज़गार की भी कोई योजना सरकार के पास होगी. लेकिन, इस मोर्चे पर यह बजट मौन है. बिहार में रोज़गार के अवसर विकसित करने की किसी परियोजना की स्पष्ट झलक इस बजट में नहीं मिलती. बजट और अन्य सरकारी दस्तावेज़ों की खामोशी सवाल पैदा करती है कि क्या हम देश में कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमशक्ति के आपूर्तिकर्ता बन जाएंगे? अगर नहीं, तो हम बिहार के युवाओं को कहां और कैसा रोज़गार दे रहे हैं?■

feedback@chauthiduniya.com

बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम की जगह बनेगा होटल

सरकार के निर्णय से खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों में निराशा

सुनील सौरभ

झारखण्ड की राजधानी रांची के मोरहाबादी में 55 करोड़ की लागत से बनाए गए राष्ट्रीय स्तर का बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. समुचित रख-रखाव के अभाव में ग्राउंड की हरी-भरी घासें सूख गई हैं. कई जगहों पर ग्राउंड की चहारदीवारी में दरारें आ गई हैं. खेल का मैदान स्तरीय फुटबॉल मैच के आयोजन लायक नहीं रह गया है. अब इस स्टेडियम को होटल बनाने के लिए राज्य सरकार ने लीज पर देने का निर्णय लिया है. विदित हो कि राजधानी रांची में 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ. उस आयोजन के पहले फुटबॉल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराने का उद्देश्य था. जिसके लिए इस स्टेडियम का निर्माण राज्य सरकार की ओर से कराया गया था. राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के बाद इस स्टेडियम में एक या दो स्तरीय फुटबॉल मैचों का आयोजन किया गया. इसके बाद धीरे-धीरे स्टेडियम के रख-रखाव के प्रति लापरवाही उजागर होने लगी. महज पांच साल में ही स्टेडियम का नजारा बदल गया. जहां हरी घासें नजर आती थीं, वहां अब मिट्टी नजर आने लगी है. इसमें एक साथ 36 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था है. वर्ष 2011 में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान ही इसमें फुटबॉल मैच व रग्बी का आयोजन किया गया था. इसके बाद फुटबॉल मैच की जगह यहां कई क्रिकेट मैचों का आयोजन किया गया. यह विडंबना ही कही जाएगी कि फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने व राज्य के फुटबॉल प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से बनाए गए इस स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने लगा. राज्य सरकार के खेलकूद, युवा कार्य विभाग की ओर से विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए स्टेडियम को किराए पर दिया जाने लगा. इससे मैदान की हरियाली व खूबसूरती खत्म होने लगी. अब हालात ऐसे हो गए हैं कि ग्राउंड में कहीं भी हरी घास देखने को नहीं मिलेगी. स्टेडियम को किराए पर देकर खेल विभाग राजस्व की प्राप्ति तो कर रहा है, लेकिन स्टेडियम के रख-रखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. कहने को तो फुटबॉल ग्राउंड है, लेकिन यहां क्रिकेट, म्यूजिकल और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं. स्टेडियम में फुटबॉल मैचों के आयोजन के प्रति खेल विभाग भी उदासीन है. पांच साल में स्टेडियम का रंग-रोगन भी नहीं किया गया. स्टेडियम के भीतर बाथरूम व शौचालय आदि की भी स्थिति बदतर होती जा रही है.

राज्य सरकार की ओर से बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में थ्री स्टार होटल बनाने की तैयारी चल रही है. इसके लिए सरकार ने स्टेडियम स्थित वीआईपी गेस्ट हाउस, स्वीमिंग पुल सहित अन्य कई हिस्से को होटल के रूप में तब्दील कर लीज पर देने का निर्णय लिया है. जानकारी के मुताबिक सरकार 30 वर्षों के लिए लीज पर होटल संचालन का जिम्मा निजी क्षेत्र के उद्यमी या व्यवसायी को देगी. इसके बदले में संबंधित कंपनी या प्रतिष्ठान झारखंड खेल प्राधिकरण को प्रत्येक वर्ष 37 लाख रुपये का भुगतान करेगा. स्टेडियम के प्रस्तावित इस क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधायुक्त क्लब सहित थ्री स्टार होटल की सुविधा उपलब्ध होगी. जानकारी के अनुसार इस योजना पर तेजी से काम चल रहा है. लेकिन राज्य के युवा कार्य विभाग या अन्य संबंधित विभाग का कोई भी पदाधिकारी इस संबंध में

आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है. झारखंड को देश के परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. फुटबॉल, हॉकी, एथलिट समेत अन्य खेलों के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने में कभी झारखंड आगे रहा करता था. लेकिन हाल के वर्षों में झारखंड के राज्य मुख्यालय स्थित राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियमों को देखने वाला कोई नहीं है तो अन्य खेल मैदानों की तो बात ही छोड़ दिजिए. जबकि वर्ष 2011 में रांची में हुए राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में झारखण्ड के खिलाड़ियों ने अधिक मेडल लेकर राज्य का मान-सम्मान बढ़ाया था. लेकिन आज बिरसा मुण्डा फुटबॉल स्टेडियम की हालत देखकर हर खेल प्रेमी को राज्य सरकार की संवेदनहीनता पर दुख है.■

feedback@chauthiduniya.com

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 62 साल की है। उठने बैठने में काफी परेशानी होती है, जोड़ों में अकड़न रहता है। कोई आर्युवेदिक दवा बतायें। दीनानाथ सिंह, रांची

उत्तर : आप REPL निर्मित ऑर्थोविट कैप्सूल एक कौप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को सोते सम लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालीश करें काफी लाभ होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 21 वर्ष है, काम क्रीड़ा में जबरदस्त उल्लास उठता है। मगर स्पर्श मात्र से ही स्खलित हो जाता हूँ। अंग भी छोटी है-मै क्या करूं? प्रभात, औरंगाबाद

उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें और विगोरा ऑयल से मालिश करें, निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 32 वर्ष है कुछ दिनों से शिघ्रपतन से परेशान हूँ और एक बार सम्बन्ध स्थापित करने के बाद दोबारा मन नहीं करता और आलस्य बना रहता है। अरूण सिन्हा, नोयडा

उत्तर : आप REPL निर्मिता विगोरा 5000 दिन में 3 बार) कप पानी में लें और विगोरा ऑयल से अंग पर मालिस करें। आपकी परेशानी दूर हो जायेगी।

प्रश्न : मैं 42 वर्षीय दो बच्चों का पिता हूँ मेरी समस्या यह है कि मुझे पत्नी से सहवास की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो मुश्किल से 15 सेकेन्ड के लिए। मैं क्या करूं? शंकर तिवारी, गुरगांव

उत्तर : बढ़ती उम्र में अक्सर ऐसा होता है। तनाव, भागदौड़ एवं किशोरावस्था की गलती बहुत से कारण हो सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप विगोरा हाई पावर का 90 दिन का कोर्स करें एवं हाई पावर मुसली ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें। निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : उम्र 64 वर्ष है। संभोग की तिव्र इच्छा होती है मगर शिशन में कोई हरकत नहीं होती है। इसलिए मन मारकर रह जाता हूँ। सुनील मेहरा वर्धमान

उत्तर : इस उम्र में ऐसा होता है। आप विगोरा 5 X का 5 शीशी का कोर्स करें और साण्डह ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें।

प्रश्न : डॉ. साहब मैने टी.वी. पर विज्ञापन देखकर वासनोउत्पति के लिए एक हलवा तरह की दवा मंगवाया उस दवा से फायदा तो कुछ नहीं हुआ उलटा पूरी रात सिर दर्द से छटपटाता रहा। कोई आर्युवेदिक और हानिरहित दवा बताएं। ईश्वरी राय, गाजियाबाद

उत्तर : ईश्वरी जी, कुछ दवा निर्माता बड़े-बड़े विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने भ्रम जाल में फंसाते हैं और अपने दवा में सिर्फ सिल्डेनाफी मिलाकर बेचते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। मेरे सुझाव से आप REPL निर्मित सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आर्युवेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफैक्ट नहीं है।

प्रश्न : मैं 24 वर्षीया एक अविवाहित युवती हूँ मेरे स्तनों का विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जिससे मैं काफी परेशान रहती हूं, आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करायेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा

उत्तर : स्तनों का का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं REPL का Breastrim Oil स्तनों पर सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से स्तन में उभार आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आयेंगी।

प्रश्न : मैं 36 वर्षीय विवाहित स्त्री हूँ पिछले एक वर्ष से पानी गिरने की समस्या है और मेरी जननांग भी काफी ढीली हो गई है। कोई हानिरहित उपचार बतायें। आभा दिल्ली

उत्तर : आभा जी आप विगोरा 1000 दिन में 2 बार 15-15 बूँद आधा कम पानी मिलाकर पियें और Virgin Oil का अंदरूनी हिस्से पर लगाएं। यह बिल्कूल ही हानिरहित दवा है।

प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्त आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है एवं सहवास की भी इच्छा नहीं होती है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। शम्भु सिंह, देहरादून

उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।

चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें :
REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला फेडरल, पटना - 801505

Contact : 9304792851,9386880107 & 0612-2251189, (10 AM to 5 PM)
E-mail : customercare@replpharma.com, Visit us at : replpharma.com

डिस्ट्रीब्यूटरः दिल्ली/हरियाणा/पंजाब : निशा मेडिकोज 8860206755, 9988532909, जयपुरः आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर 0141-2315071, उत्तर प्रदेश-कानपुर : खरया मेडिकल एजेंसी 0512-2372347, 9415127822, मुगलसरायः प्रकाश होमियो स्टोर 253078, मध्य प्रदेश-जबलपुर : मनीष फार्मा 0761-4004863, 9425157379, छतीसगढ़-भिलाई : सिंह होमियो हॉल 0788-403828, 9302839666, रायपुर : जर्मन होमियो 0771 4095630, बिहारः मॉर्डन डिस्ट्रीब्यूटर 9304018193, नॉर्थईस्ट आसाम- बोरिक होमियो रेमेडिज 03672 225340, 09435061793, पश्चिम बंगाल : एम एस ट्रेर्डस 9903175579, देव मार्केटिंग 033-30221018, सिलिगुड़ी : कलकत्ता होमियो 9593313011, झारखंडः सिंघानियां डिस्ट्रीब्यूटर 9431164318, उड़ीसा-भुवनेश्वर डायनेमिक होमियो हॉल 9437110810 कर्नाटक -विजापुर 9341610592 गुलवर्गः9343834519

पीरियड के प्रति रहें सजग

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

DR. NUSRAT YASMIN
Gynecologist इमारते शरिया (फुलवारीशरीफ)

इमारते शरिया फुलवारीशरीफ में कार्यरत डॉ. नुसरत यास्मीन ने आज कल लड़कियों को अपने मासिक धर्म(मेन्सूरेसन या पिरियड) के प्रति सजग रहने की सलाह दी है। डॉ. यास्मीन ने इसे बांझपन से भी जोड़ा है। उन्होंने बताया कि 16-18 की यंग एज की लड़कियां जिनको पिरियड की प्रोब्लम है उन्हें देर नहीं करनी चाहिए वरना आगे जाकर बांझपन का कारण बन सकती है। मासिक या पिरियड का एक खास समय होता है 21-35 दिन 21 से पहले और 35 दिनों के बाद आता है तो इसका तुरंत इलाज करायें। ज्यादातर देर से ही आता है जिसे हम ओलिगोमनेरिया कहते हैं किसी किसी को 2 महीने भी हो जाते हैं ऐसी स्थिति में ब्लीडिंग होती है। बच्चेदानी खराब होने का यह एक प्रमुख कारण है। पीसीओडी, ओवरी में बनने वाले अंडे छोटे-छोटे ही बनते हैं यह अंडे बड़े नहीं हो पाते। यह एक प्रमुख कारण है इस बीमारी का जबकी 14 दिनों में अंडा बढ़ जाना चाहिए। एम.सी. का पहले आने को पॉलीगोमनेरिया कहते हैं। दोनों ही स्थितियों में ग्यनोकोलॉजीस्ट से सम्पर्क करें इन बीमारी का प्रमुख कारण है मॉर्डन लाइफ स्टाइल, मोटापा, दैनिक दिनचर्या खराब होना और जंक फूड खाना। सही ईलाज नहीं होने पर बांझपन और यूटरस के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। डॉ. यास्मीन ने बताया कि दोनों तरह के मासिक धर्म वाले परेशानी का ईलाज मेडिसिन से या फिर लेप्रस्कोपिक ओपे. ड्रिलिंग से किया जाता है। इसका इलाज यदि आपने शादी से पहले नहीं कराया तो शादी के बाद इलाज और आपके जीवन में परेशानी बढ़ जाती है। नॉरमल पिरियड का समय 21-35 है (एक माह +2 या -2 दिन) इस तरह के परेशानी वाले मरीज को थायराइड की भी जांच करा लेनी चाहिए और उसका उचित इलाज कराना चाहिए। डॉ. नुसरत ने कहा कि लड़कियों और महिलाओं को मेरी सलाह है कि इसे इग्नोर न करें और पिरियड सही समय नहीं होने पर या दर्द रहने बोमेटिंग होने, ज्यादा ब्लीडिंग होने पर (कई-कई लड़कियां तो स्कूल कॉलेज तक नहीं जा पाती हैं) इसे संजीदगी से लें और तुरंत गायनोक्लॉजीस्ट से सम्पर्क करें। ▪ भारती

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.

A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil

Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus

Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg

Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

गरीबों के आशियाने का सपना लोहिया ग्रामीण आवास योजना

शत-प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना

आवासों का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम

निर्मित होने वाले प्रत्येक आवास हेतु शासकीय अनुदान के अतिरिक्त सोलर लाइट के लिये अलग से शासकीय सहायता अनुमन्य

प्रदेश में काफी संख्या में ग्रामीण परिवार आवासविहीन हैं। बी0पी0एल0 सर्वे-2002 के आधार पर बनाई गई आवासविहीन पात्र व्यक्तियों की स्थाई सूची के अनुसार प्रत्येक वर्ष निर्धारित लक्ष्यानुसार इन्दिरा आवास योजना के अधीन लाभान्वित किया जाता है।

प्रदेश के ग्रामीण अनुसूचित जाति/जनजाति तथा सामान्य वर्ग के परिवार, अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए, जो गरीब हैं और बी0पी0एल0 सर्वे-2002 की सूची में उनका नाम सूचीवद्ध न होने के कारण वे इन्दिरा आवास योजना के अधीन आवासीय सुविधा से भी वंचित हैं। ऐसे परिवारों की आवासीय बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार द्वारा आवास सुविधा मुहैया कराने के लिए लोहिया ग्रामीण आवास योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जा रही है।

लोहिया ग्रामीण आवास योजना शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। आवासों का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम होता है। यदि परिवार में महिला अर्थात पत्नी का देहान्त हो गया हो, तो आवास विधुर पति को भी आवंटित किया जा सकता है।

आवास के साथ स्वच्छ शौचालय निर्माण हेतु अनिवार्य रूप से जिला स्तर पर पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित ''निर्मल भारत अभियान'' से युगपित कर निधियां प्राप्त की जाती हैं। इस योजना के अधीन निर्मित होने वाले प्रत्येक आवास के लिए शासकीय अनुदान के अतिरिक्त सोलर लाइट के लिये अलग से शासकीय सहायता अनुमन्य की जाती है। सोलर लाइट का सम्पूर्ण कार्य वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के माध्यम से नेडा द्वारा पूर्ण कराया जाता है। सोलर लाइट के नियमित रख-रखाव एवं देखरेख के लिये 05 वर्ष की वारण्टी/कम्प्रिहेन्सिव ऐनुअल मेन्टेनेन्स कान्ट्रेक्ट की भी नेडा द्वारा निविदा में ही प्राविधान कर व्यवस्था बनाई गई है।

आवास का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप ही कराया जा सकता है। आवंटित आवास का मानक के अनुसार ही न्यूनतम आच्छादन क्षेत्रफल 21.11 वर्ग मीटर रहता है। इस हेतु विकास खण्ड स्तर पर तकनीकी कर्मिक द्वारा प्रत्येक लाभार्थी की भूमि पर ले-आउट बनाया जाता है। घर के आन्तरिक ले-आउट यथा कमरों के आकार आदि में लाभार्थी की इच्छानुसार परिवर्तन अनुमन्य किया जा सकता है, किन्तु दो कमरे अवश्य बनाये जाने चाहिये।

योजना के अन्तर्गत आवासों का आवंटन प्रथमतः ''डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना'' के अधीन चयनित ग्रामों में किया जायेगा।

योजना के कार्यान्वयन का दायित्व मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का होता है।

योजना के अन्तर्गत भविष्य में यदि कोई लाभार्थी परिवार जांच के दौरान गलत तथ्यों के आधार पर आवास प्राप्त हुआ पाया जाता है तो उससे आवास की पूरी लागत भू-राजस्व की भांति वसूल कर ली जायेगी तथा इस हेतु दोषी संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक तथा खण्ड विकास अधिकारी एवं संबंधित दोषी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर से विभागाध्यक्ष को 50-50 प्रतिशत की दो किश्तों में धनराशि दी जाती है जिसे वह अपने स्तर से जनपदों को अवमुक्त करते हैं। जनपदों को प्रथम किश्त के रूप में आवंटित धनराशि के सापेक्ष 60 प्रतिशत उपभोग करने के उपरान्त जनपद की मॉग पर राज्य स्तर से द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किए जाने का प्राविधान है।

जिले से आवास के लाभार्थियों को उनके राष्ट्रीयकृत बैंक खातों में दो किश्तों में धनराशि उपलब्ध कराई जाती है तथा प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत तथा द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जाती है। द्वितीय किश्त की धनराशि लाभार्थी द्वारा पूर्व निर्गत धनराशि के अनुसार 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लेने के पश्चात प्रदान की जाएगी।

चयनित लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायतों तथा विकास खण्डों द्वारा अपने कार्यालय भवन की दीवार पर अंकित किये जाने की व्यवस्था है। यह दायित्व खण्ड विकास अधिकारी तथा सचिव, ग्राम पंचायत का होगा। योजना का अनुश्रवण आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के स्तर पर किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक मण्डल/जनपद से ई-मेल पर सूचना प्राप्त करते हुए पाक्षिक समीक्षा की जायेगी और टीम तैयार कर फील्ड में भौतिक सत्यापन कराया जायेगा।

लोहिया ग्रामीण आवास योजना के निर्माण बने उच्च गुणवत्ता का प्रतीक

गांव, गरीब और किसान समाजवादी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इनके किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। उसका साक्षात उदाहरण लोहिया ग्रामीण आवास योजना है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित लोहिया आवास की गुणवता पर कम कीमत के बावजूद किसी भी प्रकार का कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है। यह सच है कि मंहगाई के कारण लोहिया आवास की कीमतें थोड़ी बढ़ी हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण निर्माण से कोई समझौता नहीं किया गया है। सरकार यदि कम कीमत पर गांव में गरीबों को लोहिया आवास दे रही है तो लखनऊ जैसे महानगर में भी चारों ओर आवास योजनायें चल रही हैं, जिसमें गरीबों को कम कीमत पर आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। इन योजनाओं से लोगों को कम कीमत पर भी अच्छे घर मिल रहे हैं।

लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत आवास की लागत के अनुरूप सामग्री मद एवं अवशेष श्रमांश के रूप में लाभार्थी द्वारा भागीदारी की जाती है। योजना के सही क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि लाभार्थी योजना की धनराशि का सही उपयोग करे। प्रथम किश्त में 50 प्रतिशत तथा द्वितीय किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी द्वारा पूर्व निर्गत धनराशि के अनुसार 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लेने के बाद निर्गत करने का प्रावधान इसीलिए रखा गया है ताकि धनराशि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार द्वारा संचालित लोहिया ग्रामीण आवास योजना में कम कीमत के बावजूद निर्माण की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं

आवास का निर्माण तीन माह में करने का लक्ष्य है तथा आवास का विक्रय व हस्तांतरण प्रतिबन्धित है। आवास का निर्माण न कराए जाने की दशा में संबंधित लाभार्थी से भू-राजस्व की भाँति सम्पूर्ण धनराशि की वसूली करने का नियम भी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु ही किया गया है ताकि केवल उचित एवं पात्र व्यक्ति ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। समाजवादी सरकार इन योजनाओं के माध्यम से गरीबों का आशियाना होने का सपना पूरा कर रही है। समाजवादी हमारे संविधान का शब्द है। समाजवादी शब्द को कोई नहीं हटा सकता। गरीबों के साथ सम्पन्नता का भी समाजवाद से नाता है। समाजवादी नाम बहुत सरल है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने लोहिया ग्रामीण आवास योजना की धनराशि बढ़ाकर 2.75 लाख रुपये की

उत्तर प्रदेश सरकार ने लोहिया ग्रामीण आवास योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि बढ़ा दी है। इसके बाद इस योजना के तहत आवासहीन गरीबों को दो लाख 75 हजार रूपये दिये जायेंगें।

इससे पहले चयनित लाभार्थियों को एक लाख 60 हजार रूपये की धनराशि दी जाती थी। साथ ही घर बनाने के लिए 21.11 वर्ग मीटर जमीन भी दी जाती थी। इसमें सोलर सिस्टम, लाइट और पंखा आदि के लिए 30 हजार रूपये सम्मिलित है।

इस संबंध में शासनादेश सभी मण्डलायुक्तों और डीएम को भेजा जा चुका है। गरीब गांववालों को अच्छा घर पहुँचाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने वर्ष 2013 के निर्धारित दरों के आधार पर मानक में बदलाव किया गया है।

लोहिया आवास योजना की प्रगति और रिपोर्टिंग के लिए ग्राम्य विकास स्तर पर

योजना के अन्तर्गत पूर्व में चयनित लाभार्थियों को एक लाख 60 हजार रुपये के स्थान पर अब दो लाख 75 हजार रुपये दिये जाने की व्यवस्था

कंट्रोल रूम बनाया जायेगा। इसके लिए योजनाओं से जुड़ी सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जायेगा।

आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा योजना के क्रियान्वयन की हर हफ्ते समीक्षा करके शासन को रिपोर्ट भेजी जायेगी।

साथ ही मंडल और जिले स्तर पर हर महीने एक टीम भेज कर निरीक्षण किया जायेगा।

इस योजना के तहत घर तैयार हो जाने के बाद उसकी फोटो खींची जायेगी, जिसे सम्बन्धित वेबसाइट पर अपलोड कराकर मूल्यांकन कराया जायेगा। इसे ही समीक्षा का आधार माना जायेगा

इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं की जाएगी ताकि लाभार्थी को योजना का वास्तविक एवं उचित लाभ प्राप्त हो सके।

लोहिया ग्रामीण आवास योजना में अनुदान राशि को बढ़ाने का उद्देश्य निर्माण की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार भी प्रकार से प्रभावित न होने देना है।

निषाद समेत यूपी की 17 अति पिछड़ी जातियां सड़क पर उतरने की तैयारी में

जाट आंदोलन का फलाफल

राष्ट्रीय निषाद संघ ने आरक्षण सीमा बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन की मांग की

दीनबंधु कबीर

जाट आरक्षण की मांग को लेकर हुए हिंसक आंदोलन के सामने सरकार के घुटने टेकने के बाद उत्तर प्रदेश में भी निषादों का आंदोलन फिर से सुगबुगाने लगा है. अभी यूपी में मुफीद माहौल भी है, 2017 में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, लिहाजा, इसे अपनी शर्तों पर राजनीतिक दलों को झुकाने का बेहतर मौका माना जा रहा है. इसके पहले भी निषादों का आंदोलन उत्तर प्रदेश में अपनी शिनाख्त दर्ज करा चुका है. पिछली बार निषाद आंदोलन के हिंसक होने के बाद थोड़ी चुप्पी तो सधी, लेकिन इसकी अंदर-अंदर तैयारियां चल रही थीं. इधर जाटों के अराजक आरक्षण आंदोलन के सामने हरियाणा सरकार के आत्मसमर्पण के बाद निषाद समुदाय के साथ-साथ 17 अति पिछड़ी जातियों के लोग फिर सड़क पर उतरने की तैयारी में लग गए हैं. जाटों के आरक्षण की मांग माने जाने के आश्वासन से नाराज राष्ट्रीय निषाद संघ ने अब आरक्षण की तय सीमा बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करने की मांग शुरू कर दी है. संघ के राष्ट्रीय सचिव चौधरी लौटन राम निषाद का कहना है कि जाट, कापू और पाटीदार जैसी प्रभु जातियों के आरक्षण आंदोलन के पीछे कांग्रेस जैसे दलों का हाथ है. निषाद ने जाट आरक्षण आंदोलन को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि आरक्षण की तय सीमा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन करना चाहिए और जाट जैसी जातियों को ओबीसी के अतिरिक्त विशेष सूची बनाकर कोटा देना चाहिए. यही न्यायसंगत रहेगा.

राष्ट्रीय निषाद संघ का कहना है कि आरक्षण की मांग कर रही जातियों को 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा के ऊपर अलग से एसबीसी के नाम से आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए न कि पिछड़े वर्ग में शामिल कर पिछड़ों का हक मारना चाहिए. संघ के राष्ट्रीय सचिव ने एलआर नायक की सिफारिश के अनुसार पिछड़ों, अति पिछड़ों व विमुक्त घुमन्तू जनजातियों को अलग-अलग आरक्षण देने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा नहीं किया गया तो आरक्षण की मूल संवैधानिक भावना का अनादर होगा. निषाद ने केरल, आंध्रप्रदेश, पंजाब, की तरह एससी में भी वर्गीय विभाजन की आवश्यकता पर जोर दिया और सरकार को चेतावनी दी कि अगर हिंसात्मक आंदोलन से ही सरकार का ध्यान आकर्षित होता है तो 17 अति पिछड़ी जातियां भी हिंसात्मक आंदोलन का रास्ता अपना लेंगी. यूपी में तीखे आंदोलन के मूड में आए निषादों और 17 अति पिछड़ी जाति के नेताओं का कहना है कि जाट, कापू, पाटीदार जैसी दबंग जातियों के आरक्षण आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है. 2014 के लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के एक दिन पहले कांग्रेस सरकार ने जाटों को केंद्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने की अधिसूचना जारी की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था.

कई राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण व्यवस्था लागू है. हरियाणा में एससी को 20 प्रतिशत, बीसीए को 16 प्रतिशत, बीसीबी को 11 प्रतिशत, एसबीसी को 10 प्रतिशत, आर्थिक रूप से बीसीसी को 10 प्रतिशत यानी कुल 67 प्रतिशत आरक्षण लागू है. महाराष्ट्र में एससी को 13 प्रतिशत, एसटी को सात प्रतिशत, ओबीसी को 20 प्रतिशत, डीएनटी को 12 प्रतिशत यानी कुल 52 प्रतिशत आरक्षण लागू है. तमिलनाडु में एससी को 18 प्रतिशत, एसटी को एक प्रतिशत, ओबीसी को 30 प्रतिशत, एमबीसी/डीएनटी को 20 प्रतिशत यानी कुल 69 प्रतिशत आरक्षण लागू है. इसी तरह छत्तीसगढ़ में एससी को 12 प्रतिशत, एसटी को 32 प्रतिशत, ओबीसी को 14 प्रतिशत अर्थात कुल 58 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है. गुजरात में पाटीदार अनामत आंदोलन, हरियाणा में जाट आंदोलन व आंध्रप्रदेश-तेलंगाना में कम्मा आरक्षण आंदोलनों को कांग्रेस ही हवा दे रही थी.

उल्लेखनीय है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के समय देश में पिछड़े वर्ग की आबादी 52 प्रतिशत, अनुसूचित जाति की आबादी 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति की आबादी 7.5 प्रतिशत, धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी 10.5 प्रतिशत और सवर्ण जातियों की आबादी 15 प्रतिशत थी. अनुसूचित जाति व जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 22.5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, जबकि ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में न देकर मात्र 27 प्रतिशत आरक्षण दिया, जो उनकी जनसंख्या का लगभग आधार था. मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के बाद 1999 में तमाम असवर्ण अगड़ी व दबंग जातियों जाट, कुर्बा, बोक्कालिगा, लिंगायत, कलवार, विश्नोई, मोढ़, घाची आदि को ओबीसी में शामिल कर लिया गया और इस समय कम्मा, पाटीदार, मराठा, जाट, जट सिख, रोड़, त्यागी सहित कुछ अन्य जातियां भी ओबीसी में शामिल होने की मांग कर रही हैं और आंदोलन कर रही हैं.

कुछ दिनों पहले निषादों और कुछ अन्य समान जाति-समुदाय के आरक्षण की मांग पर जुझारू आंदोलन चलाने वाले राष्ट्रीय निषाद एकता मंच के नेता संजय निषाद कहते हैं कि सरकार ने संविधान में व्यवस्था न होने के बावजूद गूर्जरों को आरक्षण दे दिया, जाटों को आरक्षण देने जा रही है, लेकिन अर्से से संघर्षरत निषाद समुदाय की उपेक्षा की जा रही है. उत्तर प्रदेश में आरक्षण की मांग को लेकर 17 अति पिछड़ी जातियों का आंदोलन हिंसक होने की पूरी आशंका है. जाटों के आरक्षण-आंदोलन के साथ-साथ यूपी में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, आरक्षण की सरगर्मी बढ़ती जा रही है. निषाद समुदाय पांच प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण की मांग पर अड़ा है. राजनीतिक पासा फेंकते हुए सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने निषाद समेत 17 अन्य पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए न केवल सहमति दे रखी है बल्कि केंद्र को इसका प्रस्ताव भी भेज रखा है. केंद्र सरकार में मामला लटका हुआ है. लेकिन निषाद समुदाय के लोग जो पांच प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण की मांग कर रहे हैं उसे सरकार अगर मान भी लेती है, तो कोर्ट उसे नहीं मानेगी, क्योंकि आरक्षण में आरक्षण दिए जाने का कोई नियम नहीं है. अति पिछड़ा वर्ग की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने के लिए यूपी सरकार की ओर से केंद्र सरकार को तीन बार पत्र भेजा गया है. 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की पहल अक्टूबर 2005 में शुरू हुई थी. तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने संप्रग सरकार को पत्र लिख कर इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग की थी. मुलायम सिंह के पत्र पर तत्कालीन यूपीए सरकार महीनों खामोश बैठी रही. प्रदेश सरकार ने जब फिर से पत्र व्यवहार शुरू किया, तो केंद्र ने कई ऐसी जानकारियां मांग लीं जिसे पूरा करना काफी कठिन था. बसपा नेता मायावती ने उत्तर प्रदेश की 17 अति-पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की सूचि में शामिल करने के साथ-साथ गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग की थी. मायावती ने 2007 में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में भी इसी प्रकार का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, जो रह हो गया था. तब कहा गया था कि ये जातियां अनुसूचित जाति के अछूतपन की शर्त को पूरा नहीं करती हैं. दलितवादियों को यह प्रस्ताव पसंद नहीं है, वे इसे दलित विरोधी बताते हैं. उनका कहना है कि अति पिछड़ी जातियों को पिछड़ी जातियों के 27 प्रतिशत कोटा में से डॉ. छेदी लाल साथी सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों के अनुसार अलग कोटा देना चाहिए.

2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी तो केंद्र को फिर से दो बार सूची भेजी गई, लेकिन वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया. केंद्र की तरफ से कोई फैसला आए, उसके पहले ही समाजवादी पार्टी की सरकार ने विधानसभा चुनाव नजदीक देखते हुए 17 अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण जैसी सुविधाएं देने का फैसला भी कर लिया. प्रदेश सरकार ग्राम्य विकास विभाग की कई योजनाओं में 17 अति पिछड़ी जातियों को मात्रात्मक आरक्षण देगी. जिससे निर्धारित योजनाओं में इन जातियों के लाभार्थियों की 7.5 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित हो. कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, मांझी और मछुआ को ग्राम्य विकास की योजनाओं में 7.5 प्रतिशत मात्रात्मक आरक्षण देने को कहा जा चुका है. इन योजनाओं में लोहिया ग्रामीण आवास, हैंडपंप, ग्रामीण पेयजल योजना, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना समेत कई अन्य ग्रामीण योजनाएं शामिल हैं. प्रदेश सरकार की कोशिश है कि यादव-मुस्लिम समीकरण के साथ अगर इन अति पिछड़ी जातियों का 15 प्रतिशत वोट भी सपा को मिल जाए तो 2017 में भी उसकी कामयाबी की राह आसान हो जाएगी. सपा सरकार की इस कोशिश के बावजूद निषाद समुदाय के नेताओं का कहना है कि आरक्षण के मसले पर केंद्र का रुख स्पष्ट होना चाहिए. लिहाजा, अब अधर में नहीं रहते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन की शुरुआत की जाएगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड के विकास में समाजवादी पार्टी की पहल, मेट्रो समेत कई मुद्दों पर बनी सहमति

पहाड़ पर जड़ें जमाने की सपाई कोशिश

खुफी यायावर

समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में भी अपनी जड़ें मजबूत करने का प्रयास कर रही है. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने इसका बीड़ा उठाया है. दोनों राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने विस्तार की योजना बनाई है. समाजवादी पार्टी पूरे उत्तराखंड राज्य में जल्द ही मुलायम संदेश यात्रा निकालने जा रही है. राज्य के विधानसभा चुनाव में सपा ताकतवर तरीके से हिस्सा लेने की तैयारी कर रही है. यूपी से कट कर बने उत्तराखंड में अपनी राजनीतिक पकड़ स्थापित करने के उद्देश्य से ही उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच मेट्रो ट्रेन चलाने की भी पहल कर रही है. उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री और समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी शिवपाल सिंह यादव ने इस सिलसिले में पिछले दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात की और मेट्रो रेल की योजना पर विचार-विमर्श हुआ. उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच मेट्रो ट्रेन के संचालन, बांध, नहरों और परिसम्पत्तियों के बंटवारे के संबंध में भी दोनों राज्यों के बीच सहमति हो गई है.

इस बारे में सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुरादनगर (गाजियाबाद) तक मेट्रो ट्रेन आ चुकी है और अब इसे उत्तराखंड के हरिद्वार तक लाया जाएगा. शिवपाल बोले कि इस संबंध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से बातचीत हुई है कि गंगा नहर के पास खाली पड़ी भूमि का मेट्रो ट्रैक बनाने के काम में इस्तेमाल किया जाएगा. शिवपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने जब से योजना आयोग को समाप्त किया है तब से राज्यों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं. रावत के वक्तव्य का हवाला देते हुए शिवपाल ने कहा कि उत्तराखंड को भी केंद्र सरकार से पर्याप्त सहायता नहीं मिल पा रही है. शिवपाल ने कहा कि ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश को केंद्र से पहले आठ हजार करोड़ रुपये मिल जाते थे, पर अब नहीं मिल रहे हैं, जिससे दोनों राज्यों के

विकास में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है. जिन मुद्दों को लेकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, वह आज भी यथावत है. यहां के बेराजगारों को रोजगार नहीं मिला, जिससे लोगों का पलायन जारी है. विकास के नाम पर उत्तराखंड में कुछ भी नहीं हुआ. उत्तराखंड के पांचों सांसद भाजपा के हैं और केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद प्रदेश को न तो विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा है और न ही ग्रीन बोनस दिया जा रहा है, जबकि उत्तराखंड का पैंसठ प्रतिशत हिस्सा वन से आच्छादित है.

शिवपाल ने अगले वर्ष उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में कहा कि समाजवादी पार्टी समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों और संगठनों से तालमेल बनाकर चुनाव लड़ेगी. इसके लिए उत्तराखंड के समाजवादी, लोहियावादी और चौधरी चरण सिंह वादी विचारधारा के राजनीतिक दलों और संगठनों से समन्वय स्थापित कर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह से राज्यभर में मुलायम संदेश यात्रा निकाली जाएगी. यात्रा के माध्यम से आम जनता को पार्टी द्वारा राज्य हित में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सपा नेता शिवपाल सिंह यादव के साथ हुई बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि दोनों राज्यों के रिश्ते और भी मजबूत होंगे. मुरादनगर से हरिद्वार तक नहर के किनारे-किनारे मेट्रो परियोजना प्रारम्भ करने के सुझाव पर एक संयुक्त एसपीवी बना कर उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी और तदनुरूप काम शुरू किया जाएगा. रूड़की में पुरानी ऊपरी गंग नहर में वाटर स्पोर्ट्स के लिए यूपी सरकार द्वारा सहमति दे दी गई है. उत्तराखंड में वर्ष 2018 में होने जा रहे नेशनल गेम्स को देखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण है. यह पहले ही तय किया जा चुका है कि उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा में स्थित उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों में से लगभग 25 प्रतिशत भवनों को उत्तराखंड राज्य के प्रयोजन के लिए उत्तराखंड को हस्तांतरित किया जाएगा. इसे 31 मार्च तक कर देने का निर्णय लिया गया. जिन नहरों के हेड व टेल उत्तराखंड में हैं और स्वामित्व उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, उन्हें यूपी सरकार द्वारा जल्द ही उत्तराखंड को सौंप दिया जाएगा. ऐसी कुल 37 नहरें हैं, जिनमें से 28 नहरें हरिद्वार जनपद में व नौ नहरें ऊधमसिंहनगर जनपद में हैं. जमरानी बांध के लिए उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में एमओयू हस्ताक्षरित किया जाना है. एमओयू का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. इसे दोनों राज्यों की केबिनेट से जल्द ही अनुमोदित करा दिया जाएगा. इसके बाद इसे केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. तय किया गया कि मार्च माह में एमओयू पर दोनों राज्यों के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे.

रामगंगा में जल संभरण बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की जाएगी. इसमें गैरसैंण से प्रारम्भ करते हुए अनेक जलाशय बनाए जाएंगे. टिहरी डैम में प्रभावित हो रहे गांवों के पुनर्वास के संबंध में यूपी व उत्तराखंड मिलकर केंद्र सरकार व टीएचडीसी से अनुरोध करेंगे. इस बात पर भी सहमति बनी है कि हरिद्वार में गंगा नदी में नालों को टैप कर उन्हें एक समानांतर कैनाल या पाईपलाईन से बाहर ले जाया जाएगा. इसके लिए यूपी सरकार द्वारा फंडिंग की जाएगी. यूपी सरकार हरिद्वार में ज्ञान गोदड़ी के लिए अपनी स्वामित्व की भूमि भी उपलब्ध करवाएगी. साथ ही आश्रम नगर हरिद्वार में ईसाई कब्रिस्तान के लिए भूमि देने पर यूपी के सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव द्वारा सहमति व्यक्त की गई. यह भी तय किया गया कि उत्तराखंड की सीमा में यूपी की ऐसी भूमि व सम्पत्ति जो उनके उपयोग में नहीं आ रही है, उत्तराखंड सरकार को विक्रय कर दी जाएगी या लीज पर दे दी जाएगी. किच्छा नगर क्षेत्र में रोडवेज बस अड्डे का स्वामित्व उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग से उत्तराखंड सरकार को कर दिया जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

> अरलु की छाल को कूटकर, बराबर मात्रा में पद्मकेसर मिलाएं, जल से पीसकर गोला बनाकर, गम्भारी पत्र में लपेटकर, पुटपाक विधि से स्वरस निकाल लें. शीतल होने पर 5 मिली स्वरस में मिश्री या शहद मिलाकर पीने से अतिसार में लाभ होता है.

अरलु

परिचय

अरलु विश्व के उष्णकटिबंधीय देशों अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया आदि में प्राप्त होता है. भारत में विशेषतः बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश के जंगलों से प्राप्त होता है. यह सड़कों के किनारे तथा उद्यानों में अलंकारिक पौधे के रूप में तथा प्रायद्वीपीय भारत में लगाया जाता है.

बाह्य स्वरूप

इसका 20-24 मी ऊंचा, 2-2.5 मी व्यास का, दुर्गन्धयुक्त, बृहत पर्णपाती वृक्ष होता है. इसके पत्र 20-30 सेमी लंबे, संयुक्त, पिच्छाकार तथा पुष्प छोटे पीताभ, बहुधा बहुशाखित गुच्छों में होते हैं. फल ताम्रवर्णी, 3.8-5.5 सेमी लंबे, 1-1.3 सेमी चौड़े भालाकार, रक्ताभ-भूरे वर्ण के बीज एकल, मध्य में 6 मिमी लंबे एवं 2.5 मिमी चौड़े होते हैं.

आयुर्वेदीय गुण-कर्म एवं प्रभाव

- अरलु रस में तिक्त, रूक्ष, कफ पित्तशामक तथा वात कारक है.
- यह संग्राही, पाचन, दीपन, ग्राही व विष्टंभी होता है तथा कृमि व कुष्ठ का शमन करता है.
- इसकी छाल ज्वर तथा तृष्णा का शमन करने वाली, संकोचक भूख बढ़ाने वाली, कृमिनाशक तथा अतिसार, कर्णशूल व त्वचा रोगों को नष्ट करती है.
- इसके कांड त्वक् से प्राप्त क्लोरोफॉर्म सत्त में कवकरोधी प्रभाव दृष्टिगत होता है.
- इसका मेथेनॉलिक सार सार्थक मात्रा आधारित श्वासहर क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है.
- इसके मूल त्वक् सार से प्राप्त ऐलेंथीओन ल्यूकीमिया ग्रस्त चूहों में कर्कटार्बुदरोधी प्रभाव दिखता है.

महारलू

- मूल छाल का प्रयोग अपस्मार, हृद्य विकार तथा श्वास कष्ट की चिकित्सा में किया जाता है.
- छाल का क्वाथ बनाकर पीने से उदरांत्र कृमियों का शमन होता है.
- छाल को पीसकर लगाने से मोच में लाभ होता है.
- छाल का क्वाथ बनाकर पीने से विषम ज्वर में लाभ मिलता है.
- मूल छाल का क्वाथ बनाकर व्रण को धोने से व्रण का शोधन तथा रोपण होता है.
- पत्र एवं छाल को पीसकर व्रण में लगाने से व्रण का शोधन तथा रोपण होता है.
- मूल क्वाथ मिश्री तथा काली मिर्च मिलाकर पीने से श्वास-कास में लाभ होता है.
- मूल छाल का क्वाथ बनाकर पीने से रक्तातिसार एवं प्रवाहिका में लाभ होता है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

कर्ण रोग:

- **कर्णशूल-** अरलु के पत्तों पर तेल लगा कर, सेंधा नमक छिड़क कर, पुटपाक-विधि से रस निकालकर 1-2 बूंद रस को कान में डालने से कान दर्द का शमन होता है.
- अरलु की छाल को पीसकर उसे तिल तेल में पकाकर तेल को छानकर रख लें. इसे 1-2 बूंद कान में डालने से कर्णशूल का शमन होता है.

मुख रोग :

- मुंह के छाले- अरलु की छाल का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से मुख के छाले दूर होते हैं.

वक्ष रोग :

- **कास-** अरलु की छाल का क्वाथ से निकलने वाली वाष्प का बफारा देने से खांसी तथा जुकाम में लाभ होता है.
- **श्वास रोग-** 1-2 ग्राम छाल चूर्ण में अदरक का रस तथा शहद मिलाकर सेवन करने से श्वास में लाभ होता है.

उदर रोग :

- **अतिसार-** अरलु की छाल को कूटकर, बराबर मात्रा में पद्मकेसर मिलाएं, जल से पीसकर गोला बनाकर, गंभारी पत्र में लपेटकर, पुटपाक विधि से स्वरस निकाल लें. शीतल होने पर 5 मिली स्वरस में मिश्री या शहद मिलाकर पीने से अतिसार में लाभ होता है.
- अरलु की छाल का कल्क बनाकर 2 ग्राम कल्क में बराबर मात्रा में घी मिलाकर, गर्म पानी की भाप से गर्म कर शीतल हो जाने पर शहद मिलाकर रोगी को देने से अतिसार में लाभ होता है.
- अरलु की छाल का कल्क बनाकर पुटपाक करके उसका रस निकालकर 5-10 मिली मात्रा में पीने से अथवा 6 ग्राम मोचरस और 10 ग्राम शहद के साथ 5 मिली अरलु स्वरस मिलाकर पीने से समस्त प्रकार के अतिसार में लाभ होता है.
- अरलु की छाल और सोंठ को पीसकर 2-4 ग्राम की मात्रा में चावल के जल के साथ सेवन करने से अतिसार का शमन होता है.
- **अग्निमांद्य-** 5 ग्राम छाल को 20 मिली गर्म या ठंडे पानी में रात में भिगोकर रख दें, सुबह छाल को पानी में मसलकर, पानी को छान कर पिलाने से जठराग्नि का दीपन होता है.
- 1 ग्राम अरलु निर्यास चुर्ण को दुध के साथ पिलाने से अतिसार का शमन होता है.

गुदा रोग:

- अरलु छाल, चित्रक मूल, इंद्रयव, करंज छाल तथा सेंधा नमक, इन सभी औषधियों को समान भाग में लेकर पीसकर चुर्ण बना लें. इस चूर्ण को 2-4 ग्राम की मात्रा में लेकर तक्र के साथ पीने से अर्श में लाभ होता है.

प्रजननसंस्थान रोग :

- 2-5 मिली अरलु छाल स्वरस में शहद मिलाकर देने से प्रसूति के पश्चात होने वाले कमजोरी तथा वेदना आदि का शमन होता है.
- जिन स्त्रियों को प्रसूति के पश्चात चार-छः दिन तक अत्यंत पीड़ा रहती है. उनके 5 ग्राम अरलु छाल चूर्ण में 4 ग्राम सोंठ तथा 5 ग्राम गुड़ मिलाकर उसकी 10 गोलियां बनाकर 1-1 गोली को सुबह, दोपहर, शाम दशमूल क्वाथ के साथ देने से अत्यंत लाभ होता है.

अस्थिसंधि रोग :

- अरलु की पत्तियों को पीसकर संधियों पर बांधने से संधिवात में बहुत लाभ होता है.
- 1-2 ग्राम अरलु छाल चूर्ण का शहद के साथ नियमित सेवन करने से संधिशूल तथा संधिशोध का शमन होता है.

त्वचा रोग :

- **व्रण-** अरलु त्वक् फांट से घाव को धोने से घाव जल्दी भर जाता है.

सर्वशरीर रोग :

- **ज्वर-** 10 ग्राम अरलु छाल को 80 मिली जल में पकाएं तथा 20 मिली शेष रहने पर ठंडा करके उसमें शहद मिलाकर प्रातः सायं पिलाने से ज्वर में लाभ होता है.
- 1-2 ग्राम अरलु छाल चूर्ण में शहद मिलाकर प्रातः सायं सेवन करने से ज्वर में लाभ होता है.

बाल रोग :

- अरलु, वरुण, पारिभद्र तथा आस्फोता के काढ़े से बालक का परिषेक करने पर बालग्रहादि रोगों का प्रतिरोध होता है.

प्रयोज्यांग : कांड त्वक एवं पत्र.

मात्रा : स्वरस 10-20 मिली. घनसत्त- 500 मिग्रा. चूर्ण 2-3 ग्राम. क्वाथ 5-10 मिली या चिकित्सक के परामर्शानुसार. ■

आचार्य बालकृष्ण

रोजगार गारंटी की पूरी जानकारी चाहिए तो आरटीआई का प्रयोग करें

चौथी दुनिया ब्यूरो

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

मैं .... ग्राम का निवासी हूं. मैंने एन.आर.ई.जी.ए. के तहत रोजगार के लिए .... आवेदन किया था. मेरी जॉब कार्ड संख्या............ है. इस संबंध में निम्न विवरण प्रदान करें:

1. आपके रिकॉर्ड के मुताबिक मेरे आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई है? क्या मुझे काम दिया गया? यदि हां तो निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

क. कार्य का नाम
ख. काम दिए जाने की तारीख
ग. काम की स्थिति (चालू है या समाप्त हो गया)
घ. आवेदन करने के बाद मुझे कितने दिन का काम दिया जा चुका है
ड. काम के बदले भुगतान की गई राशि
च. राशि का भुगतान किस तारीख को किया गया
छ. रिकॉर्ड रजिस्टर के उस भाग की प्रमाणित प्रति, जहां मेरे भुगतान से सम्बंधित विवरण दर्ज हैं.

2. एन.आर.ई.जी.ए. के तहत काम के लिए आवेदन करने के कितने दिनों के अन्दर काम मिल जाना चाहिए? इससे सम्बंधित नियमों/आदेशों/दिशानिर्देशों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं.

3. एन.आर.ई.जी.ए. के तहत काम के लिए आवेदन करने के कितने दिनों तक काम नहीं उपलब्ध करा पाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है?

4. आपके रिकॉर्ड के अनुसार, क्या मुझे बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए? यदि हां तो क्या मुझे बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? यदि हां तो इससे सम्बंधित निम्नलिखित सूचनाएं दें:

क. कब से दिया जा रहा है, तारीख बताएं
ख. कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है, तिथिवार विवरण दें

ग. रिकॉर्ड रजिस्टर के उस भाग की प्रमाणित प्रति, जहां मेरे भुगतान से सम्बंधित विवरण दर्ज है

5. मेरे गांव में जिन लोगों को जॉब कार्ड दिया गया है, उनमें से कितने लोगों ने काम देने का आवेदन किया है, उसकी सूची निम्नलिखित सूचनाओं के साथ उपलब्ध कराएं:

क. आवेदक का नाम व पता
ख. आवेदन करने की तारीख
ग. दिए गए कार्य का नाम
घ. कार्य दिए जाने की तारीख
ड. कार्य के लिए भुगतान की गई राशि व भुगतान की तारीख
च. रिकॉर्ड रजिस्टर के उस भाग की प्रमाणित प्रति, जहां इनके भुगतान से सम्बंधित विवरण दर्ज हैं
छ. यदि काम नहीं दिया गया है तो क्यों?
ज. क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है?

6. एन.आर.ई.जी.ए. के तहत तय समयसीमा के अंदर काम या बेरोजगारी भत्ता नहीं देने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी और कब तक? मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

भवदीय
नाम:
पता:
फोन नं:
संलग्नक:
(यदि कुछ हो) ■

यदि आपने सूचना अधिकार कानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

साईं वंदना

कर्मफल : फल-भोग से पाप का क्षय

यह आवश्यक नहीं है कि पापी सदैव आनंदमय जीवन व्यतीत करें और सत्कर्म करने वाले प्राणी सदैव दुःख भोगें. पुण्यवानों के संदर्भ में कभी-कभी पूर्व जन्म के अशुभ कर्म इस जीवन में विपरीत प्रभाव डालते हैं.

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

बुरा न करने पर भी कुछ व्यक्तियों को किन कारणों से दुःख भोगने पड़ते हैं?

मनुष्य के जीवन की प्रत्येक घटना उस व्यक्ति के कर्म के आधार पर घटित होती है. जन्मों से अर्जित पाप-पुण्यों के संयोग के आधार पर संस्कार प्राप्त होते हैं और हमारी इच्छा-शक्ति बनती है. किसी का बुरा न करने पर भी यदि व्यक्ति को किन्हीं कारणों से दुःख भोगने पड़ते हैं और वह उन्हें रोक पाने में असमर्थ होते हैं तो समझें कि पुराने पाप-कर्मों का फल आ रहा है. पाप का फल भोगने से पाप का क्षय होता है और हमारी वह इच्छाशक्ति जिसका प्रयोग करने में हम असमर्थ थे, नियंत्रित होकर अच्छे कार्य करती है.

सद्गुरु : कर्मों की रेखा मिटाएं

सद्गुरु की शरण में आने से पूर्वजन्मों के कर्मों का प्रभाव मन्द क्यों पड़ने लगता है?

सद्गुरु प्रकृति की दिव्य शक्तियों को लोक-कल्याण के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, परन्तु वे इन शक्तियों को अपने भक्तों के लिए प्रयोग करने से पहले उनके पाप एवं पुण्य-राशि को ध्यान में रखते हैं. कोई भी व्यक्ति जो सद्गुरु के सान्निध्य में आता है, तो अदृश्य शक्तियां सद्गुरु के विचारों के साथ उस व्यक्ति की सहायता करती हैं. इसलिए जो भी सद्गुरु के संबंध में आकर उनके दिव्य प्रभा-मंडल के साथ जुड़ जाता है, उसका योग-क्षेम प्रदान करने के लिए और उसका पालन करने के लिए सद्गुरु सतत प्रयासरत रहते हैं, चाहे उस व्यक्ति को इस विषय में भान हो अथवा न हो. सद्गुरु के संपर्क में आने पर उन दिव्य अलौकिक रश्मियों से प्रभावित होकर, उल्लास और आशा का संचार होता है. जैसे कि श्री साई सच्चरित्र पढ़ने पर पता चलता है कि ज्यादातर भक्तों को पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, दैहिक, आदि कष्टों से छुटकारा मिलता है या फिर इन कष्टों में कमी आ जाती है.

संचित कर्म

इस संसार में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो अपने जीवन-काल में अनेक प्राणियों की सहायता करते हैं, फिर भी उन्हें अत्यंत दुःख भोगना पड़ता है, जबकि दुष्कर्म करने वाले अनेक व्यक्तियों का जीवन आनंदपूर्ण होता है. इसका क्या कारण है?

यह आवश्यक नहीं है कि पापी सदैव आनंदमय जीवन व्यतीत करें और सत्कर्म करने वाले प्राणी सदैव दुःख भोगें. पुण्यवानों के संदर्भ में कभी-कभी पूर्व जन्म के अशुभ कर्म इस जीवन में विपरीत प्रभाव डालते हैं. इसी प्रकार पापी यदि इस जीवन में सुखी हैं तो अपने पूर्वजन्मों के सत्कर्मों के संचित शुभ कर्मों के फलस्वरूप वे भले ही सुखी प्रतीत होते हैं, किंतु वर्तमान जीवन में या आगे उन शुभ कर्मों के प्रभाव के नष्ट होते ही उन्हें आज के दुष्कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा. सत्कर्मों का महत्व सदैव रहेगा. वे कभी व्यर्थ नहीं जाते. हमारे जीवन-खाते में क्या अवशिष्ट है, उसी के आधार पर हमारे भोग होते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

प्रभावशाली युवाओं की सूची

सायना, सानिया और कोहली रहे अव्वल

फोर्ब्स ने भारत, इंडोनेशिया, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, जापान, पाकिस्तान और वियतनाम जैसे देशों के उन युवाओं की सूची तैयार की है, जो अपने क्षेत्र में बेहद प्रभावशाली दखल रखते हैं तथा महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. इस सूची का नाम 30 अंडर 30 एशिया है. संस्था ने कहा है कि इस समय भारत में क्रिकेट के शीर्ष पर विराट कोहली मौजूद हैं.

चर्चित पत्रिका फोर्ब्स की एशिया के 30 साल से कम उम्र के प्रभावशाली युवाओं की सूची में 56 भारतीयों को शामिल किया है. इनमें भारतीय खेलों के चर्चित चेहरे टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, क्रिकेटर विराट कोहली और बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल शीर्ष स्थानों पर रहे हैं.

फोर्ब्स ने भारत, इंडोनेशिया, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, जापान, पाकिस्तान और वियतनाम जैसे देशों के उन युवाओं की सूची तैयार की है, जो अपने क्षेत्र में बेहद प्रभावशाली दखल रखते हैं तथा महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. इस सूची का नाम 30 अंडर 30 एशिया है. संस्था ने कहा है कि इस समय भारत में क्रिकेट के शीर्ष पर विराट कोहली मौजूद हैं. बीते साल एक करोड़ 13 लाख डॉलर की सर्वाधिक कमाई करने वाले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को बल्लेबाजी का शहजादा बताया है. जिन्होंने अपने नेतृत्व में भारत को जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी–20 श्रृंखला में एक तरफा जीत दिलाई थी. वह 2015 में 1.13 करोड़ डॉलर के साथ भारत के सबसे अधिक कमाई वाले सेलीब्रेटी रहे थे. फोर्ब्स ने कहा कि 16 की उम्र में सानिया ने टेनिस खेलना शुरू किया था. तभी से वह भारत की सबसे सफल टेनिस खेलाड़ी हैं. साथ ही फोर्ब्स ने सायना नेहवाल को इंडियन बैडमिंटन क्वीन और रोल मॉडल बताया है.■

रेसलिंग

खली ने लिया बदला

> खली ने फाइट से पहले विशेष पूजा की थी और कहा था कि मैं विदेशी रेसलरों को पीटकर अपना बदला लूंगा. मैं सिर के बदले सिर फोड़ूंगा और खून के बदले खून निकालूंगा.

भारत के रेसलर द ग्रेट खली एक फाइट के दौरान विदेशी रेसलर्स से फाइट में जख्मी हुए थे. फिर उन्होंने अगली फाइट में अपना बदला पूरा किया. खली ने सिर्फ दो मिनट में कनाडा के रेसलर्स को हरा दिया. इसी के साथ द ग्रेट खली ने रिटर्न्स मेगा शो टाइटल अपने नाम किया.

यह फाइट उत्तराखंड में हुई थी. इससे पहले जख्मी हो जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें फाइट नहीं करने की सलाह दी थी. लेकिन खली ने फाइट से पहले विशेष पूजा की थी और उन्होंने कहा था, कि मैं विदेशी रेसलरों को पीटकर अपना बदला लूंगा. मैं सिर के बदले सिर फोड़ूंगा और खून के बदले खून निकालूंगा. खली ने ब्रॉडी स्टील, मैक्स और अपोलो को

दो मिनट में चित कर दिया. खली ने तीनों को पीट–पीटकर उनकी सारी अकड़ निकाल दी. खली ने तीनों को कुर्सी से भी जमकर पीटा.■

टेनिस

वावरिंका को दुबई ओपन ख़िताब

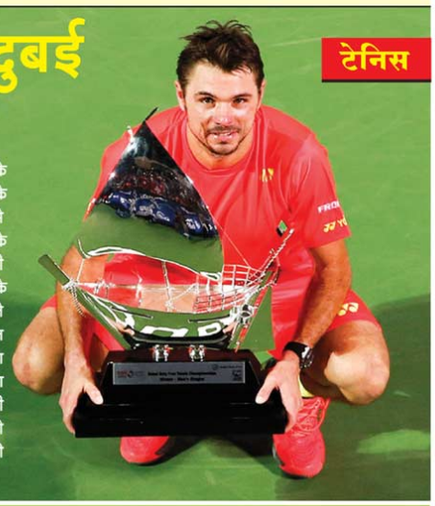

स्विट्ज़रलैंड के स्टेन वावरिंका दुबई ओपन के चैम्पियन बन गए हैं. वावरिंका ने साइप्रस के मार्कोस बघदातिस को 6-4, 7-6 (13) से हराकर ख़िताबी जीत हासिल की. दोनों खिलाड़ियों के बीच मुक़ाबला काफी दिलचस्प रहा था. लेकिन अपनी क्षमता को बरकरार रखते हुए वावरिंका ने टाईब्रेकर होने के बाद बेहतरीन प्रदर्शन कर जीत हासिल की. इससे पहले उन्होंने चेन्नई ओपन का ख़िताब जीता था. अपनी जीत के बाद वावरिंका ने कहा कि यह काफी मुश्किल मैच था और मैं इस साल दुबई चैंपियनशिप को जीतकर काफी खुश हूं. मार्कोस ने एक अच्छा मुक़ाबला खेला और मैं सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. वावरिंका को जीत के साथ टूर्नामेंट की ट्रॉफी और 5,11,750 डॉलर की पुरस्कार राशि दी गई.■

फीफा

जियानी बने नए अध्यक्ष

स्विट्ज़रलैंड के जियानी इनफैंटीनो फुटबॉल की वैश्विक संस्थान फीफा के नए अध्यक्ष बने हैं. इनफैंटीनो को 207 वोटों में से 115 वोट मिले. जिसके दम पर उन्होंने बहरीन के शेख सलमान को अध्यक्ष पद की दौड़ में पीछे छोड़ दिया.

चार महीने से चल रहे इस अभियान में वह हालांकि सबसे आगे रहे, लेकिन शेख सलमान को 88 वोट मिले, जॉर्डन के प्रिंस अली को चार वोट मिले और फ्रांस के जेरोम शैम्पेन को एक भी वोट नहीं मिला. इनफैंटीनो यूरोपीय फुटबॉल की शीर्ष संस्था यूएफा के महासचिव हैं और वह इस जीत के साथ वह फीफा के दूसरे नए अध्यक्ष बन गए हैं.■

मुक्केबाज़ों का रियो ओलंपिक से बाहर रहने का ख़तरा

क्वालीफायर्स के लिए भारतीय आवेदन स्वीकार कर लिया गया है. लेकिन एआईबीए ने नई शर्तें रखी हैं. वह जल्द से जल्द राष्ट्रीय महासंघ चाहते हैं और यदि ऐसा नहीं होता है तो इसे विश्व संस्था को चुनौती के रूप में देखा जाएगा. भारतीय मुक्केबाज़ पिछले साल मई से बिना संघ के हैं. तब बॉक्सिंग इंडिया को निलंबित कर दिया गया था. देश में अभी इस खेल का संचालन एआईबीए की तदर्थ समिति कर रही है.

अभी तक भारत के किसी भी मुक्केबाज ने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई नहीं किया है. लेकिन वह इसमें जगह बना लेते हैं. तब भी यदि अगले महीने के एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर्स तक नए राष्ट्रीय महासंघ का गठन नहीं किया जाता है, तो उन पर इस साल के रियो ओलंपिक खेलों से बाहर रहने का खतरा मंडरा रहा है.

अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ (एआईबीए) ने हाल ही में मैनचेस्टर में विभिन्न आयोगों के साथ बैठक के बाद यह ताजा जानकारी दी. भारतीयों के पास 23 मार्च से चीन के शहर क्विनयान में होने वाले एशियाई क्वालीफायर्स के जरिए ओलंपिक में जगह बनाने का अवसर रहेगा. लेकिन विश्व संस्था भारतीय खिलाड़ियों को अगस्त में रियो डि जनेरियो में होने वाले टूर्नामेंट में भाग लेने से रोकने में नहीं हिचकिचाएगी.

भारत पर अब महासंघ गठित करने का काफी दबाव है. उन्होंने (एआईबीए) ने भारत को एशियाई क्वालीफायर्स तक का समय दिया है. यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर क्वालीफाई करने वाले हमारे मुक्केबाज़ों को ओलंपिक में भाग लेने से रोका जा सकता है. भारतीय खिलाड़ियों की उम्मीदें अब एशियाई क्वालीफायर्स पर टिकी हैं. क्वालीफायर्स के लिए भारतीय आवेदन स्वीकार कर लिया गया है. लेकिन एआईबीए ने नई शर्तें रखी हैं. वह जल्द से जल्द राष्ट्रीय महासंघ चाहते हैं और यदि ऐसा नहीं होता है तो इसे विश्व संस्था को चुनौती के रूप देखा जाएगा. भारतीय मुक्केबाज पिछले साल मई से बिना संघ के है. तब बॉक्सिंग इंडिया को निलंबित कर दिया गया था. देश में अभी इस खेल का संचालन एआईबीए की तदर्थ समिति कर रही हैं.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

क्रिकेट

भारत से डरे हुए हैं स्मिथ

> ऑस्ट्रेलिया टीम को शायद ही किसी विरोधी टीम से डर लगता हो, उनके कप्तान स्टीव स्मिथ भी विपक्षी टीम पर हावी होकर खेलने पर ही विश्वास रखते हैं. लेकिन टीम इंडिया की मौजूदा फॉर्म से उन्हें भी डर लग रहा है. विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम एक बार भी अभी तक टी–20 विश्व कप ट्रॉफी नहीं जीत सकी है और टेस्ट और वनडे प्रारूपों में उम्दा प्रदर्शन करने वाले ऑस्ट्रेलिया को अगले महीने भारत में होने वाले टी–20 विश्व कप में ख़िताब के प्रबल दावेदार के रूप में नहीं देखा जा रहा है.

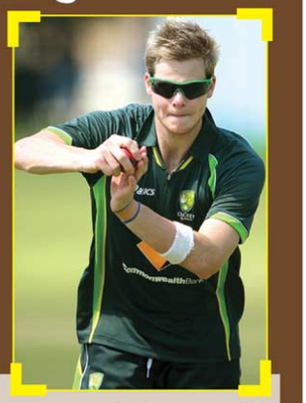

विश्व चैंपियन और टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन टीम ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवन स्मिथ ने कहा है कि आगामी टी–20 विश्व कप में उनकी टीम जीत के इरादे से उतरेगी. लेकिन मेजबान भारत की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है.

ऑस्ट्रेलियाई टीम को शायद ही किसी विरोधी टीम से डर लगता हो, उनके कप्तान स्टीव स्मिथ भी विपक्षी टीम पर हावी होकर खेलने पर ही विश्वास रखते हैं. लेकिन टीम इंडिया की मौजूदा फॉर्म से उन्हें भी डर लग रहा है. विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम एक बार भी अभी तक टी–20 विश्व कप ट्रॉफी नहीं जीत सकी है और टेस्ट और वनडे प्रारूपों में अच्छा प्रदर्शन करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को अगले महीने भारत में होने वाले टी–20 विश्व कप में खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में नहीं देखा जा रहा है.

स्मिथ ने कहा कि टी–20 क्रिकेट में किसी कोई एक क्रिकेटर भी आपसे मैच छीन सकता है और परिणाम बदल सकता है. कोई भी टीम ख़तरनाक साबित हो सकती है. मुझे लगता है कि मेजबान टीम इंडिया को भारतीय परिस्थितियों में हराना काफी मुश्किल होगा. वह एक शानदार टीम है. भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 3 टी–20 मैचों की सीरीज में 3–0 से हराया था और इस लिहाज से भी वह एक मजबूत टीम नजर आ रही है. ऑस्ट्रेलिया ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साल 2010 में किया था और वह टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहा था.

स्मिथ ने कहा कि टी–20 विश्व कप की ट्रॉफी ऐसी है जो हमसे अभी तक दूर रही है. भारत का दौरा जरूर कठिन होगा. वहां की परिस्थितियां हमारे लिए विदेश जैसी होंगी. लेकिन हमारे पास ऐसी टीम है जो बड़ा कमाल जरूर करेगी. आरोन फिंच की फिटनेस समस्याओं के चलते ऑस्ट्रेलिया की टी–20 टीम की कप्तानी स्टीवन स्मिथ को सौंपी गई है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन अंतरराष्ट्रीय टी–20 मैचों की सीरीज के लिए रवाना होने से पहले स्मिथ ने कहा कि फिलहाल मुझे नहीं पता कि शीर्ष 3 या 4 नंबर पर कौन बल्लेबाजी करेगा. हमारे पास विश्व कप से पहले 3 मैच हैं और उसी में प्रदर्शन के आधार पर हम फैसले लेंगे. स्मिथ ने कहा कि टीम प्रबंधन को टीम के चयन पर फैसला करना है.■

फ्लैशबैक
नूतन

जब टूट गया था दिल

आसिफ साहब ने अनारकली में नूतन के लिए छह गीत भी तैयार करवा लिए थे. इस फिल्म में बतौर हीरो दिलीप कुमार का नाम तय हुआ, तो लगा कि नूतन की चाहत इस बार पूरी होकर ही रहेगी. इससे पहले कि फिल्म की शूटिंग शुरू होती नूतन ने अनारकली का किरदार निभाने से मना कर दिया. यह इंकार आसिफ साहब की समझ से परे था. तमाम कोशिशों के बावजूद नूतन नहीं मानीं.

कहते हैं जहां चाह, वहां राह, लेकिन किसी-किसी की चाह के लिए राह बनते-बनते रह जाती है. ऐसी ही चाहत थी मशहूर अभिनेत्री नूतन की, जो अधूरी ही रह गई. नूतन दिलीप कुमार के साथ काम करना चाहती थीं. इसके लिए बस एक ऐसे निर्माता की ज़रूरत थी, जो दिलीप कुमार के साथ नूतन की जोड़ी बना दे. ये जरूरत निर्माता अनिल विश्वास ने पूरी कर दी. फिल्म का नाम रखा गया *शिकवा*. विश्वास *शिकवा* के साथ-साथ *शिकस्त* के नाम से एक और फिल्म बना रहे थे, जिसमें हीरोइन ली गई नूतन की दूर के रिश्ते की बहन नलिनी जयवंत. नूतन के लिए दो गीत भी लता की आवाज़ में रिकॉर्ड कर लिए गए थे. अब इसे समय का फेर कह लीजिए कि फिल्म *शिकस्त* तो बन गई और *शिकवा* बीच में ही अटक गई. नतीजा, *फिल्म शिकवा* के अटक जाने से नूतन का दिल टूट गया और उनकी चाहत पूरी होते-होते रह गई.

भारतीय सिनेमा के इतिहास का सुनहरा पन्ना! आज की पीढ़ी ही नहीं, उस दौर के दर्शक भी मधुबाला और दिलीप कुमार को मुगल-ए-आज़म से जुदा करके नहीं देख पाएंगे. फिल्म ही नहीं उसकेगाने, प्यार किया तो डरना क्या, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए की यादें भी सदाबहार हैं.

आगे चलकर समय ने फिर पलटी मारी. के. आसिफ अनारकली फिल्म बना रहे थे, जिसके लिए उन्होंने नूतन का नाम पहले ही फाइनल कर रखा था. आसिफ साहब ने अनारकली में नूतन के लिए छह गीत भी तैयार करवा लिए थे. इस फिल्म में बतौर हीरो दिलीप कुमार का नाम तय हुआ, तो लगा कि नूतन की चाहत इस बार पूरी होकर ही रहेगी. इससे पहले कि फिल्म की शूटिंग शुरू होती नूतन ने अनारकली का किरदार निभाने से मना कर दिया. यह इंकार आसिफ साहब की समझ से परे था. तमाम कोशिशों के बावजूद नूतन नहीं मानीं. मजबूरन के. आसिफ ने मधुबाला को अनारकली का रोल दे दिया, साथ ही फिल्म का नाम बदलकर मुगल-ए-आज़म कर दिया.

भारतीय सिनेमा के इतिहास का सुनहरा पन्ना! आज की पीढ़ी ही नहीं, उस दौर के दर्शक भी मधुबाला और दिलीप कुमार को मुगल-ए-आज़म से जुदा करके नहीं देख पाएंगे. फिल्म ही नहीं उसके गाने, प्यार किया तो डरना क्या, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए और मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे की यादें भी सदाबहार हैं.

अब सोचने वाली बात यह है कि अनारकली के रूप में सबसे पहली पसंद नूतन थीं और वह खुद भी दिलीप कुमार के साथ काम करना चाहती थीं, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि नूतन ने अपने चहेते हीरो की अनारकली बनने से इंकार कर दिया. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

रणवीर के साथ काम नहीं करना चाहतीं दीपिका !

फिल्म की डेट्स के लिए भंसाली ने रणवीर के बाद दीपिका से बात की. दीपिका ने उन्हें फिल्म के लिए मना नहीं किया, लेकिन हां भी नहीं कहा. बस मुस्करा कर बात बीच में छोड़ दी. हॉलीवुड एक्शन स्टार विन डीजल की फिल्म के बाद दीपिका के ब्रैड पिट के साथ भी फिल्म करने की चर्चा है.

रणवीर सिंह के शादी के प्रस्ताव को दीपिका ने पहले ही ठुकरा दिया था. अब संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म साइन करने को लेकर दीपिका ने बात बीच में लटका रखी है. बताया जा रहा है कि इस प्रेमी-जोड़े का रिश्ता पहले जितना अच्छा नहीं है. पेशेवर मोर्चे पर यह साफ देखा जा सकता है. दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह मीडिया के सामने गुड फ्रेंडशिप का टैग लेकर घूमते हैं. लेकिन लोगों का कहना है कि इनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं है.

रामलीला और बाजीराव मस्तानी के बाद इस जोड़ी को लेकर संजय लीला भंसाली ने एक और फिल्म प्लान की है. रणवीर सिंह ने हां करके 2017 में दीपावली के बाद की तारीख देने की बात कही है. इसके पहले की डेट्स वे आदित्य चोपड़ा और रोहित शेट्टी की फिल्मों को दे चुके हैं.

रणवीर के बाद भंसाली ने दीपिका से बात की. यहां पर कहानी में नया मोड़ आया. दीपिका ने उन्हें फिल्म के लिए मना तो नहीं किया, लेकिन हां भी नहीं कहा. बस मुस्करा कर बात बीच में छोड़ दीं. हॉलीवुड एक्शन स्टार विन डीजल की फिल्म के बाद दीपिका के ब्रैड पिट के साथ भी फिल्म करने की चर्चा है. ऐसा होता है तो भंसाली की फिल्म और रणवीर को पीछे छोड़ते हुए दीपिका हॉलीवुड की सक्सेस राइड पर निकल जाएंगी. करियर एम्बिशन के चलते दीपिका ने रणवीर का शादी का प्रपोजल भी ठुकरा दिया. सवाल यह भी है कि क्या रणवीर को पता नहीं था कि दीपिका हॉलीवुड प्रोजेक्ट करने वाली हैं? या वो नहीं चाहते थे कि दीपिका उन्हें छोड़ कर हॉलीवुड जाएं, इसीलिए शादी का प्रपोजल दिया. जो भी हो दीपिका ने स्मार्ट तरीके से इंकार कर दिया.

दीपिका पादुकोण इन दिनों टोरंटो में अपनी हॉलीवुड फिल्म *ट्रिपल एक्स द रिटर्न ऑफ एक्सजेंडर केज* की शूटिंग में व्यस्त हैं. फिल्म में उनके अपोजिट हॉलीवुड स्टार विन डीजल हैं. खबरों की मानें तो इस फिल्म के बाद उनकी अगली हॉलीवुड फिल्म ब्रैड पिट के साथ होगी. दीपिका ने इस फिल्म के लिए हामी भी भर दी है.■

जय गंगाजल में नारी शक्ति को दर्शाकर

गौरवान्वित हूं : प्रियंका

आज के समय में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं. वे अपने क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के निशान छोड़ रही हैं. मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि मुझको फिल्म *जय गंगाजल* में काम करने का अवसर मिला.

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा फिल्म जय गंगाजल में पुलिस अधिकारी आभा माथुर की भूमिका में नजर आईं. उनका कहना है कि वह अपने किरदार के जरिए नारी शक्ति को प्रदर्शित करके काफी गौरव महसूस कर रही हैं. प्रियंका ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया. वीडियो साझा करने के साथ प्रियंका ने सलाम करते हुए कहा कि फिल्म में नारी शक्ति को प्रदर्शित करने का अवसर पाकर गौरवान्वित हूं. उन्होंने कहा कि आज के समय में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं. वे अपने क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के निशान छोड़ रही हैं. मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि फिल्म *जय गंगाजल* में काम करने का अवसर मुझको मिला. प्रकाश झा द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म *जय गंगाजल* चार मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. ■

इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक प्रकाश झा ने भी जय गंगाजल में एक्टिंग की है. इसमें प्रकाश ने एक पुलिसवाले का किरदार निभाया है जिसमें वह प्रियंका के एक साथी हैं. प्रकाश झा का कहना है कि 2003 का जो समाज था और जो 2016 का भारत का समाज है. उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है. 2003 में जब हम कहते थे कि समाज को पुलिस ऐसी ही मिलती है, जैसा कि समाज होता है. आज का पुलिस वाला घबराता है कि एक्शन लें कि नहीं लें. ■

ऑस्कर

लियोनार्डो बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता

अमेरिका के लॉस एंजलिस में 88वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार लियोनार्डो डिकैप्रियो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिल ही गया. लियोनार्डो को यह पुरस्कार फिल्म द रेवेनेंट के लिए मिला है. इससे पहले भी वह ऑस्कर के लिए चार बार नामांकित हो चुके थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी. लियोनार्डो ने द रेवेनेंट फिल्म में अपनी भूमिका के लिए खूब तारीफें बटोरी थीं. सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार द रेवेनेंट के निर्देशक एलेजांद्रो जी इनारितु को मिला है. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री

बनी हैं ब्री लार्सन जिन्हें फिल्म *रूम* में अदाकारी के लिए यह पुरस्कार मिला है. सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार स्पॉटलाइट को मिला. सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर का पुरस्कार एमी को दिया गया है. एमी का निर्देशन भारतीय मूल के फिल्म निर्देशक आसिफ कपाड़िया ने किया है.

द डैनिश गर्ल फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार अलीसिया विकांडर को दिया गया. ब्रिज ऑफ स्पाइज के लिए मार्क रायलैंस को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया. बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट पुरस्कार *द गर्ल इन द रिवर : द प्राइस ऑफ फॉरगिवनेस* को मिला है. पाकिस्तान की शरमीन उबैद चिनॉय को दूसरा ऑस्कर पुरस्कार पाक में ऑनर किलिंग पर आधारित इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दिया गया है.

हंगरी की फिल्म *सन ऑफ सॉल* को विदेशी भाषा की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार मिला है. ऑस्कर में इस बार सबसे ज्यादा फिल्म *द रेवेनेंट* पर सबकी निगाहें रहीं, जिसे 12 श्रेणियों में नामांकित किया गया था. इस फिल्म को बेहतरीन सिनेमैटोग्राफी का भी पुरस्कार मिला है.

वहीं ऑस्ट्रेलियाई निर्देशक जॉर्ज मिलर की फिल्म *मैड मैक्स : फ्यूरी रोड* को 10 श्रेणियों में नामांकित किया गया. इस फिल्म को बेस्ट फिल्म एडिटिंग का पुरस्कार मिला है. दोनों फिल्मों के अलावा *द बिग शॉर्ट, ब्रिज ऑफ स्पाइज़, ब्रुकलिन, द मार्शियन और रूम एंड स्पॉटलाइट* को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकित किया गया था. बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भी ऑस्कर अवॉर्ड देने के लिए समारोह में शामिल हुईं. ऑस्कर पुरस्कार समारोह में प्रियंका के साथ क्विंसी जोंस, रीस विदपर्सन, स्टील कैरेल, जेकेसिमांस और जार्द लेटो जैसे कलाकार भी शामिल थे.■